

# हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1997

खण्ड-1, अंक-8

अधिकृत विवरण

विशत सूची

शुक्रवार, 14 मार्च, 1997

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वाक-आउट	(8)16
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(8)17
नियम-45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(8)19

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)33
अभिकथित विशेषाधिकार का प्रश्न	(8)36
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)38
बैठक का समय बढ़ाना	(8)71
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)71
बैठक का समय बढ़ाना	(8)76
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)77
बैठक का समय बढ़ाना	(8)80
वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा	(8)80

## हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 14 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो. छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

### तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, अब सवाल होंगे।

#### **Upgradation of Govt. High School, Mahara**

**\*200. Sh. Devi Raj Diwan:** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government High School, Mahara, District Sonapat into 10+2 system school, and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): वर्तमान में विद्यालय का स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवराज दीवान: स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि माहरा गांव मेरे हल्के का एक बहुत बड़ा गांव है। इसी के साथ-साथ एक और जुआं गांव है और

इनमें दो पंचायतें हैं। कई सालों से इस स्कूल का दर्जा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और मैंने पहले कई बार इसके बारे में लिखा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे मेरे सवाल का जवाब न के बजाए हां में बदल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

**श्री राम बिलास शर्मा:** स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा हमारे साथी देवराज दीवान जी को बताना चाहूंगा कि यह ठीक है कि माहरा गांव सोनीपत जिले का एक बड़ा गांव है और इसमें 9 हजार की आबादी है लेकिन माहरा गांव के इस विद्यालय में कुछ तो भवन की कमी है परन्तु हमने फिर भी इसका अच्छी तरह से सर्वेक्षण करवाया है। स्पीकर सर, अगले वित्तीय वर्ष में हम इस विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे।

**श्री कृष्ण लाल:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो विद्यालय इस समय अपग्रेड होने की कंडीशन फुलफिल करते हैं क्या उनका दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? मेरे हल्के के मतलौडा गांव में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। यह स्कूल अपग्रेड करने की सारी कंडीशनज फुलफिल करता है। क्या इसको अपग्रेड करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है?

**श्री राम बिलास शर्मा:** स्पीकर सर, मेरे भाई कृष्ण लाल जी ने ठीक ही कहा कि मतलौडा इनके क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। सर, हमने पूरे हरियाणा में इस बारे में सर्वेक्षण करवाया है और

जहां-जहां पर जिन-जिन विद्यालयों के छात्रों की संख्या उपयुक्त है, भवन उपयुक्त है या खेल का मैदान है और अगर वे अपग्रेड होने के सौर नोर्म्ज पूरे करते हैं तो हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनैतिक कारण से, उनको अपग्रेड करेंगे। शिक्षा विभाग ने पूरे हरियाणा में इस तरह का सर्वेक्षण किया है।

**श्री दिलूराम:** अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में दो कस्बे बहुत बड़े हैं। एक तो सीवन है जहां पर हाई स्कूल है और यह हाई स्कूल अपग्रेड करने के लिए सारे नोर्म्ज भी पूरे करता है। इस स्कूल में 22 कमरे हैं और यह पूरे का पूरा बना हुआ भी है। इसी तरह से एक भागल गांव है यह बहुत बड़ा गांव है और वहां पर एक हाई स्कूल है इसमें भी 25 कमरे हैं। मैं मंत्री जी से आपके द्वारा यह आश्वासन चाहूंगा तथा यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इन स्कूलों को प्लस टू करवाने की कोशिश करेंगे?

**श्री राम बिलास शर्मा:** स्पीकर सर, चौ. दिलूराम बाजीगर को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। (विघ्न) बाजीगर इनकी सब कास्ट है। इसमें क्या दिक्कत है। ये हमारे साथ पहले भी विधायक रहे हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** मनीराम जी, आप बहुत ही पुराने मैम्बर हैं इसलिए आपको बीच-बीच में बोलने की आदत शोभा नहीं देती। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस तरह से बीच में न बोलें।

**श्री राम बिलास शर्मा:** स्पीकर सर, मैं दिलूराम जी को बताना चाहूंगा। उन्होंने ठीक ही कहा कि सीवन गांव गुहला चीका चुनाव क्षेत्र का एक बड़ा गांव है और वहां पर एक गर्ल्स स्कूल चलता है और उसमें छात्रों की संख्या भी काफी है तथा भवन भी पूरा है। सर, मैंने इस आगस्ट हाउस में कई बार निवेदन किया है कि हमने पूरे हरियाणा में इस तरह का एक सर्वेक्षण करवाया है और करा रहे हैं। जहां-जहां पर भी नोम्ज्र पूरे होंगे वहां-वहां पर स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। सर, शिक्षा विभाग आपकी रहनुमाई में कितना अच्छा चल रहा है यह आप जानते ही हैं। हमने स्कूलों में वन्दे मातरम प्रारंभ किया और मीड डे मीलज की स्कीम भी हमने चालू की है। पहले ग्यारह अध्यापकों को सम्मानित किया जाता था इस बार हमने सब्जैक्टवाइज स्टेट अवार्ड देने की बात की है और खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनकी शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए हम विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। सीवन गांव का सर्वेक्षण हमने इसीलिए करवाया है।

**श्री मनीराम:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे मंडी डबवाली के गोरीवाला में 10वीं जमा का स्कूल है और वह सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल बनाये जाने के सभी नार्म्ज्र पूरे करता है, क्या उसको अपग्रेड करने का कोई विचार है?

श्री राम बिलास शर्मा: चौ. मनी राम जी ने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था लेकिन वह लगा नहीं। इस सवाल में जिन चार गांवों के बारे में इन्होंने पूछा था उन चारों गांवों का सर्वेक्षण करवाया है। जो भी गांव नामर्ज पूरा करेगा हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मनी राम जी आप कितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?

श्री मनीराम: सर, मैंने जिस हाई स्कूल का जिक्र किया है वह सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाए जाने के नामर्ज पूरे करता है क्या उसे सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाने जा रहे हैं।

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि जो-जो स्कूल नामर्ज पूरे कर रहे हैं उन पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मनी राम जी, आपने और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर आप बीच में न बोलना।

### **Repair of Damaged Roads**

**\*209. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state –

(a) whether it is a fact the following roads were damaged due to flood during the year 1996-97:

(i) Link road to village Khaliyawas;

(ii) Link road to village Malehera (via Khatawal, Dakiya);

(iii) Link road to Jeetpura & Rojka;

(iv) Link road Assadpur (Via Turkiawas, Tatarrpur Istemurar and Meerpur);

(v) Link road to Kakoria, Bhuthal Jat;

(vi) Link road to Gurkawas, Khokhi;

(vii) Link road to village Khijuri (via Mundiokhera);

(viii) Link road to Sangwari (via Bhudhla, Konsiwas);

(ix) Link road to Janti Jant;

(x) Link road to Kishangarh (via Ghasera); and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads as referred to in part (a) above together with the time by which these roads are likely to be repaired?

**Public Works Minister** (Sh. Dharamvir Yadav):

(a) Yes, Sir.

(b) Essential repairs like filling of cuts and patch work have been done. Balance work of repair will be completed by 30.4.1997, subject to availability of funds.

**कैप्टन अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, चौधरी धर्मवीर जी बड़े विद्वान साथी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं लेकिन जो



इन्होंने बात कही है कि इन सड़कों की दरारें भर गई हैं और उन पर पेच वर्क भी कर दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप एक कमेटी बना दें और वह कमेटी जाकर देखे अगर एक भी पैसा वहां लगा हो तो वह कमेटी आपको बना देगी? जो मैंने नाम दे रखे हैं उन पर कितना पैसा लगाया गया है यह मैं जानना चाहता हूं। मैं इस बारे में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कम से कम सही जवाब तो दें।

**श्री अध्यक्ष:** कैप्टन अजय सिंह जी मेरे भी पड़ौसी हैं और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है। मुझे भी उन सड़कों से होकर जाना पड़ता है, कृपया यह बताएं कि वे सड़कें कितने समय से टूटी पड़ी हैं?

**कैप्टल अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मसानी बैराज पर शटर नहीं लगे और जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी उससे तमाम सड़कें टूट गई थीं ये सड़कें बाढ़ अपने के बाद टूटी थीं उससे पहले बहुत अच्छी थीं।

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, बाढ़ हमारे समय में नहीं आई, इन्हीं के टाइम में आई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में वहां काम न के बराबर हुआ है। जब कैप्टन अजय सिंह खुद वजारत में वजीर थे उस समय भी का नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों की रिपेयर के लिए कुछ ऐस्टीमेटस बनाए गए हैं, इन पर 18 लाख रूपया खर्च होना है

जिसमें से 3 लाख रूपया खर्च हो चुका है। बाकी पैसा जैसे-जैसे फंडज आएंगे, खर्च किया जाएगा। इन सड़कों की केवल प्री मिक्स कार्पेटिंग रहती है।

**श्री भागीराम:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जब भी अलग-अलग सड़कों की मुरम्मत की बात की जाती है तो कहते हैं कि मुरम्मत न कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक ही बात कह देते हैं कि जब फंडज अवेलेबल होंगे तब मुरम्मत की जायेगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये फंडज कब तक उपलब्ध होंगे?

**श्री अध्यक्ष:** भागीराम जी, नो डिस्कशन, आपने अपना सवाल पूछ लिया।

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों की हालत ज्यादा खराब थी उन पर काम चल रहा है और जिन बाकी सड़कों को ठीक करना है उनको भी फंडज आने पर ठीक कर दिय जायेगा।

**कैप्टल अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से सवाल पूछा है कि जिन सड़कों पर पैच वर्क और मुरम्मत का काम किया है उनमें से खासतौर पर जांटी, असादपुर और खलियावास गांवों कि सड़कों की मुरम्मत के लिए कितना पैसा लगाया है?

**श्री धर्मवीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, खलियावास गांव की सड़क पर 1.26 लाख रूपये का एस्टिमेट बना है जिसमें से 70

हजार रूपये खर्च हो चुके हैं। दूसरा असादपुर वाली सड़क पर साढ़े छः लाख रूपया खर्च होना है जिसमें से 1.84 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं और जांटी गांव की सड़क पर अढ़ाई लाख रूपये खर्च होने हैं जिनमें से दस हजार रूपये खर्च हो चुके हैं।

**कैप्टल अजय सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है।

### **Repair of Roads of Bahadurgarh Sub-Division**

**\*251. Sh. Nafe Singh Rathee:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of Sub-Division Bhadurgarh, District Rohtak:-

1. Bhadurgarh to Khurampur via Sohati;
2. Bhadurgarh to Tandaheri, Maudohathi and Rohad;
3. Bhadurgarh to Barauna; and
4. Nuna-Majra to Mahendipur, Daboda etc.

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired?

**Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav):**

(a) Yes, Sir.

(b) Roads have been repaired by heavy patch work. These will further be improved by premix carpet/strengthening/raising wherever necessary by 30.6.97 depending upon availability of funds.

**श्री नफे सिंह राठी:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हैवी पैच वर्क करने की बात कही है लेकिन इन सड़कों पर कोई काम नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह हैवी पैच वर्क और रिपेयर का काम कब तक पूरा हो जायेगा?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, पैच वर्क का काम हो गया है और कापेटिंग का काम होना है। फंडज आने पर यह काम भी 30 जून तक पूरा कर दिया जायेगा।

**श्री जसविन्द्र सिंह संधु:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि श्री दिलूराम जी के हल्के के गांव भूसला से मेरे हल्के के गांव अदोहा तक की सड़क सन् 1993 से टुटी हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इसको प्रियोरिटी के आधार पर बनाने की कृपा करेंगे।

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नूँ मैं इस दियां कि जेहडी बी सड़कें इन्हा दे हल्के विच खराब पर्ईयां हन उन्हां दी प्रियोरिटी दे आधार ते मरम्मत करवांगे।

**श्री नफे सिंह राठी:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के गांव से वाया झाड़सा होकर के एक सड़क जा रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन मंत्री जी ने इसकी रिपेयर करने की बजाए

नैशनल हाईवे नं. 8 से अपना नया रोड़ निकलवा लिया क्या यह बात सच है?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात असत्य है तथा झाड़सा होते हुए कनई को जो रोड़ जा रही है, उसके उपर काम शुरू कर दिया गया है।

**श्री दिलू राम:** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में हर साल फल्ड से पानी आ जाता है क्योंकि घग्घर नदी, टांगरी नदी और मारकंडा, अबाला, रोपड तथा हिमाचल प्रदेश का सारा का सारा पानी वहां आता है। वहां पर सड़कों की इतनी दुर्दशा है कि उन पर चलने में बहुत समस्याएं आती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कमेटी बनाकर एक बार वहां पर स्थिति का जायजा ले लें। मेरा निवेदन है कि और काम तो बाद में होता रहेगा, कम से कम पैच-वर्क तो करवाने की कृपा करें, मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी।

**श्री धर्मवीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग और यह सरकार वचनबद्ध है कि जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं, चाहे वे किसी भी विधान सभा क्षेत्र की हों, हम उनकी मुरम्मत करवाएंगे।

### **Construction of Fire Station, Julana**

**\*236. Sh. Sat Narain Lather:** Will the Minister for Local Governmet be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct

a Fire Sation at Julana, district Jind; if so, the details thereof?

**स्थानीय शासन मंत्री (डा. कमला वर्मा):** इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**श्री सत नारायण लाठर:** अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की लाखों रूपए की गाड़ियां हैं, उनको लंग लग रहा है।

**श्री अध्यक्ष:** आप सवाल पूछिए।

**श्री सत नारायण लाठर:** अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। वहां पर जमीन है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर दमकल केन्द्र बनाया जाए इससे सरकार को काफी फायदा होगा। वैसे मेरे हल्के को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह सरकार की भलाई की बात है। मैं मानता हूं कि श्री धर्मवीर जी के महकमे के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन कर्ण सिंह दलाल साहब के विभाग के पास तो पैसा है क्या ये उससे दमकल स्टेशन बनाने की कृपा करेंगे?

**डा. कमला वर्मा:** मैं कर्ण सिंह दलाल जी से प्रार्थना करूंगी कि वहां पर एक दमकल केन्द्र संस्थान बनाया जाए।

**कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लाठर साहब को बताना चाहता हूं कि इस बारे में वे विभाग को लिखकर के दे दें। उनकी मांग अगर जायज होगी तो उस पर हम विचार करेंगे।

श्री सत नारायण लाठर: ठीक है सर, मैं लिखकर इनको दे दूंगा।

### **Repair of Roads**

**\*227. Sh. Krishan Lal:** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of Assandh Constituency:-

(i) Gagsina to Padha via Echla (Karnal);

(ii) Salwan (Karnal) to village Khandra (Panipat);

(iii) Munak to Shekhupura Khalsa via Khora-Kheri (Karnal);

(iv) Assandh to dera Gujrakhian (Karnal); and

(v) Kurlan to Balla via Maanpura; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired?

**Public Works Minister** (Sh. Dharamvir Yadav):

(a) Yes, Sir.

(b) Essential repair like filling of cuts, Patch Work has been done. Balance work of repair will be completed by 30.4.1997, subject to availability of funds.

**श्री कृष्ण लाल:** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मैंने जिन रोड़ज का जिक्र किया है जैसे कि गगसीना से पाढा वाया ऐचला (करनाल), सालवन (करनाल) से गांव खण्डरा (पानीपत), मुनक से शेखुपुरा खालसा वाया खोरा-खेड़ी (करनाल) असंध से डेरा गिजराखियां (करनाल) तथा कुरलन स बल्ला वाया मानपुरा इन पर खड्डे भरने का यानि कि पैच-वर्क के कार्य पर कितना खर्च होना था और अब तक कितना खर्च हो चुका है? क्योंकि मंत्री जी ने बताया है कि पैच-वर्क का काम कर दिया गया है।

**Sh. Dharamvir Yadav:** Sir, the expenditure to be incurred on the first road is Rs. 3.79 lakhs. On second road, it is Rs. 2.99 lakhs. On third road, it is Rs. 3.12 lakhs. On fourth road, it is Rs. 0.50 lakh and on fifth road, it is Rs. 2.44 lakhs.

**श्री कृष्ण लाल:** स्पीकर सर, मंत्री जी ने आंकड़ों के साथ दर्शाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सालवन से खण्डरा रोड़, जिसका कि मैंने जिक्र किया है, उसके बीच में एक मोर माजरा गांव भी आता है। वहां पर इतनी बुरी हालत है कि बसों वगैरह को भी खेतों में से ले जाना पड़ता है और सवारियां को परेशानियां उठाना पड़ती हैं। क्या मंत्री जी ने इस बारे में कोई एक्शन लिय है?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, उसका पैच-वर्क कर दिया गया है।



## **Shortage of Doctors in Civil Hospital, Bhiwani**

**\*222. Sh. Satpal Sangwan:** Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of Doctors in Civil Hospitals and Community Health Centres in distirct Bhiwani, and

(b) if so, the time by which the aforesaid shortage of Doctors is met out?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन):**

(क) नहीं श्रीमान जी, जिला में केवल कुछ ही पद खाली हैं।

(ख) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 205 पदों के लिए चुनाव किया है। डॉक्टरों की नियुक्ति जल्दी की जा रही है।

**श्री सतपाल सांगवान:** अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी मैं न डैंटल सर्जन है, न आई सर्जन है और न कोई दूसरा सर्जन है। वहां पर डॉक्टर्ज की भी बहुत कमी है। खास करके मेरे हल्के में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर डाक्टर नहीं है अगर डाक्टर हैं तो वे आते नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भिवावनी डिस्ट्रिक्ट में डाक्टर्ज की कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं और इस समय वहां पर कितने डाक्टर हैं?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सांगवान साहब ने भिवानी जिले में डॉक्टरों की पोजिशन पूछी है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि भिवानी जिले में 68 पोस्टें डॉक्टरों की सैक्शंड हैं। उनमें से 54 पोस्टों पर डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है और 14 पोस्टें खाली हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम 205 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। डॉक्टरों की इस भर्ती में से वहां पर जो 14 पोस्टें खाली हैं उनको भी भर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चरखी दादरी में डॉक्टरों की 35 पोस्टें सैक्शंड हैं जिनमें से 25 पोस्टों पर डॉक्टर लगे हुए हैं और 10 पोस्टें खाली हैं।

**श्री कैलाश चन्द्र शर्मा:** माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नारनौल में एक बहुत अच्छी लेडी डाक्टर बी.डी. गुप्ता थी। जिनकी वजह से वहां का सिविल होस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन वहां पर जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले हैं उन्होंने उनकी वहां से बदली करा दी है। डा.बी.डी. गुप्ता का बिना वजह रिवाड़ी 60 दिन के लिए deputation कर दिया है उसको वापिस नारनौल लाया जाये और deputation रद्द किया जाए।

**Mr. Speaker:** Please ask question.

**श्री कैलाश चन्द्र शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, उनका परसों रिवाड़ी डैपुटेशन कर दिया गया है। पता नहीं डायरेक्टर हैल्थ सर्विसिज को कहां से सूचना मिली उन्होंने उनको रिवाड़ी डैपुटेशन कर दिया। मैंने सरकार से प्रार्थना भी की थी कि उस

लेडी डॉक्टर और डॉक्टर गुप्ता को वहीं पर रहने दिया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस लेडी डाक्टर का डैपुटेशन कैंसिल करके उसको वहीं नारनौल में रहने दिया जाएगा।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात कल मेरे नोटिस में लाई थी और इन्होंने मुझे जो नोट दिया था वह मैंने सरकार के पास भेज दिया है। डा. बी. डी. गुप्ता और श्रीमती बी.डी. गुप्ता के वहां रहने से कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम वालों को तकलीफ थी और उन्होंने उस लेडी डॉक्टर को और डा. बी.डी. गुप्ता को वहां से बदलने की योजना बनाई थी। माननीय सदस्य ने जो नोट मुझे लिखकर दिया था वह मेरी तरफ से ऊपर जा भी चुका है। उम्मीद है कि वे लेडी डॉक्टर नारनौल में ही रहेगी।

**श्री राम भजन अग्रवाल:** अध्यक्ष महोदय, भिवानी के अन्दर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी एक रेंटिड बिल्डिंग में चल रही है और उस बिल्डिंग का सरकार को हर महीने का 8 हजार रूपए रेंट देना पड़ता है। भिवानी सिविल होस्पिटल में कमरे खाली पड़े हैं इसलिए क्यों न उस डिस्पेंसरी को सिविल होस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि लोगों को एक ही जगह पर इलाज हो सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस डिस्पेंसरी को सिविल होस्पिटल की बिल्डिंग में जो कमरे खाली पड़े हैं उनके अन्दर शिफ्ट किया जाएगा? इसके साथ-साथ मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना

चाहता हूँ कि भिवानी के अन्दर करीब 10 हजार मजदूर काम करते हैं वहां पर एक ई.एस.आई. होस्पिटल की बिल्डिंग निर्माणाधीन है उसका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह ठीक किया है कि हम 8 हजार रूपया प्राईवेट बिल्डिंग का उस किराये के रूप में दे रहे हैं। जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस पर हम अमल करने जा रहे हैं यानि इसकी सिविल हस्पताल में ही शिफ्ट करने जा रहे हैं। जहां तक ई.एस.आई. हस्पताल की बात है उसको भी जल्दी कम्प्लीट करने जा रहे हैं और ई.एस.आई. हस्पताल को भी नई बिल्डिंग में जल्दी ही शिफ्ट करने जा रहे हैं।

**स्थानीय शासन मंत्री (डा. कमला वर्मा):** अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने यह सवाल उठा कर अच्छा किया है क्योंकि जिस जगह पर अब यह बिल्डिंग (आयुर्वेदिक की है) है, वह वैसे भी ठीक नहीं है, वहां पर काफी जाले आदि भी लगे हुए हैं और मरीजों को पौड़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है जिससे उनको परेशानी होती है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी ही वहां से शिफ्ट कर देंगे, यह एक अच्छी बात होगी।

**श्री अध्यक्ष:** बहन जी हम तो इसके लिए पिछले पांच साल से कहते आ रहे थे लेकिन उस वक्त हमीर बात नहीं सुनी

गई। अब खुशी की बात है कि इस सरकार ने हमारी बात को मान लिया है।

**श्री सतनारायण लाठर:** ग्रामीण क्षेत्रों में पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. में लेडीज डॉक्टरों की काफी कमी है और खासकर मेरे हल्के जुलाना में तो पिछले 2 साल से लेडी डॉक्टर कोई है ही नहीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन खाली पड़ी पोस्टों को कब तक भर दिया जायेगा?

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. में काफी जगहों पर स्टाफ की कमी है। पी.एच.सीज. में अभी 62 डाक्टरज की कमी है, जिनको अभी तक हम लगा नहीं पाये हैं। अब हम 205 नये डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं और इस भर्ती में पी.एच.सीज. और सी.एच.सीज. में भी डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे।

**श्री जगदीश नैयर:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी ने नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने मेरी कांस्टिच्यूएन्सी की जो सी.एच.सी. है उसका सारा सामान उठा कर कहीं और भिजवा दिया था। मैं मंत्री जी ने जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सी.एच.सी. का सारा सामान हमारी सरकार वापस दिलवाने का कष्ट करेगी।

**श्री ओम प्रकाश महाजन:** अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के बारे में तो मुझे पता नहीं कि क्या किया या क्या नहीं

किया हां मैं अपने सदस्य साथी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। अगर वहां से कोई सामान उठाया गया होगा तो वापस दिलवा दिया जायेगा।

### **Construction of New Road**

**\*260. Sh. Balwant Singh:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Sunariyakalan to Mayana in Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the said road it likely to be constructed?

**लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह):**

(क) नहीं श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) को सम्मुख रखते हुए उक्त सड़क के निर्माण बारे कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती।

**श्री बलवंत सिंह:** स्पीकर साहब, मुझे यह सड़क न बनाये जाने के बारे में दुबारा से लिखित रूप से मिल रहा है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हरेक गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है। मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सुनारिया से मायना गांव आपस में मिले हुए नहीं हैं। सुनारिया जब जाना होता है तो रोहतक होकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार

से जब किसानों को शूगर मिल जाना होता है तो भी उन्हें वाया रोहतक ही जाना पड़ता है। जिस कारण 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। यदि वे दोनों गांव आपस में सड़कों से जोड़ दिए जाएं तो किसानों को और लोगों को 6 किलोमीटर का फासला तय करने की बजाये दो या अढ़ाई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस "ना" के जवाब को "हां" के जवाब में बदलने की कृपा करेंगे?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, सुनारिया, रोहतक—बेरी रोड से कनैक्टिड है और मायना झज्जर—रोहतक रोड से कनैक्टिड है। इसलिए फिलहाल जो रोड यह कह रहे हैं उसको बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

**श्री बलवंत सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पहले ही कह रहा हूं कि वाया रोहतक होकर इन गांवों में जाना पड़ता है। अब मैं यह चाहता हूं कि इन गांवों को आपस में मिला दिया जाये ताकि वाया रोहतक होकर न जाना पड़े। यह सिर्फ दो अढ़ाई किलोमीटर की ही तो बात है।

**श्री धर्मवीर यादव:** ऐसे आल्ट्रानेटिव रोड का कोई प्रावधान नहीं है।

**10.00 बजे**

**श्री भागी राम:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जब मैम्बर साहेब ने एक क्वेश्चन किया है और कहा है कि

एक गांव से दूसरे गांव का फासला अढ़ाई किलोमीटर है, अगर दूसरे साईड से जाएं तो लम्बा सफर तय करके जाना पड़ता है। सड़क तो ये बाद में बना दें “हां” कहने में इनका क्या जाता है?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो काम हम कर सकते हैं उसी के लिए “हां” करेंगे मिथ्या आश्वासन नहीं देंगे जैसे कि पिछली सरकारें करती रही हैं।

**श्री अध्यक्ष:** भागी राम जी, आपको बोलने का मौका देंगे उस वक्त आप बोल लेना लेकिन इस प्रकार से बीच में रनिंग कमेंटरी न करें।

**श्री बलवन्त सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया है कि हर गांव को रोड टू रोड जोड़ा जाएगा। इन गांवों में आने के लिए 7 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है जब कि यह मात्र डेढ़ किलोमीटर का फासला है जो कि ज्यादा नहीं है इसलिए इसको बनवाने की कृपा करें।

**मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल):** अध्यक्ष महोदय, मेरे वायदे के मुताबिक ये दोनों गांव एक तरफ से सड़क से जुड़े हुए हैं, अगर न जुड़े हुए हों तो ये बता दें। स्पीकर सर, लग्जरी के लिए फिलहाल सड़क से जोड़ने का प्रावधान नहीं है अगर इनको जरूरी लगता है तो ये हैलीकॉप्टर ले लें (हंसी)

### **Construction of New Road**



**\*274. Sh. Anil Vij:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state –

(a) the district-wise number of Government fair price shops and ration card holders in the State at present separately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to issue new ration cards to the weaker sections of the Society as per the policy of the Central Government to provide ration at cheaper rates?

**खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल):**

(क) सूचना सदन के पटल पर अनुबन्ध "क" पर रखी है।

(ख) नये राशन कार्ड जारी नहीं किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की नीति के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान राशन कार्डों पर मोहर लगाने का कार्य हरियाणा सरकार ने आरम्भ कर दिया है।

**अनुबन्ध "क"**

**31.1.97 तक जिलावार उचित मूल्य की दुकानें व राशन कार्ड**

जिला का नाम	उचित मूल्य की दुकानों	राशन कार्डों की संख्या
-------------	-----------------------	------------------------

	की संख्या	
1	2	3
अम्बाला	363	162432
यमुनानगर	431	176863
भिवानी	490	224947
गुड़गांव	469	237575
फरीदाबाद	979	398835
हिसार	825	367455
जीन्द	356	171059
कैथल	302	143504
करनाल	479	208970
कुरुक्षेत्र	336	136376
नारनौल	373	125759
रिवाड़ी	247	124569
रोहतक	481	286796

सिरसा	420	189530
सोनीपत	399	202944
पानीपत	340	159357
पंचकूला	168	83328
जोड़:	7458	3400299

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने प्रश्न "ख" भाग के बारे में मंत्री महोदय से सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूँ। गरीबों को सस्ते दाम पर अनाज देने का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और उसके लिए राशन कार्ड की बजाए स्टैम्प लगाने का काम शुरू किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि इस स्टैम्प लगाने का क्राईटीरिया क्या बनाया गया है?

**श्री गणेशी लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि यह जो राशन कार्ड ग्राम में गरीबी रेखा से नीचे आई.आर.डी.पी. संस्थान हे उसके तहत होते हैं, संस्था हरियाणा की है। शहर में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को नेहरू रोजगार योजना के तहत वर्ष 1993-94 में प्रो. लक्कडवाला जिनका स्वर्गवास हो चुका है, की अध्यक्षता में लेटैस्ट सर्वे करवाया गया था जिसके मुताबिक जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 6 लाख 29 हजार ऐसी फेमिलीज हैं जो कि गांवों के अन्दर गरीबी रेखा से

नीचे रह रही हैं ओर 78619 फेमिलीज शहरों के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे राज्य में रह रही हैं। इस प्रकार 1993-94 तक कुल मिलाकर 7 लाख 33 हजार कुछ फेमिलीज ऐसी हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं। इस प्रकार 43 लाख 88 हजार कुल लोग बिलो पावरटी लाईन राज्य में रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को केन्द्रीय मंत्री की फूड मिनिस्टर्ज के साथ हुई कान्फ्रैन्स में तय किया गया है कि अभी अप्रैल तक यह सिस्टम जारी रखा जाए पी.डी.एस. और टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्तर्गत फिर बिलो पावरटी लाईन तथा एबव पावरटी लाईन में विभाजन किया गया है। बिलो पावरटी लाईन के अन्तर्गत आरने वाले लोगों को आधी कीमत पर तथा अढाई रूप्य प्रति किलो ग्राम की दर पर अनाज दिया जाएगा और 50 पैसे उस पर हैण्डलिंग चार्जिजके लगेंगे। 31 मार्च तक राशन कार्डों पर स्टैम्प लगेगी। जहां तक उन्होंने यह जानना चाहा है कि राशन कार्ड नये कैसे बनायेंगे। राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था 5 वर्ष के लिए होती है यह राशन कार्ड 1992-97 के चल रहे हैं जोकि दिसम्बर, 1997 तक चलेगा। आई.आर.डी.पी. लेटैस्ट सर्वे करवाएगी जैसे ही वह कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद दिसम्बर, 1997 के बाद बिलो पावरटी लाईन 43 लाख 88 हजार लोगों को जिनकी चर्चा मैंने की है, भिन्न-भिन्न कलर के कार्ड उपलब्ध करवा देंगे।

**श्री अनिल विज:** अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी ये यह जानना चाहा था कि उनको राशन कार्ड देने के लिए क्राईटेरिया

क्या है और उनके लिए क्या प्रोसीजर अडाप्ट किया जाएगा, ताकि राशन कार्डज देने में इस फ़ैसिलिटी का मिसयूज न हो सके। इसी तरह से मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि सस्ती दरों पर गरीब लोगों को राशन मिलना कब शुरू हो जाएगा और इसमें क्या-क्या राशन होगा?

**श्री गणेशी लाल:** अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को लेटेस्ट कांफ्रेंस हुई है और हम एक मर्ड से इस प्रणाली को आडॉप्ट करेंगे। इस हिसाब से एक कार्ड पर 10 किलो राशन देने का प्रावधान है। इसके अलावा जो इन्होंने मिसयूज होने वाली बात कही है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि जिसकी सालाना 11 हजार रूपये आमदनी हों हे उसको हम बिलो पावर्टी लाईन मानते हैं। इस बारे में शहरों के अन्दर एन.वाई.आर. तथा गांवों में आई.आर.डी.पी. सर्वे करती है। इसमें लैंड लैस लेबरर्ज, नौन एग्रीकल्चर लेबरर्ज, रुरल आर्टिसन, रिक्शा चलाने वाले, फल बेचने वाले, और भट्टा मजदूर, समाल एवं मार्जिनल फार्मर्ज आदि आते हैं। इसके बारे में डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारी सर्वे करते हैं। अब इनकी कुछ संख्या पहले के मुकाबले में बढ़ गई होगी। अध्यक्ष महोदय, गांवों में 6 लाख 29 हजार फ़ैमलीज और शहरों में 78 हजार 6 सौ उन्नीस फ़ैमलीज बिलो पावरटी लाईन आईडेंटिफाई की गई हैं। हो सकता है कि इस सर्वे में कुछ बोगस फ़ैमलीज भी आ गई हों तो इस बारे में हमने इन्स्ट्रक्शन दे रखी हैं कि इसकी सफ़्रीनिंग करके ऐसी फ़ैमलीज को पकड़ें। अगर ऐसी कोई फ़ैमली

होगी तो आपको पता ही है कि ऐसे मामले में जेल जाते देर नहीं लगती।

**श्री करतार सिंह भडाना:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यह आधे रेटों पर अनाज देने की जो स्कीम सैन्टर गवर्नमेंट की है इसके तहत घटिया किरम का अनाज आता है जो कि खराब होने लग गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये इस बारे में कोई कमेटी बनाएंगे जो इस किरम के अनाज की जांच करे अथवा लोगों को घटिया अनाज ही दिया जाएगा?

**श्री गणेशी लाल:** अध्यक्ष महोदय, विलेज लैवल पर, ब्लाक लैवल पर और स्टेट लैवल पर हमने विजिलेंस कमेटियां बना रखी हैं उन कमेटियों में डिप्टी कमिश्नर हो सकता है, म्यूनिसिपल कमिश्नरी हो सकता है और हमारे विपक्ष के भाई चाहें या अगर किसी को शक हो कि अनाज खराब आता है तो वे भी आएँ और इसको चैक करें कहीं अनाज खराब तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर करतार सिंह जी के ध्यान में ऐसा कोई केस है कि ऐसा माल स्टोरेज किया जा रहा है तो ये हमें बताएं हम उस बारे में कार्यवाही करेंगे।

**श्री रमेश कुमार:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि सैन्टर गवर्नमेंट की तरफ से कम रेटों वाला जो राशन आता है वह राशन निम्न वर्ग के लिए आता है लेकिन

वह निम्न वर्ग के लोगों को मिल नहीं पाता है। क्या मंत्री जी इस बारे में कोई कदम उठाएंगे जिससे जिनके लिए वह अनाज आए उनको ही मिले। दूसरा प्रश्न यह है कि हर राशन कार्ड पर 10 किलो अनाज देने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक घर में 10 आदमी हैं तो उनको भी राशन कार्ड पर 10 किलो अनाज देना ही लिखा हुआ है तथा यदि एक घर में पांच आदमी हैं एवं यदि उनका भी राशन कार्ड पर नाम है तो इन सबके बारे में यह लिखा हुआ है कि उनको दस किलो राशन दिया जाएगा। क्या मंत्री जी बताएंगे कि अगर राशन कार्ड पर दस आदमियों का नाम भी लिखा हुआ है तो उनको भी दस किलो राशन दिया जाएगा एवं यदि पांच आदमियों का नाम लिखा हुआ है तो क्या उनको भी दस किलो ही अनाज दिया जाएगा।

**श्री गणेशी लाल:** सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि राशन कार्ड पर दस किलो राशन देने का ही प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निश्चित किया गया है चाहे राशन कार्ड पर दो लोगों के नाम हों, चाहे लोगों के नाम हों या फिर 6 लोगों के नाम हों। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक बात और तय की है और वह है इम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम एवं जवाहर रोजगार योजना। इनके अन्तर्गत जो लोग मजदूरी का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को एक किलो एक व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन राशन मिलता है। जैसे फर्ज करो कि एक परिवार ने ही काम किया तो उनको एक कूपन अलाट किया

जाएगा और इसके माध्यम से एक किला राशन एक दिन में एक व्यक्ति को अलग से देने का इसके अंदर प्रावधान है। जहां तक इन्होंने कहा कि राशन ठीक से नहीं पहुंचता है और कहीं न कहीं बीच में ही गड़बड़ हो जाती है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत किसी पर्टीकुलर डिपो के बारे में सदस्य के पास है तो ये कृपया हमें बता दें, हम इसको देखकर तुरन्त ऐक्शन लेंगे।

### **Construction of Bus Stand, Babain**

**\*290. Sh. Banta Ram Balmiki:** Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bus Stand at Babain; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

**परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण पाल गुर्जर):** जी नहीं।

**श्री बन्ता राम बाल्मिकी:** स्पीकर सर, बबैन कस्बा मेरे हल्के का एक बहुत बड़ा कस्बा है। इसके आसपास सौ गांव पड़ते हैं और यह कस्बा मेरे हल्के का दिल है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि हरियाणा के 90 क्षेत्रों में सबसे अच्छा क्षेत्र है जहां पर धरती माता अपना सीना चीरकर अनाज के गोदाम भरती है। स्पीकर सर, वहां पर बस स्टैंड न होने की वजह से सड़क के ऊपर एक किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से



सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इस क्षेत्र को केवल सुरक्षित क्षेत्र में समझें। यह बस स्टैंड बनना पब्लिक इंटरस्ट में जरूरी है। क्या मंत्री जी बबैन बस स्टैंड को बनाने की तरफ ध्यान देंगे, यदि हां तो कब तक वे इसकी बनवा देंगे?

**श्री कृष्ण पाल गुर्जर:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनको बताया चाहूंगा कि हमारी सरकार सुरक्षित क्षेत्र एवं जनरल क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं करती है। माननीय सदस्य ने अभी इसके बारे में लिखकर नहीं दिया है अगर ये हमें लिखकर दे देंगे और अगर वहां बस स्टैंड बनाने के लिए सारी शर्तें पूरी होती हैं तो हम जरूर इसके बनाने के बारे में विचार करेंगे।

**श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान:** स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन रूरल एरियाज में जो बस डिपोज हैं लेकिन वहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए शैल्टर शैडज नहीं बने हुए हैं, क्या मंत्री जी वहां पर शैल्टर शैडज बनवाने की कृपा करेंगे?

**श्री कृष्ण पाल गुर्जर:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय बिजेन्द्र सिंह को बताना चाहूंगा कि ऐसा मामला विचाराधीन है और कुछ बस शैल्टर शैडज हम बनाने जा रहे हैं। यह हमें इस बारे में लिखकर दे दें, हम उस पर जरूर गौर करेंगे।

राव नरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अटेली बस स्टैंड का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इस पर कितनी लागत आएगी?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदस्य को बताना चाहूंगा कि अटेली में पांच एकड़ एक कनाल भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस पर 34687 रूपये खर्च होने थे। इस कार्य को अगले 6 महीनों में पूर्ण कर दिए जाने की संभावना है।

### **National Capital Region**

**\*285. Sh. Dhir Pal Singh:** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state –

(a) whether any funds have been earmarked/received from the Central Government during the years 1991-92 to 1995-96 for the development of the areas of the State under National Capital Region (NCR); and

(b) if so, the year wise details thereof togetherwith the names of the areas developed with the said funds?

**नगर तथा ग्राम आयोजन मंत्री (सेठ सिरी किशन दास):**

(क) जी हां महोदय।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वर्ष 1991-92 से वर्ष 1995-96 तक

जो केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा निम्न अनुसार है:—

वर्ष		
1991—92	शापिंग सेंटर सैक्टर 3, रिवाडी	7.00
	ब्रास, मार्केट रिवाडी	27.00
	इनफारमल सैक्टर 25, पानीपत	32.00
	शापिंग सेंटर, सैक्टर 6 धारुहेड़ा	8.00
	आवासिय सैक्टर 2, 3 और भाग -4 रोहतक	200.00
	अः	274.00
1992—93		
1993—94	आवासिय सैक्टर 2, 3 भाग 4, रोहतक	200.00
	बः	200.00
1994—95		
1995—96	आवासिय सैक्टर 2, 3, भाग रोहतक	350.00
	आवासिय सैक्टर 13 और 17 पानीपत	720.00

	आवासिय सैक्टर 3 (भाग-II) रेवाड़ी	220.00
	आवासिय सैक्टर 59, फरीदाबाद	623.58
	आवासिय सैक्टर 39, गुड़गांव	650.73
	आवासिय सैक्टर 12, सोनीपत	907.00
	आवासिय सैक्टर 40, गुड़गांव	752.00
	सः	4223.31
	कुल जोड़ अ+ब+स=रूपये	4697.31
		लाख

**श्री धीरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि कल मेरी सप्लीमेंट्री के दौरान भवन और सड़क मंत्री जी ने झज्जर बाई पास पर जो उत्तर जारी किया उसमें एन.सी. आर. के तहत उसके निर्माण की बात की गई जब कि आज जो सदन के पटल पर रिप्लाइं आया है इसमें कहीं भी झज्जर और बहादुरगढ़ की चर्चा नहीं है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था का प्रश्न है और मंत्रीगण हाउस को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। सन् 1991 से 1996 तक झज्जर बहादुरगढ़ ग्रामीण अंचल के विकास के लिए एन.सी.आर. के तहत कोई राशि नहीं मिली। इस बारे में भले अभी जवाब न दिया जा सके तो 21 तारीख तक हाउस चलेगा। आप इस बारे में समय दें।

**Mr. Speaker:** You may please ask the question and not make the statement.

**श्री धीरपाल सिंह:** सर, यह सीरियस मामला है, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि ऋण के रूप में इन 5-6 शहरों के विकास के लिए जो राशि मिली है क्या इसका प्रस्ताव प्रदेश की तरफ से गया था या एन.सी.आर. ने खुद इनका चयन किया था? दिल्ली के पास सबसे पहले कोट इलाका है तो बादली और बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत के कुछ गांव हैं जहां कि सारी की सारी मार हमें झेलनी पड़ती है वहां से आने जाने की, रहने की सारी परेशानियां हमारी हैं लेकिन पिछले 6 साल के दौरान एन.सी.आर. से जो 4223.31 लाख रूपया मिला है उसमें से एक भी पैसा ग्रामीण अंचल के विकास के लिए खर्च नहीं हुआ। क्या एन.सी.आर. से अनुदान केवल शहरों के लिए मिलता है या गांवों के लिए भी मिलता है और क्या गांवों के लिए प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव उनके पास भेजा है?

**सेठ सिरी किशन दास:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एन.सी.आर. का रूपया इस वास्ते आता है ताकि दिल्ली से बाहर रिहायशी मकान बनाये जायें, सड़कें बनाई जायें ताकि दिल्ली की आबादी को बोझ कुछ कम हो सके इसी वास्ते बहादुरगढ़ में जोकि दिल्ली के पास लगता है, मकान और कालोनियां तथा सड़कें बनाई जा रही हैं और एन.सी.आर. का रूपया खर्च किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 334 (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नो मोर सप्लीमेंटरी, कृपया बैठिये।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने कल रूलिंग भी दी थी कि एक विधायक दो से ज्यादा सप्लीमेंटरी पूछ सकता है (इस दौरान कई मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष: मैंने कल इस महान सदन को यह आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे पूरा प्रयास करूंगा I am trying to give opportunity to every member to ask more than one supplementary but this is not a right.

### वाक आउट

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूँ जो इस एन.सी.आर. के तहत पैसा आता है (विघ्न) यह कोई व्यवस्था है अगर आप मुझे बोलने नहीं देते तो मैं इस सदन से वाक आउट करता हूँ। (इस समय श्री धीरपाल सिंह सदन से वाक आउट कर गये) (विघ्न एवं शोर)

तांराकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनराम्भ)

### Construction of Roads

**\*334. Sh. Sri Krishan Hooda:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal to construct a road from village Sanghi to Chiri in District Rohtak; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

**लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव):**

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस सड़क का निर्माण मार्च, 1998 तक धन की उपलब्धि पर कर दिया जायेगा।

**श्री सिरी कृष्ण हुड्डा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एरिया है जिसकी सड़क को जोड़ना है, क्या मंत्री जी इस काम को प्रोरियरिटी देकर बनाने का प्रयास करेंगे?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, मामला विचाराधीन है ज्यों ही फण्डज अवेलेबल होंगे सड़क बना दी जायेगी।

**श्री सिरी कृष्ण हुड्डा:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि वे कोई ऐसी डेट टाईम बतायें जिस तक यह सड़क बन जायेगी।

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को लिखित रूप में भी बताया है कि यह सड़क मार्च 1998 तक बना दी जायेगी।

**श्री बलवीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि रोहतक शूगर मिल के पास जा सुनारिया बाई पास बनना है वह कब तक बना दिया जायेगा? मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सुनारिया बाई पास सड़क को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें क्योंकि किसानों को रोहतक शूगर मिल में आना पड़ता है और बाईपास सड़क के बिना जमींदारों को दिक्कत है।

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का एस्टिमेट बनाकर फण्डज के अवेलेबल होने पर जल्दी ही निर्माण कार्य करा दिया जायेगा।

**श्री बलवीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, यह कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। मंत्री जी कृपया यह बताएं कि कितने दिन यह काम ऐसे ही लटका रहेगा?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री सतविन्द्र सिंह राणा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरे गांव राजौन्द में केवल आधा किलोमीटर का रास्ता है जो कि असंध और कैथल का मेन रास्ता है। इसके लिए एस्टिमेट



भी बन चुका है लेकिन पता नहीं किस कारण वे कैथल का मेन रास्ता है। इसके लिए एस्टिमेट भी बन चुका है लेकिन पता नहीं किस कारण से वह एस्टिमेंट भी वापिस कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सड़क पर कार्य कब तक हो जाएगा?

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, ये लिखित रूप में हमें दे दें, हम इसका एस्टिमेट बनवा लेंगे तथा शीघ्र ही हम इस सड़क को बनवाने की कोशिश करेंगे।

**श्री सतपाल सांगवान:** अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मंत्री महोदय खुद मेरी कंस्टीच्यूएंसी में गए थे और इन्होंने गांव भागेश्वरी से भिवानी जो रोड़ जाती है, उसकी हालत भी देखी थी। ये तो नई सड़क की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां तो पिछले बीस साल से किसी भी सड़क पर एक चवन्नी भी खर्च नहीं की गई। मंत्री जी ने इस सड़क को खुद भी देखा है। इसलिए मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे यह बताएं कि इस सड़क को कब तक रिपेयर करवाने की कृपा करेंगे।

**श्री धर्मवीर यादव:** अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी सड़कें हैं वे सब सरकार की हैं तथा उनकी देखरेख व मुरम्मत वगैरह की जिम्मेवारी सरकार की है। मेरा आश्वासन है कि हर सड़क की मुरम्मत की जाएगी।

**Providing of TA/DA to the Members of Zila Parishad**

**\*342. Sh. Kailash Chander Sharma:** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the facility of T.A./D.A. to the members of Zila Parishad (District Council) for attending the meetings of Zila Parishad or hearing the public grievances in their constituencies.

**Development & Panchayats Minister** (Sh. Kanwal Singh): Yes Sir. It has been decided to provide the facility of T.A./D.A. to the elected representatives of Panchayati Raj Institutions including members of Zila Parishads for their official journeys. Necessary instructions have been issued in this regard.

**श्री कैलाश चन्द्र शर्मा:** माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परिशदों को बने दो साल हो गए हैं और इस बीच इनकी 24 मीटिंगे भी हो चुकी हैं। जबकि पंचायत समितियां जिला परिशदों से छोटी संस्थाएं हैं फिर भी इनके सदस्यों को टी.ए.डी.ए. मीटिंग के दिन ही मिल जाता है लेकिन जिला परिशदों के सदस्यों को उसी दिन टी.ए.डी.ए नहीं मिलता है। इस बारे में वैसे मुख्यमंत्री जी की जिला परिशदों के चेयरमैनो से अच्छी तरह से बातचीत हो चुकी है। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि जिला परिशदों को टी.ए.डी.ए. मीटिंग के दिन ही दिया जाए और पीछे का बकाया टी.ए.डी.ए. भी दिया जाये तथा उनको बस पास भी दिए जाएं। क्योंकि 30-30, 35-35 कि.मी. का इनका क्षेत्र पड़ता है इसलिए बस पास

कम से कम जिला परिशद को जिले तक अवश्य दिया जाये जिससे वह अपने जिले में आ जा सके ।

**श्री कंवल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इंस्ट्रक्शंज इशू हो गई हैं और बहुत जल्दी ही कार्यवाही हो जाएगी ।

### **Repair of Water Courses**

**\*372. Dr. Virender Pal Ahlawat:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged water courses constructed by CADA and MITC in the State?

**Chief Minister** (Sh. Bansi Lal): Yes Sir, Command Area Development is a centrally sponsored programme funded by the Government of India and the State Govt. on matching basis. This programme envisages repair of the damaged water courses through Water Users Associations which are being formed as per the guidelines issued by the Government of India. MITC is undertaking repair of the damaged water courses under the World Bank Funded Water Resources Consolidation Project. The repaired/functional water courses will eventually be handed over to the beneficiaries through Water Users Associations for operation and maintenance.

**Dr. Virender Pal Ahlawat:** Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state whether such associations of the farmers already exist in the State or not? If yes, how many associations are already there and what are the conditions required to be fulfilled by the farmers to be the members of such associations? Thirdly, in his reply, the worthy Chief

Minister has stated that repaired water courses will be handed over to the beneficiaries or the users of the water courses through associations. Sir, in this connection, I would like to know whether the repair works are undertaken by both the agencies mentioned in the reply or by one agency i.e. M.I.T.C. I would also like to know whether in each village of the State, such association has been established or not?

**Mr. Speaker:** Questions hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के  
लिखित उत्तर

#### **Allotment of Custodian Land**

**\*316. Sh. Jagbir Singh Malik:** Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the Custodian land has been allotted to some influential persons in the State during the years 1994-95 and 1995-96; and

(b) if so, the details thereof, togetherwith the action taken/proposed to be takne against such persons?

**Revenue Minister** (Sh. Suraj Pal Singh):

(a) & (b) A Statement regarding total allotments made is laid on the Table of the House.

#### **Statement**

**Statement showing the allottees who have allotted  
Custodian Land during the year 1994-95 & 1995-96 (1.4.94  
to 31.3.96)**

Sr. No.	Name of the Village with Tehsil in which allotment has been made		Date on which actual allotment made	Area allotted in O.A.	Name of the allottee in whose name allotment has been made
	Village	Tehsil			
1	2		3	4	5
<b>1. District Ambala</b>					
1	Kalu Majra	Naraingarh	23.07.94	4.7.15	Rulda Ram S/o Tara Chand, R/o Tajpur (Panipat)
2	Rataur	do	1.09.94	5.6.14	Dewan Singh S/o Amar Singh, Vill. Ali Sadar (Hisar)
3	Rataur	do	23.07.94	29.0.0	Rulda Ram S/o Tara Chand R/o Tajpur (Panipat)
4	Pilkhani	Ambala	26.12.94	0.1.7	Rajinder Singh S/o Sarda Singh, Vill. Hizrawan Khurd (Hisar)

	Bhundia	do		0.7.11	
	Sajan Majra	do		1.0.13	
	Malikpur	do		0.7.12	
	Shadipur	do		0.7.18	
	Sabka	do		0.3.10	
5	Nikasi	do	28.7.94	3.3.2	Tulsi Dass S/o Rattan Lal, R/o Ali Sadar (Hisar)
	Sirasgarh	do		2.5.17	
6	Tangali	do	22.5.94	0.2.13	Bishan Dass S/o Ram Kishan, C/o Maru Lal Employee Central Govt. Chandigarh
	Babyal	do		0.6.0	
	Panjail	do		0.2.19	
7	Sirasgarh	Barara	08.11.95	1.4.0	Soda Ram S/o Dawan Chand
8	Gola	Ambala	22.05.94	1.0.1	Narender S/o Sada, R/o Ali Sadar (Hisar)
9	Shadipur	do	12.06.94	0.3.0	Nand Singh S/o Prem Singh, R/o

					ITI, Ludhiana
	Dulliana	do		0.1.11	
	Jalubi	do		0.2.9	
	Tangali	do		0.3.16	
	Pattanheri	do		1.2.0	
10	Gola	do	30.11.94	8.7.0	Ishar Dass S/o Radha Krishan, R/o Sherpur, Teh. Ambala
11	Jassal Majra	do	10.6.94	1.4.16	Sadhu Singh S/o Sham Singh, R/o Ali Sadar (Hisar)
12	Toba	Ambala	14.07.94	1.6.2	Gobind Singh S/o Jawand Sing, R/o Lada Khadar Distt. Yamuna Nagar.
	Tibbi	do		1.7.17	
13	Gola	do	24.6.94	38.1.6	Uttami Bai W/o Tula Ram, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
14	Jaimal Majra	do	02.08.94	5.5.0	Raji Bai W/o Chahan Dass, R/o Hizrawan Khurd

					(Hisar)
	Mangoli	do		2.3.3	
15	Gola	do	12.08.94	9.0.0	Jagdish Chand S/o Sant Ram, R/o Patvi, Distt. Kaithal
16	Kalu Majra	do	26.08.94	15.3.0	Teja Singh S/o Mangat Singh, R/o Mukeria (Hisar)
17	Sarangpur	do	25.12.94	42.0.3	Mangal Singh S/o Isher Singh, R/o Jamer
18	Sirasgarh	do	do	2.5.15	Gurbax Singh S/o Inder Singh, R/o Sirasgarh, Ambala
	Ramgarh		do	0.2.14	
19	Dera	Naraingarh	05.08.94	4.0.15	Hira S/o Ram Ditta Mal R/o Vishvakarama Colony, Yamuna Nagar.
20	Rataur	do	05.04.94	21.5.4	Arun Singh S/o Bisakhi Singh, R/o Hizrawan Khurd



21	Dera	do	05.08.94	0.7.5	Bishan Dass S/o Ram Kishan, C/o Maru Lal Employee, Central Govt. Chandigarh.
22	Rao Majra	do	22.05.94	2.5.15	Nathu S/o Sadhu, R/o Ali Sadar (Hisar)
	Dera	do		0.7.19	
23	Rataur	do	09.06.94	27.1.4	Jagar Singh S/o Foja Singh, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
24	Shadipur	do	04.07.94	6.2.12	Bir Singh S/o Pal Singh
	Ganeshpur	do		2.3.19	
25	Dera	do	02.08.94	8.6.18	Sadhu Singh S/o Gujjar Singh, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
26	Rajauli	Ambala	06.01.95	3.2.0	Sadhu Singh S/o Shyam Singh, R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
27	Sirasgarh	do	30.09.95	6.7.19	Maya Devi W/o

					Dewan R.C. Khochar
28	Saha	do	14.06.95	0.4.0	Tara Singh S/o Nanak Singh, Vill. Hizrawan Khurd (Hisar)
	Dudla	do		1.0.0	
29	Tapla Alludin	do	20.11.95	0.6.0	Jodh Singh S/o Sajjan Singh, Vill. Khurd Beri, Radaur
	Majra	do		2.5.4	
30	Sirasgarh	Ambala	23.11.95	1.1.19	Gurbax Singh S/o Sunder Singh
31	Tharwa	do	27.03.95	0.5.18	Ram Niwas S/o Shankar Dass
32	Dhanaura	do	16.11.95	0.3.16	Bishan Dass S/o Gurditta, R/o Ali Sadar (Hisar)
	Sohala	do		1.6.10	
	Ugala	do		2.1.0	
33	Ugala	do	13.11.95	0.1.16	Tahla Ram s/o Thakar Dass
34	Sounthli	do	20.07.95	2.0.0	Jodh Singh S/o Sajjan Singh, Vill.

					Khurd Beri (Yamuna Nagar)
	Rataur	do		2.6.0	
	Wassipur	do		0.5.6	
35	Rataur	do	13.01.95	2.3.10	Inder Singh S/o Foja Singh, Vill. Hizrawan Khurd (Hisar)
	Sultanpur	do		0.5.0	
	Rataur	do		9.7.17	
36	Dera	do	09.06.95	6.1.11	Sant Kaur W/o Ladha Singh, Vill. Ali Sadar (Hisar)
	Maumadpur	do		2.7.2	
	Kathumazra	do		1.4.17	
	Chhachhrauli	do		0.2.0	
37	Dera	N.Garh	12.10.95	39.4.15	Tehla Ram S/o Thakar Dass
38	Rataur	do	03.11.95	6.6.19	Jeewan Dass S/o Nihal Chand
39	Talhari	Ambala	12.01.96	0.2.4	Kesar Singh S/o Sawal Singh, R/o Hizrawan Khurd,

					Teh. Fatehabad, Distt. Hisar
	Kalpi	do		0.1.5	
	Manumajra			0.5.1	
	Jahangirpur			0.3.2	
	Tandwal			2.4.8	
	Sultanpur			0.7.7	
	Sohana			1.6.0	
	Sajan Majra			1.6.17	
	Binjalpur			1.2.5	
	Khera			1.1.11	
40	Pilkhani		29.02.96	1.5.0	Labh Chand S/o Lal Chand
41	Sohata	do	do	0.1.13	Gian Chand S/o Lal Chand
	Pilkhani	do		3.7.4	
42	Dera	N.Garh	12.01.96	21.0.1	Kesar Singh S/o Sawal Singh, R/o Hizrawan Khurd, Teh. Fatehabad (Hisar)

	Rajo Majra			3.3.0	
		<b>Total</b>		<b>400.1.8</b>	
<b>2. District Yamuna Nagar</b>					
1	Jaroda	Jagadhari	15.04.94	16.4.0	Attar Singh S/o Bharat Singh, ITI, Kaithal
2	Mikher	do	20.05.94	2.4.19	Nandu S/o Sadhu, R/o Ali Sadar, Hisar
	Khajuri			2.0.16	
3	Machhrauli	do	12.06.94	1.2.8	Nand Singh S/o Prem Singh, R/o 17-G, Ludhiana
	Gurjani			1.0.0	
4	Lada Khera	do	14.07.94	10.1.13	Gobind Singh S/o Jawand Singh R/o Lada Khera, Distt. Yamuna Nagar.
5	Minapur	do	26.08.94	3.7.6	Mutani Ram S/o Sukh Dayal, R/o Yamuna Nagar.
6	Ibrahimpur	do	14.06.95	6.0.13	Hans Raj S/o Goverdhan Lal, R/o Hijrawan Khurd

					(Hisar)
7	Sunder Bahadurpur	do	14.06.95	4.2.0	Tara Singh S/o Santa Singh, R/o Jammu
8	Kot Sarkari	do	20.8.95	4.1.6	Jodh Singh S/o Sajjan Singh, r/o Khurd Bhan, Tehsil Radaur
9	Mohalanwali	do	12.06.95	1.0.14	Mohan Lal S/o Boor Singh, R/o Modern Colony, Yamuna Nagar.
10	Leharpur	do	14.11.95	12.6.6	Gangi Bai W/o Bhagwan Dass.
11	Ramgarh	do	3.10.95	8.612	Gobind Lal S/o Padam Lal
	Gumthala			14.6.12	
12	Guhlapur	do	20.10.95	5.2.3	Khandi Bai S/o Lal Chand R/o Indri, Distt. Karnal.
	Gorabandi	do		5.1.0	
	Kabarwali			5.3.10	
	Chhachhrauli			0.6.0	

	Baloli			0.1.0	
13	Laherpur	do	8.8.95	14.3.5	Bodh Raj S/o Chuni Lal R/o Raipur, Dehradun
	Udhamgarh			10.5.8	
	Tibbi Ararain			1.4.10	
14	Ugamgarh	do	29.02.96	13.2.11	Jaswant Ram S/o Ali Sadar, Hizrawan Khurd (Hisar)
15	Arainwala	do	do	5.7.10	Harphool etc. S/o Narain Dass R/o Hijrawan Khurd Distt. Hisar.
		<b>Total</b>		<b>153.0.12</b>	
<b>3. District Panchkula</b>					
1	Dabkori	Kalka	10.06.94	0.5.7	Rajinder Singh S/o Shardha Singh R/o Hizrawan Khurd (Hisar)
	Shahpur	do		0.7.7	
	Alipur	do		0.2.2	
2	Kot	do	do	10.3.9	Sahu Singh S/o Sham Singh Vill.

					Ali Sadar, Distt. Hisar
3	Fatehpur Dewan wala	do	02.08.94	5.6.3	Ram Ditta Ram S/o Mangal Ram R/o 428, Subash Nagar, Ludhiana
4	do	do	14.10.95	25.0.12	Tara Chand S/o Santa Ram, R/o Hizrawan Khurd, Hisar
5	do	do	02.12.95	0.6.8	Sant Kaur, W/o Ladha Singh, R/o Ali Sadar, Hisar
6	Khokhran	do	30.08.95	18.6.5	Mangal Singh S/o Ishar Singh, R/o Jammu
7	do	do	26.8.95	11.0.15	Madan Mohan Mehra S/o Nand Kishore R/o Jammu
8	Fatehpur Dewanwala	do	30.9.95	30.6.8	Bhikam Singh S/o Rumla Singh, R/o Hizrawan Khurd, Hisar
9	do	do	13.10.95	15.7.12	Ram Kishan S/o



					Pokhar Dass
			08.11.95	12.2.19	
			06.01.95	3.4.0	
10	do	do	13.10.95	8.3.0	Ishar Singh S/o Natha Singh
11	do	do	do	3.1.12	Mam Singh S/o Ishar Singh
12	do	do	03.11.95	10.1.1	Sadhu Singh S/o Sham Singh R/o Vill. Ali Sadar, Hisar
13	do	do	25.10.95	10.0.4	Jeewan Dass S/o Nihal Chand
14	Alipur	do	07.11.95	10.5.19	Khandi Bai W/o Lal Chand R/o Indri, Distt. Karnal
15	Fatehpur Dewanwala	do	15.11.95	37.6.19	Kalu Ram S/o Raghu Ram
16	Fatehpur Dewanwala	do	do	8.3.4	Attar Singh S/o Bir Singh
17	Haripur	do	do	3.4.1	Ishar Singh S/o Bahadar Singh
	Hari Singh		do	2.5.1	

18	Fatehpur Dewanwala	do	do	2.3.4	Chanan Mal s/o Jaimal Singh
19	Bhogpur	do	27.11.95	1.4.1	Sadhu Singh S/o Hardial Singh
20	Fatehpur Dewanwala	do	18.11.95	12.0.0	Kahan Singh S/o Guhala Singh
21	Fatehpur Dewanwala	Kalka	18.11.95	37.5.2	Roop Singh S/o Gainda Singh
22	do	do	30.11.95	9.1.1	Pale Singh S/o Deva Singh, R/o Bhunder, Sirsa
23	do	do	3.12.95	26.3.4	Bhudh Singh S/o Hema Ram
24	do	do	do	11.3.19	Juma Ram s/o Handi Ram
25	do	do	30.12.95	9.7.2	Lal chand S/o Pokhar Dass
26	do	do	07.12.95	8.6.9	Bhawani Dass S/o Hira Mal R/o Hizrawas Khurd (Hisar)
27	do	do	do	13.6.18	Amir Chand S/o Mohri Ram
28	do	do	do	13.6.18	Chandran S/o

					Salmdha
29	do	do	07.12.95	13.6.18	Vir Bhan S/o Devi Ditta
30	do	do	09.01.96	27.0.2	Gurditta Mal S/o Gahela Ram
31	do	do	do	11.0.2	Ashi Ram S/o Devi Ditta
32	Dabkohri	do	12.01.96	0.1.5	Kasher Singh S/o Sewal Singh, R/o Hizrawan Khurd Teh. Fatehabad, Distt. Hisar
	Mirapur Bakshiwala	do		1.5.1	
	Ishlam Nagar	do		1.1.1	
33	Fatehpur Dewanwala	do	06.02.96	85.3.15	Mool Chand S/o Nihal Chand
34	Dabkohri	do	29.02.96	0.5.13	Labh Chand S/o Lal Chand
		<b>Total</b>		<b>519.2.3</b>	
<b>4. District Karnal</b>					
1	Kunjpura	Karnal	1.7.94	0.3.18	Gyan Chand S/o Thakar Dass V.

					Sandeer (Karnal)
2	Kasba Karnal	do	13.6.94	8.4.15	Mohinder Kumar S/o Nand Kishore Vill. Vaisali Nagar, Ajmer, Rajsthan
3	Kasba Karnal	do	10.10.94	2.3.4	do
4	Mundigari	do	28.10.94	6.3.1	Smt. Gyan Kaur W/o Boora H.No. 97, Sector 23 A, Chandigarh
	Bohla			10.6.0	
5	Mundigarhi	do	26.8.94	8.4.10	do
6	Rai Tekhan	do	18.1.95	6.4.16	Punnu Ram S/o Asha Ram R/o 1877, Marg Kotla Mubarkpur, Delhi
	Makhala			0.4.0	
	Garhpur Khalsa			1.0.0	
7	Bhola	do	31.3.95	21.1.6	M.D. Nangia S/o Hem Raj Nangia R/o Mohali Road, Dehradun, U.P.
	Ghandrav			4.7.0	

8	Kasba Karnal	Karnal	24.8.95	4.3.9	Lal Chand S/o Kesar Dass R/o Hijrawan Khurd, Teh. Fatehabad Hisar
9	do	do	18.1.95	1.1.3	Laxman Dass S/o Nand Kishore, 2/629, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajsthan)
		<b>Total</b>		<b>76.7.2</b>	

#### 5. District Panipat

1	Patti Insar	Panipat	12.8.94	1.7.15	Sukh Ram S/o Udai Singh R/o Navel (Karnal)
2	Taraf Madkum Jadgan	do	26.7.94	1.2.14	Jeta ram S/o Tikkan Ram R/o H.No. 720, Sector 13, U.E. Karnal
3	Taraf Rajputana	do	28.10.94	6.3.17	Smt. Gian Kaur W/o Boor, H.No. 93, Sector 28, Chandigarh
4	Patti Insar	do	18.1.95	7.3.5	Gurdial Singh S/o Jhande Singh Shahbad

					markanda, Distt. Kurukshetra
5	Kachroli	do	12.6.95	3.7.12	G.D. Nangia S/o Hem Raj, H.No. H- 56, Kirti Nagar, New Delhi
6	Taraf Insar	do	24.8.95	2.2.13	Lal Chand S/o Kesar Dass R/o Hijrawan Khurd Teh. Fatehabad, Distt. Hisar
	Taraf	do		2.2.0	
	Rajputana				
	Kawan Bag.	do		1.1.4	
		<b>Total</b>		<b>26.7.0</b>	
<b>6. District Kaithal</b>					
			Nil		
<b>7. District Kurukshetra</b>					
1	Patti Kakran Shahabad	Thanesar	18.1.95	2.1.0	Krishan Mal S/o Chamru Mal, R/o Patti Kalan, Teh. Thanesar, Kurukshetra

2	do	do	11.7.94	8.5.15	Attar Singh S/o Bhagat Singh, R/o Julana Teh. Fatehabad, Hisar
3	do	do	15.6.94	17.4.2	Inder Kumar S/o Nand Kishore, Ajmer Hall H.No. 720, Sector 13, U.E. Karnal
4	Patti Kakran Shahabad	Thanesar	12.6.95	4.7.1	Lachhman Dass S/o Nand Kishore, R/o 2/629, Jawahar Nagar, Awrana Mandal Scheme, Jaipur
5	do	do	22.3.96	15.1.13	Ram Saran S/o Hosnak Rai, H.No. C-1042, Dayal Pura, Karnal.
		<b>Total</b>		<b>48.3.11</b>	
<b>8. District Rohtak</b>					
1	Rohtak	Rohtak	9.5.94	0.3.0	Banesh Dass S/o Chhata Ram, Kahanaur.
2	Meham	do	5.9.94	3.0.8	Hemi Bai, D/o Khamisa Ram R/o

					Mehtam
3	do	do	do	8.7.0	Khamisa Ram S/o Aya ram, R/o Meham.
4	Jahajgarh	do	10.2.95	3.4.1	Jagga Ram Kudda ram S/o Suharu Ram R/o Dujana.
5	Nigana	do	9.3.95	6.2.10	Gela Ram etc.
6	Kherka Rajputana	do	31.5.95	8.6.0	Chellu Ram S/o Lalji R/o Vill. Assalwas.
7	Rohtak	do	14.6.95	0.1.10	Aya Singh S/o Diwan Singh R/o Rohtak.
8	Maham	do	30.6.95	6.5.15	Attar Chand S/o Mohri Ram.
9	Nigana	do	25.3.96	3.2.10	Jhanda Ram S/o Khem Chand.
		<b>Total</b>		<b>41.0.14</b>	

### 9. District Sonapat

1	Jhundpur	Sonapat	6.12.94	2.1.0	Wazir Chand S/o Budh Ram
2	Giaspur	Ganaur	1.1.95	12.60	Radhey Sham S/o



					Asa Nand.
3	Bega	Ganaur	31.5.95	31.0.1	Sh. Chhatu Ram S/o Lal
	Panchhi Gujran	do	31.5.95	8.2.9	do
4	Bega	do	do	45.5.10	Sawan Ram S/o Tikkan Ram
5	Bega	do	5.9.95	5.7.10	Kapoor Singh S/o Sunder Singh
	Chandoli	do	do	0.6.15	do
6	Bega	do	29.9.95	32.2.0	Jhanda ram S/o Khem Chand
7	do	do	do	46.1.0	Mohinder Kumar Mehta S/o Nand Kishore
	Pabnera	do	16.6.95	30.0.10	Chander Bhan S/o Fatech Chand
8	Gyaspur	do	19.6.95	13.0.0	Bihari Lal S/o Chhata Ram, Jiwani Bai, Dharm Chand.
9	Gyaspur	Ganaur	19.6.95	3.6.0	Smt. Viran Bai W/o Ram Parkash.

10	do	do	do	4.0.0	Ram Gopal Harijan R/o Sonapat.
11	do	do	do	2.7.10	Hans Raj S/o Nand Lal R/o Sonapat.
12	do	do	do	3.6.0	Sant Lal S/o Nand Lal R/o Sonapat.
13	Barot	do	8.9.95	3.6.5	Attar Chand S/o Mohri Ram
14	do	do	18.10.95	0.4.0	Jeewan Dass S/o Bagi Ram
15	do	do	do	0.2.18	do
	do	do	do	1.6.7	do
	do	do	do	1.6.18	do
16	Sonapat	Sonapat	8.1.96	0.1.5	Aya Singh S/o Diwan Chand
17	Juan	do	5.9.95	2.0.11	Kapoor Singh S/o Sunder Singh
18	Chandoli	Ganaur	12.2.96	16.0.1	Ram Ditta Mal S/o Kishan Chand R/o Sanipat
19	Barot	do	21.3.96	0.1.7	Ajit Singh S/o Pala Singh

	Pabnera	do	21.3.96	1.5.16	do
	Chandoli	do	do	4.2.9	do
	Umedgarh	do	do	0.3.13	do
		<b>Grant Total</b>		<b>272.5.15</b>	
<b>10. District Jind</b>					
Nil					
<b>11. District Hisar</b>					
1	Agroha	Hisar	22.9.94	4.3.12	Diwan Singh S/o Amrik Singh Vill. Hijrawan Khurd, Distt. Hisar
		<b>Grand Total</b>		<b>4.3.12</b>	
<b>12. District Bhiwani</b>					
1	Siwani	Siwani	7.9.94	2.4.0	Deewan Singh S/o Amrik Singh R/o Chak No. 8 LL, Distt. Sri Ganga Nagar, Rajasthan.
2	Dhani Silanwali	do	11.5.95	21.5.16	Surat Singh S/o Mehanga Ram R/o H.No. 428, W.No. 1, Sirsa (Sirsa)

3	Baindawas	do	19.5.95	8.6.10	Sant Ram S/o Kishan Chand R/o Ali Sadar, Teh. Fatehabad, Hisar
		<b>Grand Total</b>		<b>33.0.6</b>	
1	Ahamadpur Darewala	Ellanabad	29.12.94	2.12.13	Parkash Singh S/o Kishan Singh
2	Nattar	Sirsa	1.12.95	0.5.7	Krishan Kumar S/o Basti Ram Vill. Bhawadeen Teh. & Distt. Sirsa
		<b>Grand Total</b>		<b>3.0.0</b>	
<b>14. District Rewari</b>					
Nil					
<b>15. District Mohindergarh</b>					
1	Mori	Mohindergarh	25.4.94	17.1.11	Jhangi Ram S/o Topal Dass R/o Teh. Tohana
	Gudyani	Kosli			
	Puriawas	do			
	Garhi	do			
2	Narnaul	Narnaul	23.06.94	12.2.19	Mohinder Kumar S/o Nand Kishore

					Ajmer, (Rajsthan)
		Gudha			
		<b>Grand Total</b>		<b>29.4.10</b>	
<b>16. District Gurgaon</b>					
1	Bawla	Nuh	20.3.95	1.1.0	Smt. Lalo Bai, D/o Kotu Ram, H.No. 753/15-A, Faridabad.
2	Sihi	Gurgaon	3.4.95	10.5.16	Jeta Ram S/o Tikkam Ram, H.No. 711, Sector 13, U.E. Karnal.
3	do	do	1.3.95	1.4.8	Sant Dass S/o Hazari Lal, R/o 6/11, Alipur Road, New Delhi.
		<b>Grand Total</b>		<b>13.3.4</b>	
<b>17. District Faridabad</b>					
1	Rajpur	Palwal Khadar	16.12.95	2.1.15	Budh Ram S/o Maya Dass H.No. 632, Hospital Area, Nilokheri Distt. Hisar.
		<b>Grand Total</b>		<b>2.1.15</b>	

### **Six-Laning of G.T. Road**

**\*404. Sh. Om Parkash Jain:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state –

(a) whether six-laning work of G.T. Road within the Municipal limits of Panipat is in progress; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be completed?

**लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव):**

(क) पानीपत नगर पालिका की सीमा में जी.टी. रोड़ पहले हो छः मार्गा है:

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

### **Desilting of Safidon Drain**

**\*416. Sh. Ram Phal Kundu:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the Safidon Drain and Safidon Ditch Drain?

**मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल):** हां, श्रीमान जी। सफीदों ड्रेन तथा सफीदों डिच ड्रेन की गाद निकालने के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। इन कार्यों पर लगभग पांच लाख रूपये खर्च होंगे और यह कार्य जून, 1997 से पहले पूरे कर दिए जावेंगे।

### **Creation of Nuisance by Officers**

**\*412. Sh. Ashok Kumar:** Will the Finance Minister be pleased to state whether it is a fact that two officers of the Finance Department under the influence of liquor, manhandled an official of the Technical Education Branch of Haryana Civil Secretariat, Sector-8, Chandigarh on 19.2.1997 during the office hours, if so, the action taken against them?

**वित्त मंत्री (श्री चरण दास):** नहीं, श्रीमान जी, वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा दिनांक 19.2.97 को कार्यालय समय में या शराब के नशे में हरियाणा सिविल सचिवालय की सैकशन-8, चण्डीगढ़ में स्थित तकनीकी शिक्षा शाखा के किसी एक कर्मचारी के साथ बल प्रयोग नहीं किया गया। यद्यपि, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी और तकनीकी शिक्षा शाखा के कर्मचारी के बीच गर्मागर्मी हुई और मामले पर मैत्रीपूर्ण ढंग से समझौता हो गया।

**Kapil Muni Shrine, Kalayat**

**\*390. Sh. Ram Bhaj:** Will the Minister for Local Government be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to bring the Kapil Muni Shrine, Kalayat under the control of Kurukshetra Development Board; and

(b) whether there is any proposal to declare Kalayat as holy city?

**स्थानीय शासन मंत्री (डा. कमला वर्मा):**

(क) जी नहीं,

(ख) जी नहीं।

**Roads Constructed by H.S.A.M.B.**

**\*401. Sh. Ram Pal Majra:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the Market Committee-wise length of roads, if any, constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the State during the year 1996-97?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): वर्ष 1996-97 (28.2.97 तक) बनाई गई सड़कों का मार्किट कमेटीवार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

**1996-97 में (28.2.97 तक) बनाई गई सड़कों की लम्बाई की सूची**

क्रमांक	मार्किट कमेटी का नाम	1996-97 में बनाई गई लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3
1	अम्बाला कैट	4.18



2	बराड़ा	5.13
3	मुलाना	1.33
4	नारायणगढ़	4.12
5	भिवानी	2.50
6	जुई	1.42
7	सिवानी	7.00
8	होडल	1.10
9	पलवल	1.45
10	नूह	0.60
11	पुन्हाना	1.00
12	ताडू	1.00
13	आदमपुर	11.43
14	बरवाला (हिसार)	4.05
15	भूना	9.71
16	धारसूल	7.67

17	फतेहाबाद	20.26
18	हांसी	4.59
19	हिसार	8.84
20	जाखल	0.83
21	रतिया	1.90
22	टोहाना	4.94
23	उकलाना	9.21
24	जींद	1.00
25	पिल्लूखेड़ा	2.15
26	सफीदों	1.67
27	उचाना	4.00
28	चीका	7.16
29	ढाण्ड	5.13
30	पुण्डरी	3.49
31	कैथल	12.92

32	पाई	2.63
33	सीवन	6.22
34	घरौं डा	5.888
35	इन्द्री	5.40
36	जुण्डला	4.94
37	करनाल	2.38
38	कुंजपुरा	1.53
39	निसिंग	3.26
40	तरावड़ी	3.33
41	बबैन	5.62
42	पेहोवा	6.79
43	शाहबाद	14.788
44	थानेसर	6.62
45	असन्ध	4.50
46	पानीपत	0.75

47	कालका	2.88
48	बरवाला (पंचकूला)	1.41
49	झज्जर	0.78
50	डबवाली	4.92
51	ऐलनाबाद	1.71
52	कालांवाली	0.10
53	सिरसा	8.58
54	गन्नौर	0.99
55	सोनीपत	3.95
56	रादौर	5.35
	<b>कुल जोड़</b>	<b>256.98</b>
	अर्थात्	

**NBK Link Canal**

**\*347. Sh. Birender Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that the capacity of N.B.K. Canal has been reduced considerably;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to take up the matter with the Punjab Government for desilting the portion of the aforesaid canals falling within the territory of Punjab?

**मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल):**

(क) जी हां,

(ख) जी नहीं। नरवाना ब्रांच करनाल (एन.बी.के.) जोड़ नहर का कोई हिस्सा पंजाब के क्षेत्र में नहीं पड़ता है।

### **अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर**

#### **Providing Drinking Water**

**29. Sh. Om Parkash Jain:** Will the Minister for Public Health be pleased to state –

(a) whether it is a fact there is an acute shortage of drinking water in the colonies adjacent to the municipal limits of Panipat; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to meet the shortage of drinking water?

**जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ):**

(क) नगरपालिका की सीमा के साथ बसी कलौनियों में (परन्तु नगरपालिका की सीमा से बाहर) अभी तक पाईपड पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन कलौनियों में पीने के पानी

का प्रबन्ध स्वयं लोगों द्वारा निजी हैंड पम्प और कम गहराई वाले कुएं लगा कर किया गया है।

(ख) फिलहाल इन कालौनियों में पाईपड वाटर सप्लाई उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Appointment made by Haryana Agricultural University,  
Hisar**

**30. Sh. Ram Pal Majra:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the category-wise number of appointments made by Chaudhri Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar during the period 1<sup>st</sup> April, 1992 to 31<sup>st</sup> January, 1997 year-wise separately?

**कृषि मंत्री (श्री कर्म सिंह दलाल):** चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा एक अप्रैल, 1992 से 31 जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है।

**की गई नियुक्तियों की संख्या**

श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1.4.96 से 31.1.97
प्राध्यापक और समकक्ष	3	1	1	8	8

सह प्राध्यापक और समकक्ष	3	2	2	4	1
सहायक प्राध्यापक और समकक्ष	49	13	42	37	3
स्कूल अध्यापक				7	
उप कम्पट्रोलर				1	
श्रेणी-II			2		1
श्रेणी-III	49	20	22	13	
श्रेणी-IV	3	38			

**31. Sh. Jagdish Nayar:** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state the names and addresses of the persons to whom residential plots have been allotted by the HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (HUDA) in the State during the period 1<sup>st</sup> January, 1988 to to-date out of the Chief Minister's discretionary quota?

**Mr. Speaker:** Extension has been sought to reply this question, which has been granted. the communication received from the Minister concerned is as under:-

“Respected Speaker Sahib,

This is in reference to the unstarted Question No. 31, regarding discretionary quota plots allotted from 1.1.1988 onwards wherein names and addresses of all the allottees under the discretionary quota asked by Sh. Jagdish Nayar, M.L.A. It is requested that since the volume of the concerned information runs into the list of about 180 pages (i.e. 17000 photo copies), it will be very difficult to supply about the 90 copies. You are requested to give us more time for this purpose.

With regards,

(Siri Kishan Dass)

Prof. Chhattar Singh Chauhan,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha.

A Copy is forwarded to Secretary, Haryana Vidhan Sabha.

Sd/-

Town & Country Planning

Minister”

13.3.97

**श्री अध्यक्ष:** ऑनरेबल मैम्बरज, बजट पर डिस्कशन शुरू होने जा रही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डिस्कशन के लिए 7 घंटे का टाईम निर्धारित किया था लेकिन राज्यपाल महोदय



अभिभाषण पर 7 घंटे की बजाय 10 घंटे का समय डिस्कशन में लगा है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

एच.वी.पी.	170 मिनट
बी.जे.पी.	61 मिनट
समता पार्टी	167 मिनट
इंडियन कांग्रेस	130 मिनट
इंडिपेंडेंट	70 मिनट

जो 7 घंटे का टाईम फिक्स हुआ था वह इस प्रकार था।

एच.वी.पी.	165 मिनट
बी.जे.पी.	50 मिनट
समता पार्टी	110 मिनट
इंडियन कांग्रेस	60 मिनट
इंडिपेंडेंट	45 मिनट

आज बजट पर डिस्कशन शुरू होने जा रही है और उसके लिए 7 घंटे का टाईम निर्धारित किया गया है इसलिए आप 7 घंटे के टाईम को अपनी अपनी पार्टी की रेशो से विभाजित कर

लें । I request the leaders of the different parties to fix the time accordingly. Now, Sh. Om Parkash Chautala may speak.

### अभिकथित विशेशाधिकार का प्रश्न

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, कल हमने आपके समक्ष एक प्रिविलेज मोशन रखा था। इस सदन में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। जिस मुद्दे को लेकर कल इस सदन में चर्चा हुई वह पत्र आपको पढ़ कर सुनाया गया उसी ऑफिशियल पत्र को इन्होंने झुठलाने का प्रयास किया है।

**श्री अध्यक्ष:** मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि जो प्रिविलेज मोशन आपने दिया है वह मेरे ऑफिस में आ चुका है and that is under consideration.

**श्री भजन लाल:** अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि पार्टी वाइज मैम्बर्ज का समय अलॉट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी है उनके आधे से ज्यादा मैम्बर मंत्री हैं इसलिए जो मंत्री बोलेंगे वह टाईम तो इसमें से काट दिया जाए बाकि टाईम आप मैम्बर्ज में तकसीम कराएं ताकि मैम्बर्ज को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले। पहले भी ऐसी प्रथा रही है।

**श्री अध्यक्ष:** चौ. भजन लाल जी, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है लेकिन आपने अपने समय में ऐसा कभी भी नहीं किया।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष: बीरेन्द्र सिंह जी आप बैठ जाएं पहले मैंने चौटाला साहब को काल कर लिया है। इसके बाद आप बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो एक सबमिशन करना चाहता हूँ। मैं प्रिविलेज मोशन के बारे में कुछ नहीं कहता।

### वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा

**Mr. Speaker:** Hon'ble members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 1997-98 will take place. I request the leader of the opposition to speak.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: चौ. बीरेन्द्र सिंह जी यह कह रहे हैं कि वह प्रिविलेज मोशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते उनका तो कोई सुझाव है।

**Mr. Speaker:** Now the next item has started and I have requested you to speak on the Budget.

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मोहतबाना रिकवैस्ट करना चाहता हूँ कि इस सदन का कोई सम्मानित सदस्य विशेष रूप से कोई वरिष्ठ सदस्य अगर कोई उपयोगी बात कहना चाहे जिससे सदन व नए आए हुए सदस्यों को लाभ हो तो उनकी बात को आप सुनें। हो सकता है कि उस बात का आपको भी लाभ मिले। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी को हाउस का बड़ा तजुर्बा है।

**श्री अध्यक्ष:** चौटाला साहब, ये बड़े सम्मानित सदस्य हैं। इनको बड़ा अनुभव है। मैं इनके अनुभव का फायदा उठाता हूँ।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** हम मानते हैं कि आपको बहुत अनुभव है, हमें भी तो अनुभव से सीखना है। (विघ्न) हमें तो अपनी बात कहनी है। ये बीच में इन्ट्रूट न करें।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** यदि कोई \*\*\*\* बात कही जाएगी तो उस बारे में तो कहा ही जायेगा।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** ये हमारी बात को सुनें। जिस तरह ये बीच में इन्ट्रूट कर रहे हैं इनको हमारी बात नहीं सुहायेगी। यह मेरे अकेले का सवाल नहीं है। यह हरियाणा का बजट जनता के समक्ष रखा गया है।

**श्री अध्यक्ष:** झूठ शब्द को कार्यवाही से निकाल दें। I request you to please start speaking.

**श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी):** अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश का बजट 1 करोड़ 60 लाख लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता-जनार्दन के सहयोग और समर्थन से चुनी हुई सरकार अपने चुनावी घोशणा पत्र के मुताबिक जनता के किए गए चुनावी वायदे पूरे किया करती है और बजट के माध्यम से सारी जनात-जनार्दन के प्रति बजट की नीतियां सरकार का

परिचायक हुआ करती हैं। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय का अधिभाषण, वित्त मंत्री का बजट भाषण और सत्ता पक्ष पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को अगर गैर से देखा जाये तो तीनों का आपस में समन्वय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है यह बड़ा नीरस है, और विकास विरोधी है। अगर इस बजट के प्रति यह कहें कि यह बजट है ही नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा। बजट में यह दर्शाने का प्रयास किया जाना चाहिए था कि सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए क्या करने जा रही है। उसके मुताबिक सत्ता पक्ष की पार्टी ने जनता-जनार्दन से जो चुनावी वायदे किए थे उन चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए इसमें प्रावधान रखे जाते हैं और ऐसा लगता कि सत्ता पक्ष द्वारा हरियाणा प्रदेश की जनता के किए गए वायदों को पूरा किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर सत्ता पक्ष के चुनावी घोषणा पत्र पर निगाह डाली जाये तो आज सारे के सारे काम चुनावी घोषणा पत्र के उलअ किए जा रहे हैं। एच.वी.पी. पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों से चुनावी वायदे किए थे कि 24 घंटे बिजली दी जायेगी और सस्ती बिजली दी जायेगी। सत्तर सम्भालने के बाद सरकार ने बिजली के रेटस बढ़ा दिए और बिजली 24 घंटे की बजाए 4 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। उस बिजली को बढ़ावा देने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाते, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाता और लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाता, बजाए इसके जितने भी बिजली पैदा करने वाले स्रोत और साधन हैं उनको भी बेचने का निर्णय ले लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार बिजली का

निजीकरण करने जा रही है। जनता-जनार्दन की तरफ से दबाव पड़ा तो सुधारीकरण नाम लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले यह वायदा किया गया था कि हरियाणा प्रदेश की हर नहर के हर किनारे तक, हर छोर तक पानी पहुंचेगा, एस.वाई.एल. को 6 महीने में मुकम्मल किया जाएगा, भाखड़ा नहर के बैक्स को मजबूत किया जाएगा ताकि पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी चल सके, आगरा कैनल का कण्ट्रोल अपने हाथ में लेंगे। इसी प्रकार से यह वायदा किया गया था कि नई योजनाएं बनाएंगे, दादूपुर नलवी नहर निकालेंगे और गंगा का पानी हरियाणा प्रदेश में लाया जाएगा। आज प्रदेश में सिंचाई की हालत यह है कि सारे साधन समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश का किसान पूर्ण यप से बर्बाद हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले कर्मचारियों से बड़ वायदे किए गए थे, चुनाव से पहले व्यापारियों से वायदे किए गए थे कि टैक्सों का सरलीकरण किया जाएगा, उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस बजट का अगर बारीकी से देखा जाए तो सारे के सारे वायदे एक प्रकार से ढकोसले साबित हुए हैं तथा लोगों को गुमराह किया गया है। मैं बजट के समक्ष उन तथ्यों को उजागर करना चाहूंगा कि जिनसे सरकार की जनात विरोधी मन्शा स्पष्ट रूप से झलकती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजअ पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि रिवाईज्ड ऐस्टिमेटस में टैक्सों की आमदनी 300 करोड़ रुपये की रखी है जब कि बढ़ौतरी इससे

कहीं अधिक होनी चाहिए थी। लगभग 500 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी होनी चाहिए थी क्योंकि 340 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टैक्स लगाने के अलावा सरकार को कुद पैसा ऐसा भी मिला है या यों कह लें कि खुशकिस्मती से मिला है। 70 करोड़ रुपये चावलों की परचेज का टैक्स का बकाया था जोकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को मिला है। इनकी ओर से यह राशि 91 करोड़ बताई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको 70 करोड़ भी मान कर चलता हूँ। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर केन्द्रीय सरकार ने जो दाम बढ़ाए हैं उनकी वजह से हुई है। अध्यक्ष महोदय, 30 करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को लॉटरी से हुई है। लॉटरी पर 20 प्रतिशत की बजाए 7 प्रतिशत टैक्स किया गया है। यकमुश्त ड्रा से जो पैसा वसूल किया गया है उसकी वजह से 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सरकार को और हुई है। इसी प्रकार से कारों का इण्टर स्टेट सेल्ज टैक्स 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत बढ़ाए जाने की वजह से 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सरकार को और हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 350 करोड़ रुपये बताया है जब कि इनकी वास्तविक आमदनी 350 करोड़ रुपये जमा 150 करोड़ रुपये कुल 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, इस अतिरिक्त आमदनी के हिसाब से सरकार ने बजट में संशोधित अनुमानों के हिसाब से जो राशि रखी है उसके मुताबिक प्रशासनिक सुधार से जो आमदनी होनी

थी वह अतिरिक्त राशि की होनी थी। अध्यक्ष महोदय, जो आमदनी होनी चाहिए थी उसे भी 150 करोड़ रूपये कम वसूले गए हैं।

हविपा और भाजपा गठबन्धन सरकार ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान घोशणा की थी कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी। जब शराब बंदी का निर्णय सरकार ने लिया और प्रैस के लोगों ने तथा दूसरे लोगों ने पूछा कि यह जो आपके रैवेन्यू का नुकसान हो गया उसका आप कैसे पूरा करेंगे, तब मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल जी बड़े बलंग बांग दावे करते थे कि हम सरकारी खर्चों में कटौती करेंगे। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज किसी भी अन्य सरकार के मुकाबले इस सरकार के बढ़े हैं। जहां छोटी कैबिनेट बनाने की बात थी वहीं इन्होंने अपनी लड़खड़ाती कुर्सी को बचाने के लिए अठाईस नम्बरी एक बहुत बड़ी कैबिनेट बनाकर प्रदेश पर उल्टा खर्च का बोझ लाद दिया है। कटौती करने की बजाए खर्चा बढ़ाया गया है। ये विकास के कार्यों में राशि बढ़ाए जाने की बात किया करते थे और जनता को बड़े लुभावने नारे दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें 1996-97 के बजट अनुमानों में से भी नॉन-प्लान खर्चों में दो करोड़ और फालतु खर्चा किया है। यह तो इस सरकार की अपने चुनावी वायदों को निभाने की आस्था है। 1997-98 के नान-प्लान रैवेन्यू के खर्चों को असलियत से काफी कम दिखाया गया है जिसके कारण बजट में जो कटौती दिखाई गई है वह और अधिक बढ़ेगी। रैवेन्यू का खर्चा 1996-97



में 6043 करोड़ रूपए दिखाया गया है और 1997-98 में 7322 करोड़ रूपए दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, 7322 करोड़ रूपए में यदि रैवेन्यू खर्च में से थो (pay) रिविजन आदि के 628 करोड़ रूपए, लाटरी के 751 करोड़ रूपए और घटा दिए जाएं यानि सरकारी खर्च के और 751 करोड़ रूपए लाटरी के निकाल दिए जाएं तो 1997-98 में रैवेन्यू का खर्चा 5943 करोड़ रूपए बैठता है। 1996-97 का इसका खर्च 6043 करोड़ रूपए बैठता है और 1997-98 को 5943 करोड़ रूपए बैठता है। अध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ रूपए का फर्क रखा गया है। एक जुलाई से महंगाई भत्ते की किस्त, सालाना साधारण वेतन, वृद्धि वगैरह का कम से कम 250 करोड़ का इसमें प्रावधान नहीं दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, 350 करोड़ रूपए का घाटा अभी से इनके हिसाब से मान लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से इस सदन में भी और गवर्नर एड्रैस में भी इस सरकार ने दर्शाया है कि हम पे-कमिशन की रिपोर्ट ज्यों की त्यों लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पे-कमिशन की रिपोर्ट अगर ये लागू करते हैं तो हमें यह मान कर चलना चाहिए कि यह खर्चा और बढ़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह बजट दिखावे के तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की है असलियत में शुरू में ही यह बहुत ही घाटे का बजट दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस घाटे को कैसे पूरा किया जाएगा? कहां से पैसे आएंगे, कहां से साधन जुटाए जाएंगे? इस बारे में इस बजट में कतई कोई जिक्र नहीं किया गया है। बजट में पे-कमिशन की रिपोर्ट को लागू करना, 1 जनवरी 1997

के महंगाई भत्ते की किस्त देना तथा कर्मचारियों को 1995-96 के बोनस को देने के लिए 628 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार इस राशि में 423 करोड़ रुपये की राशि प्रोविडेंट फंड में जमा की जाएगी। जो 628 करोड़ रुपये कर्मचारियों को देने चाहिए उसमें से ये कहते हैं कि 423 करोड़ रुपये की राशि प्रोविडेंट फंड में जमा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर इतनी बड़ी राशि प्रोविडेंट फंड में जाम कर दी जाएगी तो कर्मचारियों को इसमें क्या मिलेगा और इस बात को कर्मचारी कैसे बर्दाश्त करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह तो लोगों की आंखों में पूरी तरह से धूल झोंकने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो सरकार ने बार-बार यह सिफारिश की कि पे-कमिशन की सिफारिश को भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार ही लागू किया जाएगा और अब जब कि भारत सरकार ने पे-कमिशन की सिफारिश को लागू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और अभी यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है तो इस अवस्था में हरियाणा सरकार द्वारा प्रोविडेंट फंड में 430 करोड़ रुपये की राशि रखा जाना सर्वथा गलत है।

वैसे भी अगर इतनी बड़ी राशि प्रोविडेंट फंड में डाल दी जाएगी तो इसे कर्मचारी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अतः इस मद के अन्तर्गत जो प्रावधान किया गया है वह सर्वथा तथ्यों के विपरित है और सरकार को इस मद में 250 करोड़ रुपये का घाटा पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में 160 करोड़ रुपये रैवेन्यू

डिपोजिटस बोर्डज और कोरपोरेशंज के नाम से रखे जाने का भी प्रावधान किया गया है। पिछले साल का ही 198 करोड़ रूपये बोर्डज और कोरपोरेशंज को देने का कोई प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है जबकि 160 करोड़ रूपये अगले साल यानि 1997-98 में ये बोर्डज और कोरपोरेशंज से और लेने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की क्लॉज 293 के तहत हरियाणा की सरकार किसी से भी चाहे कोई कारपोरेशन या बोर्ड हो, चाहे कोई व्यक्तिगत पार्टी हो, चाहे कोई और बैंक आदि हो, से अगर कर्जा लेगी तो उसको पहले भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसलिए हरियाणा की सरकार बोर्डज ओर कारपोरेशनज से कर्जा नहीं ले सकती। अगर यह सरकार ऐसा करती है तो यह संविधान की उल्लंघना है और लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए इन्होंने इसको कर्जे का नाम देने के बजाए इसे रैवेन्यू डिपोजिटस का नाम दे दिया है जबकि यह सरकार उनसे कर्जा लेने जा रही है। हम यह तो मान सकते हैं कि बजट पेश करने वाला हमारा साथी तो शायद इस बात से अनभिज्ञ है लेकिन मुख्य मंत्री तो लॉ ग्रेजुएट हैं, कर्ण सिंह दलाल ला ग्रेजुएट हैं तथा यहां और भी कई लॉ ग्रेजुएटस बैठे हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यू डिपोजिटस का मतलब यह होता है कि अदालत की तरफ से डिपोजिट की गारंटी ली जाती है कि अदालत के निर्णय के बाद इसको वापस लौटा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह कर्जा नहीं माना जा सकता। जिन बोर्डज और कोरपोरेशंज से सरकार ने कर्जा लिया है वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मार्केटिंग बोर्ड से

भी कर्जा लेने की बात कही गयी है। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजाब में मार्केटिंग बोर्ड जिस वक्त बनाया गया था उस वक्त इसके बनाने की मंशा यही थी कि जो मार्केट फीस के रूप में पैसा लिया जाता है वह कोई टैक्स नहीं है बल्कि वह पैसा किसानों की भलाई के लिए खर्च करने का निर्णय लिया गया था। मार्केटिंग बोर्ड के पैसे से किसानों के खेत से मंडी तक पहुंचने के लिए सड़कें बनायी जाएं, किसानों के ठहरने के लिए रैस्ट हाउसिज बनाए जाएं, किसानों के लिए मण्डियों में पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाए एवं उनकी दूसरी सुविधाओं के लिए यह पैसा खर्च किया जाए और उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं।

**कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर, अभी अभी आदरणीय चौटाला साहब बोर्डज और कारपोरेशंज के बारे में अपनी बात कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1987 में इनका अपना राज था तब इनके अपने सगे भाई स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एंव ऐक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, तब उन्होंने काफी विदेशी यात्राएं की थीं, तब यह कहां गए थे? अब यह हमारी कारगुजारी पर शक करते हैं लेकिन इनके अपने शासनकाल में क्या हुआ, वह इनको याद नहीं रहा। इनको अपने कामों को भी याद करना चाहिए। (विघ्न) आपन मेरी बात तो सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहूंगा कि उस दिन ये

कायदे कानून कहां गए थे जिस दिन इनका सगा भाई हरियाणा की जनता के खून पसीने की कमाई से विदेशों में घूम कर आया था और उस कॉरपोरेशन का भट्ठा बिठा दिया था।

**श्री बलवन्त सिंह:** अध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। वैसे भी जो सदस्य इस हाउस का मैम्बर न हो उसका नाम इनको यहां पर नहीं लेना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** भाई का जिक्र तो किया जा सकता है। (विघ्न) ऐसा है कि मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप यहां पर कंट्रोवर्सी पैदा करने का प्रयास न करें और आप स्मूथली काम करें।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह जिक्र किया था कि कोई ऑनरेबल मैम्बर यदि तकरीर कर रहा हो और कोई दूसरा मंत्री या सदस्य उसे यदि बीच में इंटरवीन करना चाहे तो उसके लिए स्पीकर महोदय आमतौर पर परमिशन देते हैं। Are you yielding? If you are not yielding then you will say let him continue. I would like to have minimum intervention. (Noise & Intervention).

**Mr. Speaker:** I will try my level best. Please sit down. दलाल साहब, आप बोलिए कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा। मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन ये

भाई अपनी तो सारी बात कह जाते हैं और वह सारी बात रिकार्ड पर आ जाती है और जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आता है तब तक भाई वाक आउट करके चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम इनकी बात सुनते हैं तो इन्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए।

**Mr. Speaker:** Constitutionally they have right to stage a walk out. आप जो कह रहे हैं वह भी रिकार्ड हो रहा है जो यह कह रहे हैं वह भी रिकार्ड हो रहा है। जनता के समक्ष आपकी बात भी जाएगी और इनकी बात भी जाएगी।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। सत्ता के जो लोग बैठे हैं इन्हें भी जबवा के समय अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा उसमें वे इस बात को कर सकते हैं बीच में बदमजगी पैदा होगी तो ठीक नहीं रहेगा। मैं वहीं बात आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ जो बजट में दर्शाई गई है। अध्यक्ष महोदय, 160 करोड़ रुपये का कर्जा इन्होंने बोर्डज और कारपोरेशंज से लेने का इसमें प्रावधान रखा है और ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड का जो ऐक्ट बना हुआ है \*\*\*\* कर्ण सिंह जी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं इन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** ओम प्रकाश जी ने जो यह दुर्भाग्य शब्द बोला है इसे रिकार्ड न किया जाए। (विध्न)

**11.00 बजे**

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, यह जो 160 करोड़ रुपये लेने का निर्णय इस सरकार ने किया है यह असंवैधानिक है। हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की परमिशन के बिना किसी से एक नया पैसा कर्जा नहीं ले सकती और उस बात को छुपाने के लिए इन्होंने कर्ज का नाम न देकर इसको डिपोजिट का नाम देने की बात की है। मार्केटिंग बोर्ड का जो पैसा है वह केवल किसानों की भलाई व बहबूदी पर खर्च हो सकता है लेकिन इस बजट की किसी मद में यह खर्च नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपनी नाकामी तथा तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है जोकि संविधान के आर्टिकल 293 के तहत बहुत ही इल्लिगल है, गलत है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरियाणा सरकार के पास 74 करोड़ रुपये के पुराने बॉड पड़े हुए हैं उनमें से 70 करोड़ के बॉड बेचने का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। प्रदेश की उस सम्पत्ति को बेचकर इस घाटे को पूरा करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से रवैन्यू खर्च 350 करोड़ रुपया कम दिखाया गया है और प्रोवीडेंट फंड का डिपोजिट 250 करोड़ रुपया दिखाया है जोकि ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, बोर्डज और कारपोरेशंज से गैर कानूनी डिपोजिअ का पैसा 160 करोड़ रुपये दिखाया गया है ट्रेजरी बिल को बचाने का जो सरकार इरादा रखती है वह है 70 करोड़ रुपया, कुल घाटा छिपाया गया है वह है 830 करोड़ रुपया और असली घाटा लगभग 880 करोड़ रुपये का है और बजट में 47.59 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वर्ष 1996-97 को खर्च 839 करोड़

रूपया है और 1997-98 का खर्च 834 करोड़ रूपया का दिखाया गया है। इसका मतलब है कि पांच करोड़ का नुकसान और हुआ है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई को देखते हुये इस मद में सरकार को कम से कम 950 करोड़ रूपये या एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान करना चाहिये था। इन्होंने 1997-98 के बजट में खर्च का जो प्रावधान दिखाया है वह 1996-97 के खर्च से भी पांच करोड़ कम है। इसका मतलब तो यह हुआ कि 1997-98 में प्रदेश में विकास कार्यों पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च करने का सरकार का इरादा नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि महंगाई के आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है क्योंकि 1997-98 का खर्च 1996-97 के खर्च से कम दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ती है और महंगाई का इंडैक्स जब आता है तो उससे हरियाणा प्रदेश में और प्रदेशों से ज्यादा महंगाई बढ़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार ने इस प्रकार के बिलडिंग मटीरियल पर 15 प्रतिशत टैक्स लगा दिए जिसके कारण ईट, सीमेंट और रोड़ी भी महंगी हो गई। इसी प्रकार से पेट्रोल पर सेल्स टैक्स अधिक बढ़पे से दूसरी चीजों के भाव भी बढ़ गये। इलैक्ट्रॉनिक्स गुडज, इवाइयां, कपड़ा और दूसरी चीजों की आज हालत यह है कि हरियाणा प्रदेश की बजाये दूसरे प्रदेशों में ये चीजें सस्ती मिलती हैं। इसका परिणाम यह निकला कि हमारे प्रदेश का व्यापार चौपट हो गया। जैसे कि टी.वी. अगर दूसरे प्रदेश से खरीदा जाये तो एक हजार रूपये सस्ता मिलता है। हमारे यहां पर टी.वी. एक हजार रूपये महंगा मिलता है सरकार के



रवैये से आमदनी नहीं हुई इस कारण हमारे दुकानदारों का कारोबार चौपट हो गया है यहां पर उपभोक्ता को हर चीज महंगी मिलती है और दाम निरन्तर बढ़ते चले गये हैं। इस प्रदेश की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्लान में पूंजीगत खर्च को आप देखें कि वर्ष 1996-97 का पूंजीगत खर्चा 483 करोड़ रुपये है और वर्ष 1997-98 में 643 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ल्ड बैंक से प्राप्त राशि, सड़क बनाने के लिए वर्ष 1996-97 में 20 करोड़ रुपये है तथा सिंचाई के लिए 123 करोड़ है और अगर यह राशि 483 करोड़ रुपये में से घटा दी जाये तो विकास कार्यों के लिए 343 करोड़ बचती है और 1997-98 में जो 643 करोड़ रुपये का प्रावधान है उसमें से अगर 342 करोड़ रुपये विश्वबैंक से प्राप्त सहायता की राशि आप घटायेंगे तो 301 करोड़ बनता है। अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत खर्च का जो प्रावधान 1997-98 के बजट में किया गया है वह 1996-97 के बजट से 42 करोड़ रुपये कम है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास, उद्योग, पर्यटन, बिजली बोर्ड और पंचायतों वगैरा के लिए पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष बजट में एक नया पैसा भी नहीं दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, विकास के काम कैसे होंगे जब बजट में एक नया पैसा भी नहीं दिया है जबकि राज्य वित्त आयोग की वर्तमान अध्यक्ष डा. कमला वर्मा जी हैं तथा पहले राजेन्द्र बिसला जी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष महोदय, एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। इससे कैसे काम चलेगा? डा. कमला वर्मा जी को तो इस बात का ज्ञान है। इन्होंने

तो 9 महीने से इस बोर्ड की देखभाल की है। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। इस सदन में प्रश्नों के उत्तरों में और सभाओं में विशेष रूप से झज्जर के उप-चुनावों में बड़ी-बड़ी घोशणाएं की गई थीं और कल भी अपने प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा था कि सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, कालेज बनाए जा रहे हैं और बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी को शायद अंधेरे में रखा गया होगा। इनको इस बात का ज्ञान नहीं रहा होगा। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञान नहीं है, वित्त मंत्री जी को भी ज्ञान नहीं है। इस सरकार ने इस प्रकार का बजट पेश किया है कि इसको किसी तरह से भी देखें लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में यह क्या है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की योजनाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पर वर्ष 1996-97 में 721 करोड़ रूपय का प्रावधान रखा था जबकि 1997-98 में इस मद में बजट में 741 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मात्र 20 करोड़ रू. से सारे वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होगा? बड़ी-बड़ी घोशणाएं की जाती हैं। आन दा फ्लोर आफ दि हाऊस और जनता में भी ये बड़े-बड़े वायदे करते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए प्रावधान सिर्फ 20 करोड़ रूपये का ही रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, दो नए कालेज और खोलने का प्रावधान है यह भी प्रावधान है कि नये टीचर्स कांट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती किए जा रहे हैं और इस प्रकार से शिक्षा को ठेके पर देने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई

बढ़ी है, तनख्वाहें बढ़ी हैं और अगर मुलजिमाओं की इन्क्रीमेंट का हिसाब भी लगाएं तो इतनी राशि बन जाती है। इस 20 करोड़ रूपए की राशि से शिक्षा का क्या सुधार होगा? इससे आप कौन-कौन से स्कूल अपग्रेड कर पाएंगे, कितने स्कूलों के कमरे बना पाएंगे। कॉलेजिज की तो बात ही छोड़िए। यह तो शिक्षा का स्तर है। मेरे ख्याल से शायद सरकार की यह सोच होगी कि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो वे नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे। चौ. बंसी लाल जी चुनाव से पहले बड़ी घोशणाएं करते थे कि हम सभी को रोजगार देंगे, गैस की एजेंसियां ओर पेट्रोल पम्पस देंगे। (विघ्न) लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी वजारत का कलमदान संभालने के बाद हर सरकारी दफतर में यह चिट्ठी लिखकर भिजवाई है कि दो वर्ष तक किसी भी विभाग में कोई नई भर्ती की जाएगी। यहां तक कि अगर कोई रिटायर हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होगी। इससे जाहिर होता है कि इस सरकार की मंशा क्या है? इससे इस प्रदेश की नई पीढ़ी शिक्षित नहीं हो सकती है। राम बिलास शर्मा जी बड़े बुलंदबांग दावे करते थे कि हम शिक्षा का सुधार करेंगे। लेकिन शिक्षा के सुधार के साथ ही साथ जब धूपबत्ती पर टैक्स की बचत की गई तो वे बड़ी तालियां बजाकर कह रहे थे कि मंदिर में खूब धूपबत्ती करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मंदिन के नाम पर ज्यादा दिन राजनीति करने का वक्त अब चला गया है। अब मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं बल्कि जनता-जनार्दन के हितों के लिए कुछ करने का प्रश्न है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद हरियाणा विकास पार्टी

वालों की सोच यह है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा हासिल किया जाए। इसलिए इनके विभाग से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चाएं चली हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो शिक्षाविद रहे हैं। साल में 20 करोड़ की राशि से कैसे शिक्षा का स्तर उठेगा? कितना पैसा, किस-किस मद में खर्च पाएंगे? इसी प्रकार से शहरी विकास की मद में 1996-97 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 52 करोड़ का खर्च दिखाया गया है जबकि 1997-98 के लिए इस में 37 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि 1997-98 के बजट में 1996-97 के बजट की तुलना में 15 करोड़ रु. का कम प्रावधान है। डा. कमला वर्मा जी बैठी हैं। कल वे बड़े लम्बे भाषण दे रही थीं। कमला वर्मा जी आप बताईए कि 37 करोड़ रु. से इस प्रदेश के 82 बड़े शहरों, 62 म्यूनिसिपल कमेटियों, बीस और अन्य एंव एक म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ऊपर क्या-क्या कर पाएंगे। अगर 82 शहरों को ही मानकर के चलें तथा 82 म्यूनिसिपल कमेटियों पर भी अगर खर्च करने की बात की जाएगी तो 37 करोड़ रु. से एक साल में कहां-कहां खर्च कर सकेंगे? अध्यक्ष महोदय, डॉ. कमला वर्मा जी कह रही थी कि हमने सरकार की तरफ से म्यूनिसिपल कर्मचारियों को सारी सुविधाएं प्रदान की दी हैं। हमने फैसला वापिस ले लिया। (विघ्न)

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** स्पीकर साहब मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात समाप्त हो जाए फिर ये बोल लें।

**श्री अध्यक्ष:** आप उनका प्वायंट ऑफ आर्डर सुन लें।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के बारे में पहले बात आ चुकी।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि चौटाला साहब शहरी विकास की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े देकर बजट की बात कर रहा हूँ।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद माना है कि बजट में शहरी विकास के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। ये अपने समय को भूल गए। ये अपने समय में कहा करते थे कि शहरों में रहने वाले लोग लुटेरे हैं, डाकू हैं इनका इलाज हरियाणा की जनता को करना चाहिए। चौटाला साहब अपने समय में यह कहा करते थे।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर चर्चा कर रहा हूँ। जिन-जिन मदों में जितनी-जितनी राशि का जो प्रावधान किया गया है मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मंत्री जी की तरफ से जो बिना वजह इन्ट्रप्शन है यह ठीक नहीं है। ये

जब चाहें प्वायंट ऑफ आर्डर रेज कर सकते हैं। इनको यह ज्ञान ही नहीं है कि प्वायंट ऑफ आर्डर क्या होता है। यह वैसे ही खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अर्बन एरिया के विकास के लिए 1997-98 यानि एक साल के लिए केवल मात्र 37 करोड़ रूपए का ही प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सरकार प्रदेश के 82 शहरों के विकास के नाम पर यह 37 करोड़ रूपया किस प्रकार से खर्च करेगी। मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी है कि इतने कम पैसे में यह सरकार शहरों का विकास कैसे करेगी। बहन कमला वर्मा जी कल कह रही थीं कि उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटीज के सारे कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया। हम सभी म्यूनिसिपल कमेटीज के सफाई कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को तनखाह दे देंगे। मैं कहता हूँ कि इस 37 करोड़ रूपए में आप उनसारे कर्मचारियों को तनखाह ही नहीं दे पाओंगे। यह उनके साथ फ्रॉड किया गया है। यह हरियणा की जनता के साथ फ्रॉड किया गया है। प्रदेश के 82 शहरों में बसने वाले करोड़ों नागरिकों के साथ फ्रॉड किया गया है। यह सरकार उन गरीब कर्मचारियों को तनखाह कहां से देगी जो स्टेट के सबसे निचले सतर के लोग हैं और वे बाल्मिकी समुदाय के लोग हैं। उन्होंने शहरों की सफाई करने का काम किया था और उन्होंने शहरों में बसने वाले लोगों को जीने का अवसर प्रदान किया था। वे लोग अपनी मांग को ले करके आन्दोलित हुए थे। उन पर लाठियां बरसाई गई थीं उनको डिसमिस किया गया था और उनको जेलों में डाला गया था। इसी बिनाह पर दूसरे विभागों के

सारे कर्मचारी आन्दोलित हुए थे। अध्यक्ष महोदय, इस 37 करोड़ रूपए से तो उन सारे कर्मचारियों को तनखाह भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनका आन्दोलन फिर भड़केगा। उससे हरियाणा प्रदेश का सारा वातावरण पूर्ण तौर पर खराब हो जाएगा।

**स्थानीय शासन मंत्री (डा. कमला वर्मा):** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंअ ऑफ आर्डर है चौटाला साहब यह तो कह सकते हैं कि यह 15 करोड़ रूपया कम कैसे खर्च किया जाएगा लेकिन उन हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के साथ हमने जो समझौता किया उसके बारे में चौटाला साहब आप चर्चा मत करें।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी से जानना चाहता हूँ कि सही स्थिति कौन सी है। बहन जी कल बता रही थीं कि उन सफाई कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को तनखाह दे देंगे तो क्या आप 15 करोड़ रूपए कम होने के बावजूद उनको तनखाह दे पाएंगे। एक साल में एक कर्मचारी की एक इन्क्रीमेंट लगती है उनको मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है उनको इतना पैसा आप इस 15 करोड़ रूपए से कैसे पूरा कर पाओंगे।

**डा. कमला वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग अपने खर्चे कम करके, अपने रिसोर्सिज से पैसे कमाएगा। जो 15 करोड़ रूपया है यह शहरों के विकास के लिए है। आप इस तरह से जनता को गुमराह मत करें।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, बहन कमला वर्मा मंत्री हैं और शायद हर वजारत में मंत्री रही हैं। हरियाणा सरकार के जितने सोर्सिज होते हैं वे सोर्सिज तो इन पोथों में होते हैं। इस बजट में दर्शाए जाते हैं। आमदनी और खर्च का सारा लेखा जोखा इन पोथों में है। इन्हीं पोथों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। 15 करोड़ रूपए बजट स्पीच में लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस 15 करोड़ रूपए से प्रदेश के 82 शहरों में की डिवैल्पमेंट कैसे कर पाएंगे? उन सारे कर्मचारियों को तनखाह कैसे दे पाएंगे? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा और अर्बन डिवैल्पमेंट पर अंकुश लगा दिया क्योंकि चौ. बंसी लाल जो बी.जे. पी. से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। बहन जी आप लोगों में जाकर क्या कहेंगी जिन लोगों से आप वोट लेकर यहां आई है, अब आप जाओ उन लोगों के पास। क्या आप उनको 15 करोड़ रूपए में तनखाह दे पाओंगे और क्या आप 20 करोड़ रूपए में हरियाणा प्रदेश को शिक्षित कर पाओगे? इस बात को बड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि किसी भी मद को उठाकर देख लीजिये, किसी भी मद में हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय बजट होता है प्रदेश को दिशा देने के लिए। उसमें सुझाव दिए जाते हैं कि इस प्रकार के विकास होंगे, फलां वर्ग के लोगों को फलां सुविधा दी जायेगी। आज व्यापारी वर्ग का व्यापार चौपट हो गया है। उन पर टैक्सों की बेइन्तहां मार मार दी गई



है। अध्यक्ष महोदय, टैक्स लगाते वक्त इनको ज्ञान नहीं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इन्होंने टैक्स लगाया जिसका परिणाम यह निकला कि पेट्रोल मिलना शुरू हो गया और सरकार के खजाने में जो रवैन्यू बढ़ना चाहिए था वह बढ़ने की बजाये घट गया। अध्यक्ष महोदय साथ लगती 5 स्टेट्स के लोग तेल लेकर चले हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार को 25 करोड़ रुपये का तो वैसे ही मुनाफा हो गया था जब केन्द्र सरकार ने दरों को बढ़ा दिया था फिर इनको सेल्ज टैक्स बढ़ाने की क्या जरूरत थी। अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी कोई अन्दरखाने बातचीत हो गई उनको टैक्सों में रियायत करने की बात की गई है लेकिन जहां कोई लाभ नहीं मिल पाता था वहां टैक्सों की बात नहीं की गई। गरी आदमी पर टैक्सों की मार की वजह से आज महंगाई आसमान को छूती जा रही है। महंगाई बढ़ी है अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश, जिस प्रदेश का नाम विश्व के स्तर पर हुआ करता था, हिन्दुस्तान के मानचित्र पर पहले नम्बर पर होता था, हरियाणा की सड़कें अच्छी होती थी, हरियाणा की बसें अच्छी होती थीं, वहीं आज हरियाणा प्रदेश में सड़कों को टांकी भी नहीं लग पा रही। यहां पर बिहार की तरह सड़क छोड़कर नीचे चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। (विघ्न) ये फिर बीच में क्यों बोलते हैं, यह समझ में नहीं आता। अगर किसी ने कोई बात कहनी है वह अपने रिकार्ड में कह देगा।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** आन ए प्वायंट आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विपक्ष के नेता चौ. ओम प्रकाश चौटाला साहब ने यह स्वयं माना है कि यह वही हरियाणा है जहां गांवों गांवों में सड़कें हुआ करती थीं, बिजली हुआ करती थी और कितनी नहरें बना करती थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि ये उस नेता का नाम भी बता दें जिन्होंने गांव गांव में सड़कें, नहरें और बिजली पहुंचाई। अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल के अपने कारनामों को इस हरियाणा प्रदेश की जनता और इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। इनके मुंह से कम से कम विकास की बात अच्छी नहीं लगती। इनके शासनकाल में चौ. बंसी लाल जी के जमाने में खरीदी हुई बसों को फुंकवाया जाता था, आग लगवाई जाती थी। (विघ्न) स्पीकर सर, चौटाला साहब को याद होगा कि 1987 में उनकी सरकार थी। हमारी सरकार पर तो इल्जाम लगा रहे हैं जरा ये अपने दिनों को भी याद करें मैं बताना चाहता हूं हरियाणा के शहरों की जो सम्पत्ति थी इस प्रदेश की जनता की जो जायदाद थी, सरकार का खर्च चलाने के लिए उसको ये खुले चौराहे पर नीलामी करवाया करते थे।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यह किस प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** देखिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे किसी प्रकार की कोठ कन्ट्रोवर्सी पैदा न करें और इस टैन्डेंसी को एवाइड करें।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, ये हमारा समय खराब कर रहे हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अगर इन्होंने सम्पत्ति की नीलामी न करवाई हो तो बता दें।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** जवाब कोई हो तो देंगे। (विधन) अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसी लाल जी ने यह कह कर वोट लिए थे कि मैं हरियाणा का निर्माता हूँ। मैंने हरियाणा क बहुत से विकास के काम किए हैं और अभी कर्ण सिंह दलाल ने और कई साथियों ने अपनी बात में कहा था कि चौ. बंसीलाल जी आपने हरियाणा प्रदेश का निर्माण बहुत किया है। अब हरियाणा प्रदेश का फिर स निर्माण करने का अवसर आपको मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़कों का जिक्र किया गया हे यह केन्द्र की सरकार की मदद से बनी थीं। इसके लिए पैसा केन्द्र सरकार से आया था। अध्यक्ष महोदय, यह जो विकास करने का काम हुआ था इसमें कमीशन खाया गया था। अध्यक्ष महोदय, हर गावं को इलैक्ट्रीफाई करने का जो निर्णय लिया गया था उसके बारे में ए. जी. की रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि इसमें कमीशन खाया गया था। अध्यक्ष महोदय, जिस एस.वाई.एल. नहर को छः महीने में

बनाने की घोशणा की बात की जाती है, हरियाणा प्रदेश की बाउंडरी में जो नहर बनाई गई वह इसलिए बनाई गई थी कि इसमें कमीशन खाया जाये। हरियाणा के हिस्से में जो नहर बनाई गई वह इसलिए बनाई गई थी कि इसमें कमीशन खाया जाये। हरियाणा के हिस्से में जो नहर बननी थी वह तो बनवाई गई लेकिन पजाब के हिस्से में यह नहीं बनवाई गई थी (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि विकास के नाम पर आज हरियाणा प्रदेश पूर्ण रूप से बरबाद हो गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए मैं विपक्ष के तौर पर ऐसी बात कहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हरियाणा प्रदेश के सम्मानित सदस्यों, जो कि हरियाणा प्रदेश की जनता में से चुनकर आए हैं, यह कहना चाहता हूँ कि वे सभी जनता के हित की बात कहें। आज हरियाणा प्रदेश की एक करोड़ साठ लाख जनता के हम प्रतिनिधि हैं आज प्रदेश की जो भयावह स्थिति हो गई है हमें इस बारे में सोचना होगा कि किस प्रकार से हम पूरे प्रदेश को इस स्थिति से उबारेंगे। प्रदेश की हालत आज बद से बदतर हो रही है। आज सरकार के पास पैसा नहीं है पता नहीं इस सरकार का काम सारा साल कैसे चल पाएगा। पे—कमीशन की रिपोर्ट जब लागू करेंगे तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? स्पीकर साहब, इन हालत में मेरा एक सुझाव है अगर ट्रेजरी बैंचिज के लोग उस सुझाव को मान लें। इसका एक ही रास्ता बच जाता है कि लॉटरी को बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए इन सारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लॉटरी की टिकटें दे दी जाएं ताकि वे उन

टिकटों को बेच कर अपनी तनख्वाहें पूरी कर लें मुझे और तो कोई साधन इसका दिखाई नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में कहीं पर विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी कल ही यहां पर हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षार्थ एक सामूहिक निर्णय लिया गया था जिस की सारे प्रदेश की जनता ने सराहना की है। आज हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है इसलिए हमें इस पर भी कोई सामूहिक फैसला लेना चाहिए। हमें यह फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमने हरियाणा प्रदेश के लिए लड़ाईयां लड़की हैं इसलिए हरियाणा प्रदेश को बरबादी से बचाने के लिए गहराई में जाकर बारीकी से सोचना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। हमें बहुत सूझ-बूझ के साथ कोई निर्णय लेना पड़ेगा कि यह प्रयास कैसे किया जा सकता है। किस प्रकार हरियाणा प्रदेश का विकास हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह थोथा, बोगस और नीरस है। इस बजट में केवल यह दिखाया गया है कि किस मद पर खर्च किया जाएगा यह खर्च कहां से और किस प्रकार से पूरा किया जाएगा इस बारे में इस बजट में कुछ नहीं दिखाया गया है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, केवल मैं ही इस बजट का विरोध नहीं कर रहा हूं जब इस बजट पर वोटिंग होगी तो इस बजट को प्रस्तुत करने वाले महानुभाव खुद भी इसके खिलाफ वोट देंगे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह जो बजट पेश किया गया है यह हरियाणा प्रदेश के हितों के रक्षार्थ नहीं है इसलिए इस बारे

बड़ा सोच-समझ कर निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं अपने लायक मंत्री श्री राम बिलास जी से कहना चाहूंगा कि लच्छेदार भाषण देने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है इस बारे में सोचें और सर्व-सम्मति से कोई फैसला लें केवल सत्ता और कुर्सी का सुख भोगने के लिए हरियाणा प्रदेश को बरबाद न होने दें। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजअ का विरोध करूंगा तथा मुझे बोलने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री बीरेन्द्र सिंह** (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। विपक्ष के नेता ने बजअ पर चर्चा का आगाज करते हुए आरम्भ में ही इस बजट को नीरस और प्रगतिहीन बजट बताया है। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस बजअ से मुझे यह लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सरकार को चलाने में है, प्रगति के काम करने में सरकार की कहीं दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सेठ साहुकार दिवाली के मौके पर लाभ हानि का हिसाब लक्ष्मी के सामने बैठकर करता है और अगले साल का काम शुरू करता है। इस बारे में वह बाहर किसी को बताने नहीं जाता कि उसे उस साल में कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ (विघ्न) अगर इस बजअ को भी उसी दिशा में लिया तो यह प्रजातन्त्र प्रणाली द्वारा स्थापित राज्य सरकार का बजट नहीं है बल्कि यह बजट ऐसा है जिसमें कोई चमक नहीं है।

तो इस बजट को 31 मार्च को पास करने की प्रथा की बजाए दिवाली को पास कर लिया जाए। मैं इस बात के लिए आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय 1996-97 का एनुअल प्लान आउट ले 1930 करोड़ रूपए था उसके बाद उसको घटाकर रिवाईज प्लान आउट ले 1372 करोड़ रूपए का हुआ। इसके बाद इस सरकार के आने के बाद जो प्लान आउट ले आया वह 1997-98 को 1575 करोड़ रूपए का दिखाया गया है। This outlay is approximately 15% higher than the plan outlay of Rs. 1372.75 crores for the last year 1996-97. अध्यक्ष महोदय, 15 प्रतिशत की इन्क्रीज इस प्लान आउट ले में है और दूसरी तरफ स्टेट के आंकड़े तथा पिछले दिनों में महंगाई का इन्डैक्स आया वह 13.4 प्रतिशत टच कर गया। (विधन)

**मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल):** यह 13 प्रतिशत कब का है।

**डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। यह जो 13 प्रतिशत है वह नवम्बर महीने तक की है अब तो यह 15 प्रतिशत भी हो सकता है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने खुद कहा है -

“The rate of inflation, both at National and the State level, continued to rise. The All India Working Class Consumer Price Index (Base 1982=100) increased by 8.9 percent from

293 in March, 1995 to 319 March, 1996. It further rose to 9.4 percent to 349 in November, 1996. Similarly the Haryana State Working Class Consumer Price Index (base 1982=100) increased from 270 to 284 between March, 1995 and March, 1996 recording a rise of 5.2 percent. It further rose to 322 in November, 1996 registering an increase of 13.4 percent.”

मेरे कहने का अभिप्राय: है कि यह बजट इसी सरकार की कार्यवाही नहीं है यह सभी सरकारें करती आई हैं। जब भी बजट आता है तो वित्त मंत्री जी को एक-डेढ़ महीने पहले ही साउंड कर दिया जाता है कि आपकी कोई प्रयोरिटी किसी स्कीम को बदलने की हो, किसी स्कीम को बूस्ट करने की हो, उसको रिडंडेंट करना हो, डिसकंटीन्यू करना हो तो बताएं। लेकिन कभी भी प्रान्त सरकार का काबिना यह बैठकर नीति तय नहीं करता है कि कौन कौन सी स्कीमज हैं जिनकी देश को जरूरत नहीं है, कौन-कौन सी स्कीमज हैं जिनको लिफ्ट करने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 1986 में मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस समय वहां एक साल का पावर सैक्टर में 900 करोड़ रूपये का प्रावधान था लेकिन उन्होंने एक साल में उसको 9000 करोड़ रूपये कर दिया था ताकि पावर क्राईसिस को समाप्त किया जा सके, बिजली की कमी को थोड़े समय में ठीक ढंग से समाप्त किया जा सके। तो इस तरह से आप भी अपनी प्रायोरिटी निर्धारित कीजिए और आज जो एक ढर्रा बन गया है कि उन्हीं स्कीमज के तहत पैसा आता रहा जिनकी अब जरूरत नहीं रह गयी है, को बंद कीजिए। इसी बजट में जो प्लान आउट ले



का हिस्सा था उसको नोन प्लान में शामिल कर दिया गया। उस पर 104 करोड़ रूपये का प्रावधान था। अध्यक्ष महोदय, इसमें ही अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको कितनी ही ऐसी स्कीम्ज मिलेंगी जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है और जिनको अब डिसकंटीन्यू कर देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रदेश के अन्दर विकास चाहते हैं तो आपको इन बातों पर सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे नहीं पता कि प्लानिंग मिनिस्टर कौन है। शायद आज एक सिस्टम बन गया है कि जो फाईनैस मिनिस्टर होगा वही प्लानिंग मिनिस्टर भी होगा। लेकिन आज यह हमारा बहुत जरूरी अंग हो गया है इसलिए इस सारे प्लान की स्टडी की जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कई स्कीमों के बहुत से पैसे को आप डायवर्ट कर सकते हैं इन स्कीमज की अब इस प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है। यह पैसा उन मदों पर खर्च किया जा सकता है जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बजट बनाने की प्रक्रिया है इसको बदला जाना चाहिए। अभी मुख्य मंत्री जी तीन दिन पहले जब गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर अपना जवाब दे रहे थे तब इन्होंने माना था कि मैं यह चाहता हूँ कि हमारा कोई भी काम हो उसमें ट्रांसपियरैन्सी हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आज के संदर्भ में और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ मल्टी नेशनल कम्पनियों के साथ, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौता करते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता

हूँ कि पारदर्शिता सिर्फ समझौतों में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि सरकार के जो डेली के काम काज हैं, उनमें भी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अभी दो दिन पहले इन्हीं के नेता चौ. भजन लाल जी कह रहे थे कि आईजनबर्ग के साथ जो एम.ओ.यू. पर समझौता हुआ था उसके तहत उनसे पावर लेनी चाहिए। अगर हम उस एम.ओ.यू. के आधार पर कोई भी पावर प्रोजैक्ट लेते हैं तो उसको भी डाउट की नजर से ही देखा जाएगा। मैंने उसी वक्त इसका जवाब देते हुए कहा था कि हम तो ग्लोबल टैंडर मांगेंगे और जिसकी कंडीशन हमें ठीक लगेगी तथा स्टेट के भले में जो टैंडर होगा, उसका ही हम टैंडर लेंगे। उस एम.ओ.यू. के बारे में चौ. बीरेन्द्र सिंह जी की क्या राय है?

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** मेरी राय को तो मुझे पता नहीं है। मुझे किसी अधिकारी ने यह बताया था and it was veyr surprising for me that Eisenberg Company which has signed MOU with the Haryana Government is a company, which manufactures toys. इस बात में कितने तथ्य हैं मैं नहीं जानता। मुझे बता रहे हैं कि वे टॉयज बिजली से चलने वाले होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके किसी भी मंत्री ने अपनी किसी भी स्कीम के बारे में अपने-अपने

महकमों के साथ बैठकर उस पर पूरा अध्ययन किया हो और फिर उसके बाद वे स्कीम्ज फाईनेंस डिपार्टमेंट को भेजी हों तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह सबसे बड़ी ट्रांसपियरैन्सी है। कोई भी मंत्री यह कह दें कि मैंने एक-एक स्कीम को अपने महकमे के साथ बैठकर उसकी बॉयलिटी को, उसकी रैलेवैन्सी को स्टडी किया है और उन स्कीम्ज में यह यह मेजर तरमीम की हैं, तो मैं ट्रांसपियरैन्सी की बात को मान लूंगा।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर हम हर प्रोजैक्ट के बारे में पूरी तरह से सोचते हैं और अफसरों के साथ मीटिंग भी करते हैं तथा जो इस तरह की हमारी स्कीम्ज आती हैं हम करीब-करीब हर बड़ी स्कीम को या मीडियम स्कीम को कैबिनेट में डिसकस करते हैं जिसमें मंत्री भी होते हैं सीनियर आफिसरज भी होते हैं, वे माईनर चेन्जिज करते हैं व मेजर चेन्जिज भी करते हैं। (विधन) बीरेन्द्र सिंह जी आपके नेता आइजनबर्ग की बात कह रहे थे कि वहां से बिजली लो, काफी सस्ती पड़ेगी लेकिन आइजनबर्ग की उस कम्पनी न आज तक बिजली के प्रोजैक्टस नहीं लगाए। यह सही बात है। (विधन)

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने माना है कि 600 करोड़ रूपया साल का शराबबंदी की वजह से हरियाणा सरकार के ऐक्सचैकर में कम आएगा। दूसरे, आपने इसी बजट में माना है कि पांचवे वेतन आयोग की रिक्मेंडेशन को मीट विद करने के लिए 628.60 करोड़ का प्रावधान किया है उसके

लिए साधन जुटाने की कोशिश भी की है लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ा ऐतराज यह है कि आपने लिखा है –

“Our Public Sector Undertakings should not lag behind in contributing towards financing State’s plan schemes. We expect financial support of Rs. 80 crore from our Public Sector Undertakings during 1997-98.”

चौटाला साहब ने भी जिक्र किया है कि जो हमारे दो-तीन अदायरे हैं जो कि फायदे में हैं यानी फायदे में नहीं तो उनके साधन अच्छे हैं उसमें मार्किटिंग बोर्ड, हैफेड व हुड्डा ये तीनों ऐसी संस्थाएं हैं। परन्तु सरकार दूसरे ऐसे अदायरों की ओर देखती है कि जहां सरप्लस पैसा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो बैंकिंग सिस्टम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, दूसरे वर्ल्ड ओरगेनाइजेशन से लोन लेने के लिए स्टेच्यूटरी बांडी फ्लोट करते हैं ताकि आप कहीं से लोन ले सकें, वर्ल्ड बैंक से सहायता ले सकें और दूसरी तरफ आप उस पैसे को अपनी ट्रेजरी में रखते हैं क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, इन दोनों बातों में विरोधाभास है। चौ. जसवंत सिंह बता रहे थे कि जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था उस समय बिजली बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं थी एक डिपार्टमेंट ऑफ पावर वह काम करता था जो आज हरियाणा और पंजाब के बिजली बोर्ड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेजरी अकाउंट को ठीक करने के लिए उन अदायरों को अपने में शामिल करना चाहते हैं और इस सरकार का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उनकी स्टेच्यूटरी बॉडी के नाम से

पलोट मत कीजिए। अगर उनको स्टेच्यूटरी बॉडी में रखना है तो अलग से रखिये उस पैसे को आप सरकार के अकाउंट में शामिल मत कीजिए क्योंकि ये दोनों बातें आपको और हरियाणा की जनता को भ्रम में डाल देंगी। इसकी एक वजह है और वह यह है कि आज तक किसी कारपोरेशन ने, किसी बोर्ड ने सरकार को पैसा लेकर वापिस नहीं किया है चाहे वह बिजली बोर्ड हो, हुड्डा हो या हैफेड हो। इस तरह की जो रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन ऐजेंसीज हैं वे कंप्लेमेंट होती हैं, वे सोचती हैं कि सरकार का 100-200 करोड़ रूपया अगर वापस नहीं किया तो क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री महोदय ने पहले सत्र में जब इस नई सरकार की विधान सभा चुनकर आई थी तो उसमें यह आश्वासन दिया था कि मैं एक रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन कमेटी का गठन करूंगा और वह कमेटी सुझाव देगी कि हरियाणा में कहां से हम ऐसे संसाधन जुटा सकते हैं जिससे, हम 600 करोड़ रूपये का घाटा और 628 करोड़ रूपया फिफथ पे-कमीशन के लिए यानि 1228 करोड़ रूपया का घाटा पूरा कर सकें और उस पैसे को स्टेट एक्सचेकर में डाल सकें। आपने कमेटी का गठन किया हमें उस कमेटी की परफोरमेंस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एक बात में जरूर कहना चाहूंगा कि वह कमेटी नहीं थी जो हरियाणा के लोगों की भावनाओं के मुताबिक आपके संसाधन इकट्ठा करने की सलाह दे सकती। वह कमेटी उन अफसरों की थी जिनका अपना एक सिस्टम है, ढर्रा हे और उस ढर्रे से आगे की वे सोच नहीं सकते। आपने वह कमेटी चीफ

सैक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर (फाईनेंस), एक्सार्इज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, सैक्रेटरी, एक्सार्इज एंड टैक्सेशन इन चार आदमियों की कमेटी बनाई। इस कमेटी में आपने कोई भी जन प्रतिनिधि शामिल नहीं किया। हम तो ये कहते थे कि आप सदन के सदस्यों की कमेटी का गठन करें और उस कमेटी में आप इन अफसरों को भी जोड़ सकते हैं। उस समय हरियाणा के तत्कालीन वित्त मंत्री सेठ किशन दास, जो अब आबकारी मंत्री है ने आंकड़े प्रस्तुत किए जिनमें कहा गया है कि 1250 करोड़ रुपये के बदले हम 1600 करोड़ रुपया का कलेक्शन करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर हरियाणा के कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकार की नीयत साफ हो और अगर ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो तो मैं दावा करता हूँ कि 1600 करोड़ रुपये की बजाए हरियाणा में 3200 करोड़ रुपये का टैक्स इकट्ठा हो सकता है क्योंकि टैक्स कलेक्शन में हर जगह लूप होल्स हैं। (विध्न)

**श्री बंसी लाल:** आप हमें एक नोट दे देना हम बैठकर डिस्कम कर लेंगे यह तो बहुत बढ़िया बात है और हमारे भले की बात है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ कि करों की कितनी चोरी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे 30 वर्ष हरियाणा को बने हुए हो गए हैं। इस बीच कई मुख्य मंत्री आए और कई सरकारें आईं। हर मुख्य मंत्री तथा हर सरकार ने अपने-अपने हिसाब से किसी टैक्स अथवा सेल्ज टैक्स की रिड्यूस

कर दिया, किसी टैक्स को अबोलिश कर दिया और यह कहकर किया कि यह हरियाणा प्रदेश के हित में है। इससे ज्यादा टैक्स आएगा। पीछे 3-4 महीने पहले सेठ श्री कृष्ण दास ने भी ऐसा ही किया। हरियाणा में इनकी अकेली फ़ैक्टरी है तथा इन्होंने अपनी फ़ैक्टरी का टैक्स 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया। (विघ्न)

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी में घटाया गया है। जब यह टैक्स घटाया गया था इससे पहले ही इनकी फ़ैक्टरी तो जल गई थी तथा 6 महीने से चालू नहीं हुई है। यह फ़ैक्टरी भी इनकी नहीं है, इनके लड़ने की है। दूसरे, इन्होंने जिन्दल स्ट्रिप्स लि. का जिक्र किया था। इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इससे हम को 3 गुना ज्यादा टैक्स एक महीने में आया है। (विघ्न) लेकिन कानूनी तौर पर अगर ये प्रत्येक कन्साईनमेंट सेल बाहर कर दें अर्थात् दूसरे प्रदेशों में कर दें तो हम को कोई पैसा टैक्स का नहीं मिलेगा। लेकिन यह हम ने इस कंडीशन पर किया है कि माल की सेल वे हरियाणा से दिखाएंगे जिससे कि हमें फायदा हुआ है।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** मुख्यमंत्री जी मारुति कार का इंटर-स्टेट टैक्स एक प्रतिशत से बढ़ाकर आपने 3 प्रतिशत कर दिया तो उससे 25 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने से

भी इजाफा हुआ है। यह फाईनैस की बातें शायद हमारी समझ में न आती हों।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, फाईनैस की बात तो मेरे से ज्यादा चौआला साहब समझते हैं। मैं फाईनैस के मामले में इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह सकता हूँ कि कल को अगर मारूति वाले भी चाहें तो अपना माल दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं जिससे हो सकता है कि एक पैसा भी कन्सार्इनमेंट टैक्स का हमें न मिल सके। लेकिन उनसे हमने समझौता किया है तथा बैठकर बातचीत की है। उसके बाद हमें एक-एक कर के टैक्स बढ़ाए ताकि हमारी आमदनी बढ़ सके। वरना एक जमाना ऐसा भी था कि ये मारूति के लिए पता नहीं कितना शोर मचाते थे। ये तो पता नहीं क्या-क्या कहेंगे।

**डा. बीरेन्द्र पाल अहलावत:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बताया तथा मंत्री जी उपस्थित हैं, जिनकी यह फ़ैक्टरी है, उन्होंने भी बताया था कि टैक्स घटाने से तीन गुना रैवेन्यू बढ़ गया जबकि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 6 महीने से यह फ़ैक्टरी बंद है तो प्रोडक्शन कहां से हो गई अर्थात् इतना कन्सार्इनमेंट एकदम कैसे पूरा कर दिया गया।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है। ये कहीं की बात कहीं करते हैं।



सेठ सिरी किशन दास: इस बारे में तो जिन्दल स्ट्रिप्ट लि. का जिक्र किया गया था।

**Education Minister** (Sh. Ram Bilas Sharma): Deputy Speaker Sir, this is debate on Budget. Sh. Birender Singh is on his legs. उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल नहीं है। चौटाला साहब व वीरेन्द्र पाल जी हमने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अगर इनको कुछ कहना है तो बजट स्पीच में कह लें। (विघ्न)

डा. बीरेन्द्र पाल अहलावत: उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि 4 प्रतिशत से एक प्रतिशत टैक्स करने पर भी 3 गुणा कैसे बढ़ गए यानि कि 12 प्रतिशत कैसे हो गए? पहले तो टैक्स की चोरी थी। यह एकदम कैसे बढ़ गए?

श्री बंसी लाल: उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का जवाब मैंने दे दिया है। लेकिन इनकी समझ में आया हो तो इनको पता लगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि इन तीन सालों में इस किस्म की कन्सैशन के अंतर्गत सेल्ज टैक्स में रिडक्शन हुई है या किसी कोमोडिटी पर सेल्ज टैक्स अबोलिश किया गया है। इस बारे में मैं चाहता हूँ कि पूरे तीस साल के लेले-जोखे के बारे में सरकार एक श्वेत पत्र इशू करे। मैंने जो ट्रांसपेरेंसी की बात की थी वह यही पर आकर के लागू होती है। श्वेत-पत्र इशू होना चाहिए ताकि हरियाणा की जनता

को भी पता लग सके कि किसी समय में किसी मुख्य मंत्री ने, किसी कंसीड्रेशन के तहत, हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा के तहत, रिड्यूस किया है या अबोलिश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि ऐसा करने से तीन गुणा आमदनी बढ़ी है यानि 9 लाख रूपए से 27 लाख रूपए आमदनी हो गई है। उनकी यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिंदल जैसे आदमी जो खुद इनकी पार्टी के मैम्बर पार्लियामेंट हैं वे अपनी फैक्टरी में जो चीज बनाते हैं वह चीज बनाने का उनका हैडक्वार्टर दिल्ली में है। जिंदल साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वे एक राजनीतिक आदमी हैं इसलिए दूसरे सारे उद्योगपतियों की बनिस्बत हरियाणा का हित उनके ज्यादा नजदीक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में सेल टैक्स की वजह से बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपे कारखाने तो हरियाणा प्रदेश में लगा लिए लेकिन उनमें बने हुए माल को बेचने का इन्तजाम दिल्ली में अपने हैडक्वार्टर बना कर शुरू कर दिया। उनकी प्रथा क्या है यह मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहां से ट्रक माल भर कर बुलंदशहर के लिए चला और उस ट्रक में माल सपोज करो सेठ सिरी किशन दास जी की फैक्टरी का है। (शोर)

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** आप सपोज सेठ सिरी किशन दास जी की फैक्टरी का माल क्यों कह रहे हैं आप सपोज भजन लाल जी की हिसार की फैक्टरी का माल क्यों नहीं कह रहे।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** चलो यह भी मान लिया।

**श्री बंसी लाल:** अगर आप सपोज की कहते हो तो सिहार की भजन लाल जी की फ़ैक्टरी के माल का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। आप जिन्दल और सेठ सिरी किशन दास का ही नाम क्यों ले रहे हैं। आप चौ. भजन लाल की हिसार की दो फ़ैक्टरी का भी जिक्र कर दो।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** चलो में मान लेता हूँ। एक ट्रक चला हिसार से वह तो 6 किलोमीटर उधर से चला और एक ट्रक 6 किलोमीटर इधर हिसार से चला। दोनों के ट्रक बुलंदशहर जाने हैं। वह सामान हरियाणा में बना, वह सामान चल कर दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली में उनको एक आदमी मिलेगा वह उससे पर्ची ले लेगा और बुलंदशहर के लिए दूसरी पर्ची दे देगा क्योंकि उस माल की बिलिंग दिल्ली में हुई है इसलिए वह सारा टैक्स दिल्ली सरकार को जाएगा। इस तरह से हरियाणा की जनता के साथ उद्योगपतियों की तरफ से यह एक बड़ा भारी अन्याय है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आप केन्द्रीय सरकारसे एक्ट में इस तरह की अमेंडमेंट कराएं कि जो चीज हमारी स्टेट की फ़ैक्टरी में बने उस पर कनसाइनमेंट टैक्स लगाने की इजाजत प्रदेश की सरकार को हो।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से आनरेबल मैम्बर की इन्फ़र्मेशन के लिए एक बात बता दूँ। पिछले

30 साल से मैं देख रहा हूँ यह कहा जा रहा है कि यह कंसाइनमेंट टैक्स लगाने की इजाजत प्रदेश की सरकार को दी जाए। केरल और नेफा स्टेट को छोड़ कर सारे हिन्दुस्तान की सारी स्टेटस यह मानती हैं कि कंसाइनमेंट टैक्स लगाने की उन्हें इजाजत दी जाए। उम्मीद की जाती है कि यह बात दो चार महीने में तय हो जाएगी। इससे स्टेट की आमदनी बढ़ेगी। एक बात मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों नार्दन जॉन के मिनिस्टर्ज की एक मीटिंग हुई थी उस मितिग में कुछ आइटम्ज के उपर यह तय हुआ है कि उन पर यूनिफारमिटी ऑफ टैक्स हो ताकि उससे हर स्टेट की आमदनी बढ़े। हो सकता है यह फर्स्ट अप्रैल से लागू हो जाए।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो एडज्वार्डनिंग 5-6 स्टेटस हैं उनको टैक्स स्ट्रक्चर एक जैसा हो। मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां पर नए कारखाने नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। उन नए कारखानों ओर नई फैक्ट्रियों के लगने के बाद उनका हैड ऑफिस दिल्ली में हो तो हरियाणा प्रान्त को उसका क्या फायदा। उन फैक्ट्रियों और कारखानों के लिए जमीन हरियाणा की दी जाती है उनमें हरियाणा के नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिलता और उनसे हमें जो टैक्स मिलना था वह भी नहीं मिलता क्योंकि उनके हैड आफिस दिल्ली में हैं इसलिए वह सारा टैक्स मिलना था वह

भी नहीं मिलता क्योंकि उनके हैड आफिस दिल्ली में हैं इसलिए वह सारा टैक्स दिल्ली को देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा स्टेट के एडज्वाइनिंग 5-6 स्टेटस का स्ट्रैक्चर एक जैसा हो जिससे किसी को मौका ही नहीं मिलेगा जैसे पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल और डीजल के 200 लीटर तेल के ड्रम की कीमत में हमारा और दिल्ली का 200 रुपये का फर्क है। अगर पेट्रोल या डीजल का एक ड्रम दिल्ली से भरवा कर कोई किसान लेकर आता है तो उसको दिल्ली में हरियाणा की बजाय 200 रुपये कम देने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी आप मेरी इस बात को नोट कर लें कि पानीपत की सभी फैक्ट्रीज वाले अपने जनरेटिंग सैटस चलाने के लिए सारी डीजल दिल्ली से लेकर आते हैं। इस तरह से काफी टैक्स की चोरी होती है। वे कोई 500, 1000 या 10000 लीटर तेल लेकर नहीं आते वे तो लाखों लीटर तेल लेकर आते हैं। इसलिए ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो कोई उद्योगपति हमारी स्टेट की धरती पर कोई चीज बनाता है तो वह टैक्स भी हमारी धरती के लोगों की बहबूदी के लिए मिलना चाहिए वह किसी दूसरी स्टेट को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह जो रिसोर्सिज एंड इकोनोमिक कमी है इसको आप दुबारा से स्थापित कीजिए। पब्लिक मैन का कन्ट्रीब्यूशन उसमें लीजिए। नए सुझाव आपके पास आएंगे। मेरा यह निश्चित मत है कि आप सही सुधारों को लागू किया जाएगा तो कोई नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी और बस के भाडे के रूप में, बिजली की दरों के रूप में या दूसरी शकल में जो टैक्स लगाए गए हैं वह भी आप

विदड़ा कर सकते हैं। हमें अपने सारे टैक्स ढांचे को दुबारा से देखना चाहिए। इसके लिए सरकार एक व्हाईट प्रेपर निकाले ताकि हरियाणा की जनता को भी पता लगे कि किस किस सरकार के समय में किन-किन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों से टैक्सों में रिडैक्शन की है या प्रदेश के हित के लिए की है। दूसरी जो बात मैं प्रदेश के हित में कहना चाहता हूँ कि वह उद्योग के बारे में है। हमारे यहां पर उद्योग काफी मात्रा में बढ़ सकता है लेकिन औद्योगिक नीति को हमेशा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। हमारी एक साख बन चुकी है जो लोग हरियाणा के उद्योग लगाना चाहते हैं वह सोच समझ कर यहां पर आते हैं यहां पर लॉ एंड आर्डर की स्थिति भी ठीक है। हालांकि हमारे यहां पर लॉ एंड आर्डर की स्थिति यू.पी. व दूसरे राज्यों से बहुत अच्छी है इसके बावजूद भी लोग यहां पर उद्योग लगाने की बजाये नोएडा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जहां पर लॉ एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे यहां पर जो हमारी औद्योगिक नीति है उसको हमें नए सिरे से रिव्यू करना पड़ेगा। आपने यहां पर उद्योग के बारे में कहा कि 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह बात कही गई है कि 17632 करोड़ रुपये का खर्च होगा लेकिन यह खर्च कैसे होगा यह बात कहीं नहीं कही गयी। 692 नए कारखाने बड़े और मध्यम दर्जे के लगेंगे। इसमें कहीं पर यह जिक्र नहीं किया गया कि वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या वह रोजगार हरियाणा के बच्चों को मिलेगा? आज मैं सन आफ दी सायल की बात नहीं कर

रहा लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हमारी धरती पर कोई कारखाना लगे और उसमें दूसरे प्रांत के आदमी आरक नौकरी पर लगे यह हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जो उद्योगपति यहां कारखाने लगा रहे हैं, क्या आप अपनी उद्योग नीति ऐसी बनाएंगे जिससे उद्योगपति आपकी तरफ आकर्षित भी हों और आपके राज्य में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार देने में भी कोई कोताही न हो।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, आज से 25 साल पहले नेशन इन्टीग्रेशन की मीटिंग श्रीनगर में हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया था कि जहां पर फ़ैक्टरी लगेगी वहीं की ही लोकल लेबर लगेगी बाहर की नहीं। हां कोई स्किल्ड या एक्सपर्टाइज वगैरा की बात हो तो अलग बात है। हमारे यहां पर जितनी भी फ़ैक्ट्रीज लगेगी उन पर यह कन्डीशन पहले लगायेंगे। इसको हम इम्प्लीमेंट करायेंगे और बाकायदा लोकल आफिसरज की रिपोर्ट लेंगे।

## 12.00 बजे

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि लेबर लगे न लगे इससे मेरा मतलब नहीं है मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस कारखाने में जो स्किल्ड है, टैक्नोक्रेटस है, टैक्नीशियन्ज हैं वे बाहर के होते हैं। उनमें हमारा कोई बच्चा नहीं होता क्योंकि हमारे बच्चों को उनकी ट्रेनिंग नहीं है। जब तक

ट्रेनिंग का इन्तजाम राज्य सरकार नहीं करेगी तब तक वे लोग हमारे बच्चों को नहीं लगायेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है, यानि जिन-जिन हुनर की उन कारखानों को जरूरत है, उस ट्रेनिंग का प्रावधान हरियाणा के अन्दर किया जाना जरूरी है। अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ। बिजली की ट्रांसपेरेंसी की बात करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से ही मैंने कांग्रेस में रहते हुए उस समय की सरकार के खिलाफ बगावत की थी सिर्फ इसलिए कि हरियाणा के लोगों के हित पर्दे के पीछे तय न किए जाएं। यह बिल्कुल हरियाणा के लोगों के हित की बात है जो कि हमें बतानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, मेरी इन्फर्मेशन यह है और मैं इनको भभी इससे आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह के एम.ओ.यू. साईन हुए हैं या होने की बात थी उसे ऐसी स्थिति आ सकती थी कि बिजली की दर बहुत ऊंची चली जाती और एक आदमी को 10 रुपये पर यूनिट पर बिजली प्राप्त नहीं होती। अब आप कल्पना करें कि कौन आदमी आज 10 रुपये पर यूनिट बिजली पर खर्च कर सकता है। इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात है। जहां तक बिजली के ट्रांसमीशन की बात है, पिछले 10 साल से सरकार कह रही है कि 900 करोड़ रुपये तक आ जाएगा। बिजली बोर्ड का ट्रांसमीशन सिस्टम ओब्सोलीट हो चुका है इसलिए उसको नया बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपये का खर्च करना होगा और हमारे पास इतने पैसे का प्रावधान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान न करके, सिर्फ



इसलिए कि हम 1200 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते, अपना ट्रांसमिशन सिस्टम किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें यह समझदारी का काम नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्ट जिसका प्रारूप तैयार किया गया है पता नहीं इसे सदन में कोई लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा। यह हरियाणा स्टेट रिफॉर्म इलैक्ट्रिसिटी बिल, 1996 अगर सदन में पेश हुआ और पेश होकर पास हुआ तो सरकार की सारी पावर उस कमीशन को चली जाएगी जो इसे रैगुलेट करेगा। (विघ्न)

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह बिल इनके नेता ने ही बनाया था और इसे भारत सरकार को भेजा था। हमने अभी इसको क्लीयर नहीं किया है। हम बाकी सारी स्टेटस का सिस्टम देखेंगे। दूसरी स्टेटस के बिलों को देखने के बाद और सोच-समझ कर इस बिल को लाएंगे, सारे सदन में थोरोली डिस्कशन के बाद ही इस पर कोई कार्यवाही करेंगे।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** डिप्टी स्पीकर सर, इसमें मेरी जो ऐप्रिहेंशन है वही ऐप्रिहेंशन सभी की होनी चाहिए। यह राज्य एक अथोर्टी है यदि हम उस अथोर्टी को टैरिफ तय करने के लिए, बिजली की दर तय करने के लिए, मैनेजमेंट तय करने के लिए, किसी प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे तो यह अथोर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो फिर हम हरियाणा के किसानों को मुफ्त बिजली देने की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा

हुआ तो किसान को मुफ्त या सस्ती बिजली कैसे दे सकेंगे। कोई भी प्राईवेट आदमी हर छः महीने में कीमत बढ़ाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी यह कहता हूँ कि हरियाणा में अभी भी उद्योगपति चाहता है कि उसे 24 घंटे बिजली मिले, अन-इंट्रिप्टिड पावर सप्लाई मिलें आप उसको स्ट्रैस कीजिए कि प्राईवेट सैक्टर से उसको बिजली मिल सके। वह अधिक बढ़ी हुई दरों पर भी बिजली खरीदने के लिए तैयार है। उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली बिजली को बेशक प्राईवेट हाथों दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम से जो बिजली अर्जित होती है वह देश के बिजली के टोटल उत्पादक को 21 प्रतिशत है। इस बिजली को जैनरेट करने पर सिर्फ 9 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट आती है और ट्रांसमिशन की कॉस्ट 40 पैसे पर यूनिट आती है। इस प्रकार 49 पैसे पर यूनिट पर भाखड़ा डैम से पैदा की गई बिजली की सप्लाई हो सकती है। किसान को जो बिजली दी जानी है वह यही बिजली सप्लाई की जानी चाहिए इसके लिए किसान को किसी प्रकार की सबसिडी देने की भी सरकार को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 49 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को बिजली की सप्लाई की जा सकती है। इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त खर्चा भी नहीं पड़ेगा। सरकार उसको यह बिजली दे सकती है। उपाध्यक्ष महोदय मुझे शक है यदि यह बिल आया और बिल इस हाउस में पास हो गया तो बिजली की सारी ताकत सरकार के हाथों से निकल कर दूसरे हाथों में चली जाएगी फिर हमारी मन्शा, आपकी मन्शा या सरकार की मन्शा कुछ भी हो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे

इसलिए मैं इस पर अधिक जोर दे रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ वह है नहरी पानी के बंटवारे के बारे में (विधन) उपाध्यक्ष महोदय, आईजनबर्ग के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आईजनबर्ग का समझौता जो हुआ है उसे कैंसल किया जाए और सरकार से कहता हूँ कि नये समझौते कीजिए वरना तो जो समझौता होगा उसके बारे में एम.ओ.यू. तो हो गया है वह समझौता स्टेट के हित में घातक होगा। आईजनबर्ग समझौता हो या यमुना नगर थर्मल पावर प्लांट, ये भी एस.वाई.एल. की संज्ञा बन कर रह जाएंगे और एस.वाई.एल. की तरह कभी कम्पलीट होने की हालत में नहीं होंगे। इस प्रकार के समझौते, जिनके बारे में आपको भी शक हो, उनको स्क्रेप कर दीजिए। इन्हीं कारणों से तो सरकार में रह कर भी मैं इनका विरोध करता रहा हूँ। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो किसी की भी सरकार हो किसी को भी इस प्रकार जनविरोधी समझौते करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम हर बात जनता के सामने क्लीयर करके करेंगे तो उससे हम सही मायनों में जनता के साथ इन्साफ करेंगे। अगर हमने कहीं गलती की है तो उन गलतियों को उजागर करना हर विधायक का फर्ज है वरना तो आज की राजनैतिक व्यवस्था ऐसी है कि बंसी लाल जी आज हैं तो वे सोचते हैं भजन लाल जी को ज्यादा तंग न करें क्योंकि क्या पता कल को फिर वे सत्ता में आ जाएं, चौटाला साहब मुख्यमंत्री हों तो वे सोचते हैं कि बंसी लाल जी और भजन लाल जी को ज्यादा तंग न करें क्योंकि क्या पता वे कल को सत्ता में आ जाएं। चौ.

भजन लाल, बंसी लाल और चौटाला साहब का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अपना तो कभी नम्बर आने वाला नहीं है (हंसी)

**प्रो. राम बिलास शर्मा:** उपाध्यक्ष महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी में वह बात हो रही है कि एक अंधा आदमी चार दीवारी में फंस गया और उसमें एक दरवाजा था। जब दरवाजे पर हाथ आया तो उसके कुल्हे में खाज पड़ गई तो वह दरवाजा निकल गया। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी का वह अवसर आया तो वह दरवाजा फिर निकल गया। इस बारे में ये क्या दोश दे रहे हैं। (हंसी)

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** मैं इस बारे में दोश नहीं दे रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी था और उसके घर में एक पुरानी कार खड़ी थी। कार उस आदमी के एम.एल.ए. बनने से पहले की थी। उसका घर पुरानी हालत में था। जब वह एम.एल.ए. बन गया और अपने हल्के में गया तो वहां के लोगों ने उसको माला डाल कर और पैसे देकर स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि इस पैसे से जो उसको मिला है क्यों न मकान बनवा लिया जाए। तो उस एम.एल.ए. ने मकान बनवाना शुरू कर दिया और जहां पर उसकी कार खड़ी थी उसके चारों ओर चार दीवारी खड़ी कर दी। उसके बाद जब उसे कार निकालनी पड़ी तो वह कहने लगा “हुन किवें कढ़िए कार नूँ”। (हंसी) शर्मा जी जब ऐसे ऐसे महारथियों का साथ होता है तो ऐसी बात हो ही जाती है। (हंसी)

**श्री जगन्नाथ:** उसके पास कार कहां से आ गई?

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** जगन्नाथ जी वह पुराना फौजी था और कहीं से डिस्पोजल की ले आया होगा। वह \*\*\*\* का था।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने बिरादरी वाली बात कही है वह कार्यवाही से निकाल दी जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। बीरेन्द्र सिंह जी आप कन्कलूड करें।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** ठीक है जी मैं कन्कलूड करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में यह कहूंगा कि हमारा एवलेबल वाटर है चाहे वह जमुना में है चाहे आगरा कैनल में है और चाहे भाखड़ा में है, मुख्यमंत्री जी मुझे इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं है कि 1976 से लेकर आजतक 21 साल हो गये हैं। हरियाणा के साढ़े चौदह जिलों का जो पानी का हक बनता है उससे उनको दूर रखा गया है इस दौरान आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौ. भजन लाल भी रह चुके हैं, चौ. देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और आधा जीन्द का इलाका है उसके हिस्से का पानी कहां चला गया। (विधन) जो मैंने डेढ़ जिला छोड़ा है वह समझते हैं कि वह इलाका कौन सा है। (विधन) बार-बार वहीं के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और मैं खुद हैरान हूँ। इंजिनियर्स भी इस बात को मानते हैं। इस बारे में मैंने सवाल भी पूछा था कि जिस नहर की

कपैस्टी 44 सौ क्यूसिक है जो डब्ल्यू.जे.सी. को स्ट्रैग्थन करने के लिए पानी लेकर आती है उसकी कपैस्टी घटती-घटती 24 सौ क्यूसिक रह गई है। जो 18 सौ क्यूसिक पानी बचा हुआ है वह भाखड़ा मेन कैनाल में चलता है और वह पानी जहां पर जाता है उस बारे में सबको पता है जहां पर किन्नू के बाग हैं। (विघ्न)

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** आप यह बताएं कि वह कौन सा इलाका है?

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** दलाल साहब हैं बता दूंगा अगर आप उनको ठीक करने की गारन्टी लेते हो तो। आप इस सदन में आश्वासन दे दो कि यह अन्याय हम साढ़े चौदह जिलों से दूर कर देंगे। मैं मुख्य मंत्री की बात पर हैरान हुआ। जब मैंने पिछली बार यह सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि अढ़ाई हजार क्यूसिक तो सिरसा जिले का है। (हंसी) यह जो हमारा पानी का हक है वह हमें मिलना चाहिए। यह हमें तभी मिल सकती है जब उस नहर को जो कि पंजाब टैरीटोरी से होकर हमारे यहां पर आती है, की डिसिल्टिंग का काम, विडिसाइडस बगैरह जो उसमें हो गए हैं, की सफाई का काम हो। अगर यह काम आप पंजाब सरकार से करवा पाएंगे तभी हरियाणा के उन जिलों को पानी मिल सकेगा।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, यह काम चालू है। हम इस काम के लिए ढाई करोड़ रूपये पंजाब सरकार को दे चुके हैं तथा लगभग ढाई या तीन करोड़ रूपये अभी उनको और देने हैं,

वह रूपये भी हम उनको दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय वह पानी आएगा क्योंकि वह नहर स्ट्रैंग्थन हो रही है। स्ट्रैंग्थन होने पर इस नहर में पूरा पानी आएगा। पिछले कई सालों से इस पर कोर्ट पैसा खर्च नहीं किया गया है इसलिए इसकी कैपेसिटी कम हो गयी। अब हमने आते ही इस काम को शुरू करवाया है। हमने वहां पर अपने ओफिसर्ज भी लगा रखे हैं ताकि वे इस काम का सुपरविजन करें और सारी चीजों को देखें। उपाध्यक्ष महोदय, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

**श्री धीरपाल सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल हमारे सीनियर मोस्ट मंत्री हैं। उन्होंने भी कमिटीमेंट की थी। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा और मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद इस बात पर है कि मैंने पिछले सेशन में और इस चालू सेशन में यही प्रश्न लगाए थे कि क्या दक्षिणी हरियाणा और रोहतक के साथ नहरी पानी के बंटवारे के मामले में कोई अंतर है? अगर अंतर है तो वह किस अनुपात में है? मैं दुःख इस बात पर व्यक्त करता हूं कि दोनों ही बार मेरे ये प्रश्न डिस-अलाऊ हुए हैं। चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने खुले मन से एक बात कही है कि 1976 से लेकर आज तक इस इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है। यह तो एक रिकार्ड की बात है कि जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो हमारी उस सरकार ने उस समय पंजाब के इलाके में भाखड़ा मेन कैनाल की सफाई के लिए और उसके किनारों को ऊंचा करने के लिए तकरीबन 6 करोड़ रुपये एवं आठ

करोड़ रूपये की राशि पंजाब सरकार को भेजी थी और कहा था कि आप इस नहर की सफाई करवाएं। लेकिन उसके बाद हालात खराब हो गए और वह काम आगे चालू नहीं हो पाया। लेकिन अब बाकी काम को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने पैसा भेजा है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** आप समझे नहीं कहीं तो गड़बड़ है। यह बात नहीं है कि आपने उस कैनल की सफाई के लिए पैसा दिया है जो कैनल टोहाना और सिरसा जाती है।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, जिस पानी की ये चर्चा कर रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा की ये बात कह रहे हैं तो हकीकत तो यह है कि मैं तथा चौ. धीरपाल सिंह तो दक्षिणी हरियाणा के हैं ही और 75 परसेंट भाई बीरेन्द्र सिंह भी इसी तरह से हैं। लेकिन 25 परसेंट यह कहीं और थोड़ा सरक गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि न तो मैं, न चौ. धीरपाल सिंह और न बीरेन्द्र सिंह कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया। (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** आप सभी बैठें। (विघ्न) आप सबको नियमों का तो पालन करना चाहिए। आप बैठें। बीरेन्द्र सिंह, आप जल्दी ही कंक्लूड करें।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब लीडर ऑफ दी हाउस इस बात को मानते हैं तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लोगों को इन्साफ मिलना



चाहिए। हरियाणा की एक करोड़ 60 लाख जनता का काम है और यह कोई एक आदमी का काम नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात में यह भी कहूंगा कि मुख्य मंत्री चाहे किसी भी हल्के के हों, चाहे किसी भी जिले के हों और चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वह सारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाबार्ड से साठा करोड़ रूपये लिए हैं लेकिन ये उस सारे पैसे को भिवानी में ही लगा रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

**श्री बंसी लाल:** उपाध्यक्ष महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ड्रामेटाइज करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एक चीज में आपके जरिए सदन को बताना चाहता हूँ कि हम 60 नहीं करीब 70 करोड़ रूपया नाबार्ड से ले रहे हैं और वह इसलिए ले रहे हैं कि हमारा 1858 करोड़ रूपये का री-कंस्ट्रक्शन का नहरों का प्रोग्राम है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) उस प्रोग्राम में पिछली सरकार ने लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को शामिल नहीं किया, न भिवानी, न रिवाड़ी, न महेन्द्रगढ़ न गुड़गांव को शामिल किया। जहां लिफ्ट का पानी जाता था पिछली सरकार ने किसी जगह को किसी स्कीम में उसे शामिल नहीं किया। उन पूरी लिफ्ट स्कीमों में पैसा लगेगा। भिवानी, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ सबमें लगेगा सबसे बड़ी नहर जे.एल.एन. है सबसे ज्यादा पैसा उस पर लगेगा। जे.एल.एन. भिवानी जिले में नहीं आती है तो उसके लिए भिवानी में लिफ्ट इरीगेशन है उनके ऊपर भी खर्च होगा। किसी के साथ कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष:** बीरेन्द्र सिंह जी, आपने 11 बज कर 25 मिनट पर बजट पर बोलना शुरू किया था आपकी सारी पार्टी का टोटल टाइम एक घंटे का है चाहें तो आप अकेले उस पर बोल लें चाहे सारे मैम्बर्ज को बुला लें।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मेरी जो इन्फर्मेेशन है कल सोमवीर जी ने बोलते हुए कहा था कि 96 खालों में से 95 पर पूरा पानी पहुंच गया है तो नाबार्ड का सारा पैसा तो वहीं लगा है।

**श्री बंसी लाल:** अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में सिर्फ 62 वाटर कोर्सिज ऐसे हैं जिनकी टेल पर पानी नहीं पहुंचा वह भी जल्दी पहुंचा देंगे।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों के साथ मैं यह कहूंगा कि प्रौडक्टीविटी चाहे औद्योगिक सैक्टर में हो, चाहे कृशि सैक्टर में हो चाहे कर्मचारियों की और नौकरशाही की बात हो, उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है। यह बड़ी अलार्मिंग बात है। पर—कैपिटा इंकम में हरियाणा दूसरे नंबर पर होता था आज चौथे नंबर पर है।

**श्री बंसी लाल:** इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। पहले जब मैं आया था तो 11वें नंबर पर थी उसे मैं दूसरे पर ले आया था। ये तो फिर पिछली सरकार के समय में हुई है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** मैं तो उस सरकार के खिलाफ था उस सरकार की कारगुजारियां ऐसी रहीं कि 63 में से 9 बनकर आए।

**श्री बंसी लाल:** अगली बार दो रह जाओगे एक खुर्शीद अहमद व दूसरे आप। (हंसी)

**श्री बीरेन्द्र सिंह:** अबकी तो मुझे आपकी और बी.जे.पी. की चिंता है। लोग इतने नाराज हैं कि चुनाव जल्दी न करा लेना नहीं तो बहुत बुरी हालात होगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव):** अध्यक्ष महोदय, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पिछले 5 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिले। गवर्नर ऐड्रस या फाइनेंस मिनिस्टर का बजट सरकार की नीतियों का एक आईना होता है। लोगों की भलाई के लिए क्या प्लानिंग है हम क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि शीशे के अंदर शकल तो अलैहदा दिखाई देती है। धुंधली सी तसवीर भी नजर नहीं आती। आज मुझे यह देखकर दुःख होता है कि सही मायनों में बजट वह होता है जिसमें इकोनोमिक रिफॉर्मज हों, जिससे लोगों का जीवन-स्तर बढ़े और लोगों को कोई राहत मिले। इस बजट के बारे में कोई नहीं कह सकता कि लोगों को कोई राहत मिलेगी या लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आज जो कुछ भी हमने इस बजट में देखा है

उससे बड़ी निराशा हुई है। गुड़गांव एक बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल टाऊन है। आज तो कुछ अखबार में छपा है मुझे उससे बहुत दुःख होता है। कल दिल्ली में एक डिवैल्पमेंट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड कांफ्रेस समाप्त हुई है। उस कांफ्रेस में यह कंकलूजन दिया गया कि इंडस्ट्रियल डिवैल्पमेंट के लिए और फौरन इंवैस्टमेंट करने के लिए अगर हिन्दुस्तान में कहीं जगह है, तो वह हरियाणा के गुड़गांव में है। अनफोर्च्यूनैटली ऐसा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। स्पीकर सर, सी.एम. साहब ने बड़े फख्र से कहा कि हमने 20-21 इंडस्ट्रियल मैमोरैण्डम को अप्रूव किया है, साईन किया है लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि 1995-96 में 100 के करीब साईन हुए थे और यह किसी ने नहीं देखा कि 40 और साईन वे नहीं कर पाये। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** आपने तो पिछले पांच सालों में बजट की कपैरेटिव स्टडी कर ली होगी।

**श्री धर्मबीर गाबा:** स्पीकर सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा खासतौर से उन मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जब बहस होती है जो हर बार कहते हैं कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया या वे इस लाईन पर चलते। मैं नहीं समझता कि ये मंत्री हमारे लिए क्या रिफोरम करेंगे। मैं यह बात मानता हूं कि गलती हुई है लेकिन उन गलतियों में क्या सुधार करने जा रहे हैं, इस बात का जवाब कोई नहीं देता। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** गाबा साहब, मेरा यह मतलब कतई नहीं था। आप एक शिक्षाविद और पुराने विधायक हैं और आपने तो कपैरेटिव स्टडी कर ली है।

**श्री धर्मबीर गाबा:** सर, हमें यह बताया गया कि पिछले नौ महीनों में गुड़गावां में 20 नई लार्ज इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि 1995-96 में 100 लगाई थीं और इंडस्ट्रियल इंटरिप्रिन्योर मीमो 100 हुई थीं, और यह बात किसी ने नहीं बताई कि 1995-96 में 400 साईन हुये थे क्या हम यह समझें कि इंडस्ट्रियल डिवैल्पमेंट हरियाणा में रुकेगी? आज डिवैल्पमेंट के दो पहलू हैं एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्रीज। अगर आप हरियाणा को प्रगति के रास्ते पर चलाना चाहते हैं तो आप हमें यह बतायें कि क्या आपने बजट के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान किया है कि इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देंगे? आज हमारी इंडस्ट्रीज नोएडा में शिफ्ट हो रही हैं। आपने कोई प्लानिंग नहीं बताई कि इंडस्ट्रीज के लिए हमने कितना पैसा लगाया है। आपने 27 करोड़ के लगभग पैसा इंडस्ट्रीज डिवैल्पमेंट के लिए इस बजट में रखा है क्या सरकार समझती है कि इससे इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमेंट हो जायेगी। आज हमें इसकी भी बहुत जरूरत है। जब चौ. बंसी लाल जी ने इस प्रदेश की सत्ता सम्भाली तो पहले ही दिन मैंने उनसे मुलाकात करके बताया था कि दक्षिणी हरियाणा ने आपको 14 एम.एल.ए. दिए हैं और हमें 15 दिए थे जब हमने जनता के साथ इंसॉफ नहीं किया तो उन्होंने हमें विपक्ष में बैठा

दिया। कहीं ऐसा न हो कि आपको भी विपक्ष में बैठा दें इसलिए जो दक्षिणी हरियाणा में डिवैल्पमेंट हो रहा है उसे कंटीन्यू रखिये। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज कहीं भी डिवैल्प होती है तो उसके कुछ कॉजिज होते हैं जैसे कहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलता है, कहीं लेबर मिलती है, कहीं रॉ मैटीरियल मिलता है, और कहीं लॉ एंड आर्डर अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है जहां इंडस्ट्रीज का तैयार माल खप सकता है, लेकिन इस बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई कहता है कि इंडस्ट्रीज को भिवानी ले जाओ या और कहीं ले जाओ। इंडस्ट्रीज के बारे में 28 फरवरी का अखबार मेरे पास है जिसमें लिखा है –

“the lack of the State Government’s interest in promoting industry is in evidence from the slackened industrial activity in the State. During the last nine months, only 20 new large industries have been established.....” अध्यक्ष महोदय, यह अखबार की राय थी। यह पब्लिक की ओपीनियन की बात रही है। (घंटी)

**श्री अध्यक्ष:** मैं आपको बीच में इंटरुप्ट करने के लिए खेद प्रकट करता हूँ। आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है। कृपया आप बताएं कि आप कितना समय और लेंगे?

**श्री धर्मवीर गाबा:** अध्यक्ष महोदय, कृपया आप ही बताएं कि आप कितना समय और देना चाहेंगे? हम तो आपकी इच्छा के मुताबिक ही बोलेंगे क्योंकि आप इस सदन के कस्टोडियन हैं।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, आप 10 मिनट में कन्कलूड करें।

**श्री धर्मवीर गाबा:** अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमेंट के लिए चौटाला साहब ने भी बात की है तथा उसमें प्रावधान भी रखा गया है। हिसार, रोहतक, कलानौर, गुड़गांव, बरवाला व चरखी-दादरी इस स्कीम के अंतर्गत चुने गए हैं ताकि बड़े शहरों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सके और वहां पर पापुलेशन न बढ़े। पापुलेशन बढ़ने के तीन मुख्य कारण हैं। क्योंकि मैं इस महकमे का मंत्री रह हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में ज्ञान है। सबसे पहले तो शिक्षा जो गांव में नहीं दे पाते हैं, उसके लिए बड़े शहरों में बच्चों को दाखिल कराना पड़ता है। दूसरा कारण रोजगार की खोज है क्योंकि बेरोजगार यूथ रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भागते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात मैडिकल फ़ैमिलिटी की है जो कि शहरों में ही मिलती है तथा गांवों में नहीं मिलती है। इन कारणों की वजह से लोग शहरों में आते हैं। इसलिए हर साल इन शहरों में 10 प्रतिशत आबादी बढ़ जाती है। इसको कैसे रोका जाए? अनअथोराइज्ड कब्जे हो जाते हैं, गंदगी फैल जाती है तथा आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस प्रकार से कैसे विकास होगा? इयकी प्लानिंग के बारे में कोई भी प्रावधान बजट में नहीं रखा गया है।

मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूँ कि आदरणीय बहिन जी जो यह समझती हैं कि ये सर्वेसर्वा हैं। मैं आपको फोटो दे सकता हूँ। मैं इसे साथ में लाया हूँ। आजकल यह हालात हैं कि आपके विभाग में एक एप्लीकेशन अढ़ाई मंजिला मकान बनाने के लिए दी जाती है। उस पर एम.ई. और बिल्डिंग इंस्पेक्टर यह रिपोर्ट करता है कि यह मकान नहीं बन सकता है। यह अनअथोराइज्ड है। 25 तारीख को तो ये कहते हैं कि यह नहीं बन सकता है लेकिन 27 तारीख को उसकी स्वीकृति हो जाती है। कहते हैं कि ऊपर से सिफारिश आई थी और इस प्रकार अढ़ाई मंजिला मकान की बजाए 5 मंजिला मकान बन गया। इससे बड़ी गलत बात आपके विभाग में कोई और नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मैं बताना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पर रात-रात में नाजायज कब्जा कर लिया जाता है। ऐसी अंधेरगर्दी हमने कहीं नहीं देखी है। लेकिन मैं तो उस जिला प्राइमरी शिक्षा अधिकारी का धन्यवादी हूँ कि जब उस स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया तो उन्होंने दूसरी जगह में क्लासिज बिठाकर स्कूल को चालू रखा। (विघ्न) बहिन जी, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ। (इस समय एक फोटो श्री धर्मवीर गाबा ने सदन के पटल पर रखी) अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि 4-5 फुट का बोर्ड, मंत्री जी ने अपने घर के बाहर सड़क पर लगाया हुआ है। हम लोग भी मंत्री रहे हैं। लेकिन हम ने कभी ऐसा नहीं किया है। किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं बनता है। क्या ऐसा कोठ प्रावधान है?



गृहमंत्री साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वे सच्चाई बताएं। (विधन)

**गृह मंत्री** (श्री मनी राम गोदारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये मुझे जो भी सूचना देंगे, उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कम से कम इनको भी तो आईने में अपना मुंह देख लेना चाहिए। जो काम इन लोगों ने किये हैं कम से कम उनको भी तो इन लोगों को याद रखना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष:** गाबा साहब, आपने मेरे पास जो फोटो भेजी है उसके लिए धन्यवाद लेकिन इसमें जो सीता राम सिंगला भूतपूर्व मंत्री लिखा हुआ है वह भूतपूर्व मंत्री आपने काट रखा है।

**श्री धर्मबीर गाबा:** सर, वह बोर्ड आज भी खड़ा है। भूतपूर्व उन्होंने ही काट रखा है हमने नहीं काटा। आप इस बात की इन्कवायरी करवा लें। मैंने एस.पी. से बात की थी।

**Sh. Mani Ram Godara:** I will be very grateful to you if you give me information about the things which are unlawful.

**श्री धर्मबीर गाबा:** स्पीकर साहब, मुझे एक बात और जरूर कहनी है कि फाईनैस मिनिस्टर साहब ने जो बजट स्पीच पढ़ी उसमें कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि साहब हम होम डिपार्टमेंट के लिए या पुलिस के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। प्रदेश में शराब बंदी लागू कर दी है। शराब बंदी को पूरी तरह से लागू

करने के लिए पुलिस के लिए नई जीपें खरीदी जानी चाहिए, उनके लिए वायरलैस सैट भी खरीदे जाने चाहिए। इस बारे में बजट स्पीच के अन्दर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन इस बारे में सी.एम. साहब की तरफ से और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से यह अश्योंरेंस जरूर दल गई है कि उनके लिए इनका प्रावधान जरूर किया जाएगा। लेकिन इस बजट स्पीच में उस बारे में कहीं पर कोई बात नहीं है, यह मैंने सारा पढ़ लिया है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से एक अर्ज करना चाहता हूँ कि गुड़गांव में सदर थाना है उसके अन्दर 13 सिपाही हैं। उस थाने के अंडर 200 गांव आते हैं और शहर का कुछ हिस्सा भी आता है। उन 13 सिपाहियों में से एक सिपाही कोर्ट में रहता है एक थाने के बाहर संतरी के तौर पर रहता है, दो सिपाही लिखने पर रहते हैं और एक जीप का ड्राइवर है तो आप यह बताएं कि जो 8 या 9 सिपाही बचते हैं क्या वे 200 गांवों की रखवाली कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। झाड़सा गांव के अन्दर गवर्नमेंट के 40 लाख रुपये 9वें महिने के अन्दर एक जीप से उठाकर ले गए जिसका आज तक पता नहीं है। उन बातों को आज 6 महीनें हो गए आज तक पुलिस उस बारे में पता नहीं कर पाई है। झाड़सा गांव के विजेन्द्र कुमार को राजीव चौक के पास गोली मार दी गई उसको शाम के 7.00 बजे गोली मारी गई। इसके बावजूद हम कहते हैं कि ला एंड आर्डर कंट्रोल में है। क्या हम कह सकते हैं कि ला एंड आर्डर की पोजिशन ठीक है? स्पीकर साहब, गुड़गांव की जिस

कालोनी में मैं रहता हूँ वह न्यू कालोनी के नाम से जानी जाती है 25 जनवरी को वहां पर एक महिला कार के अन्दर साढ़े ग्यारह बजे बैंक से पैसे निकलवा कर आती है और वह मार्किट के पास पुलिस चौकी से 10 गज के फासले पर आकर ठहरती है। वह सोचती है कि कार लेकर आई हूँ इसलिए रिश्तेदारों को मिठाई खिला दूँ। वह मिठाई लेने के लिए रुकती है तो वहां पर दो आदमी आते हैं और उसको पिस्तौल दिखाकर उसकी कार से दो लाख रुपये उठा कर चले जाते हैं। यह 25 जनवरी की बात है कि आज 14 मार्च ही गई उनका आज तक कोई पता नहीं है। इसी तरह से आदमी धर्मपाल वल्द नथुराम कार बुक करवाने के लिए 95 हजार रुपये लेकर जा रहा था उसको राव विरेन्द्र की कोठी के पास पिस्तौल दिखाकर उससे 95 हजार रुपये ले गए, अपराधियों का आज तक पता नहीं है। यही नहीं स्कूलों की बच्चियों को उठा लिया जाता है। एक राखी नाम की बच्ची गवर्नमेंट गर्ल्ज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल से बाहर निकलते हुए उठा ली गई, उसका आज तक पता नहीं लगा कि वह कहां गई?

**श्री मनी राम गोदारा:** जो इन्फर्मेशन आप दे रहे हैं I will be very grateful to you if you give this information in writing as I have no knowledge about it.

**श्री धर्मबीर गाबा:** ठीक है जी। मैं आपको आज ही टाईप करवा कर दे दूंगा। अगर आप इजाजत दें तो यह मैं आपका सोमवार तक दे दूँ।

श्री मनी राम गोदारा: ठीक है आप सोमवार को दे देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री धर्मबीर गाबा: यह ऐसा मंच है जहां पर हम विद दि परमिशन ऑफ दि स्पीकर कुछ कह सकते हैं। हमने अपना सर पटक लिया पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने सोचा ये बातें अगर हम हाउस में कहेंगे तो इन पर कुछ एक्शन होगा और लोगों को कुछ राहत मिलेगी। आपका नाम होगा आपकी हकूमत का नाम होगा। हम चाहते हैं कि चाहे हकूमत आपकी हो चाहे हमारी हो हमें अपने फर्ज से गुरेज नहीं करना चाहिए। हमें अपने फर्ज को निभाना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। (घंटी)

**Mr. Speaker:** Please conclude within a minute.

श्री धर्मबीर गाबा: मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं मेहरबानी करके, इन पर ध्यान दें। खासतौर पर फाईनैस मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि 27.4 करोड़ रुपये से बैलेंस खोला है और 47.59 करोड़ रुपये का लौस इस बजट के अन्दर है। इसके अलावा जो लाइबिलिटीज हैं वे अलग से रह गयी हैं। लायबिलिटीज 31 मार्च 1997 तक 7213.13 करोड़ रुपये की रह जायेंगी और जो आगे 31 मार्च 1998 तक 853.46 करोड़ रुपये हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी लायबिलिटीज क बाद कहां से प्लान के लिए पैसा आयेगा। कहीं हमारे प्लानिंग वर्क में कोई रुकावट तो नहीं आ जायेगी। सरकार ने जो राहत के काम

किए हैं क्या उन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह तो आपने देखना है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर ने 6 तारीख को 3, 10 तारीख को 2, 11 तारीख को 3 और 12 तारीख को 4 सवालों के जवाब में यानि 12 सवालों के जवाब में यही कहा कि पैसा अवेलेबल होगा तो काम हो जायेगा वरना नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेहरबानी करके पैसे का प्रावधान कीजिए ताकि लोगों को राहत दी जा सके। धन्यवाद।

**श्री रामपाल माजरा (पाई):** अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि कई दिनों के बाद आपकी नजरे इनायत मेरी तरफ हुई हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। हरियाणा प्रदेश की सरकार के वित्त मंत्री श्री चरणदास शोरेवाला ने जो इस सदन में अपना बजट पेश किया इसे बार-बार पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, कई बार पढ़ने के बाद मैं समझता था कि इसका विरोध न करूँ क्योंकि ये मेरे नजदीकी हैं। यदि इनकी नजरें किसानों की तरफ चली जाती, कर्मचारियों की तरफ चली जाती तो बात बनती या कुछ व्यापारियों को सहूलियत दी जाती तो अच्छी बात होगी। परन्तु सारे का सारा बजट बार बार पढ़ने के बाद यही पता चला कि इनको जो काम करने हैं या तो ये वर्ल्ड बैंक से कोई मदद लेंगे या किसी और से मदद लेकर काम करेंगे। इनकी बात को देखकर मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि

तू इधर उधर की बात न कर

तू ये बता ए काफला क्यों लुटा  
मुझे तेरे राह जनों की गर्ज नहीं  
तेरी राहबरी का सवाल है।

हरियाणा प्रदेश के लोगों की निगाहें इस बजट की तरफ लगी हुई थीं कि यह सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुछ सुख सुविधाएं देगी। हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार पुरानी लीक से हट कर काम करेगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा सरकार किसानों का हमदर्द होने की बात करती है। सभी किसानों को नाम लेते हैं लेकिन मौजूदा सरकार ने इस तरफ कोई काम नहीं किया। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने से यह पता लगा कि अब की सरकार ने कुछ खातों में कुछ प्रतिशत इधर-उधर किया है। 1995-96 में कृषि पर टोटल बजट का 7.2 प्रतिशत खर्च हुआ था। 1996-97 में यह 7.2 प्रतिशत खर्च हुआ है जबकि इस काम के लिए 1997-98 में 6.7 प्रतिशत पैसा रखा गया है। यहां किसानों का नाम लेकर विधान सभा में कदम रखते हैं, भाषण दिये जाते हैं लेकिन किसी प्रकार से किसानों की सुख-सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार ओले पड़ जाते हैं या प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, उनका ध्यान नहीं रखा गया और न ही इस बजट में किसानों की फसल का बीमा करने की कोई बात की गई। सरकार की इस तरफ नजर ही नहीं गई कि किसानों को राहत दी जाये। किसान को जिस वक्त डी.ए.पी. की

जरूरत होती है उस वक्त यूरिया लेने के लिए कहा जाता है और जिस वक्त यूरिया की जरूरत होती है उस वक्त डी.ए.पी. लेने के लिए कहा जाता है। जब खेतों में पानी फेरने की जरूरत पड़ती है तब तो किसान को पानी नहीं मिलता लेकिन फलड के दिनों में किसानों से कहते हैं कि पानी ले लो। इस प्रकार की किसान विरोधी बात ये लोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है लेकिन किसानों को किसी प्रकार का मुआवजा देने की भी कोई स्कीम सरकार ने नहीं बनाई। अगर किसान जमनी के नीचे ट्यूबवैल की मोटर तक जाता है तो जहरीली गैस से मरता है, वहां बैठा हुआ सांप उसे डस लेना है, आसमानी बिजली भी उसी किसान पर गिरती है। खरपतवार और किटनाशक फर्जी दवाईयां उसको दी जाती है। वह उसके सिर में चढ़ जाती हैं जिससे वह मर जाता है अगर उसको हरियाणा सरकार के खजाने के वजीरे खजाना द्वारा बीमा गारन्टी दी जाती तो मैं इस बजट का स्वागत करता लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है इसलिए मुझे इस बजट का विरोध करना ही पड़ेगा क्योंकि इस बजट में किसानों के नाम पर कोठ पैसा खर्च करने की योजना नहीं बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एक हरियाणा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया गया है लेकिन यह बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बाढ़ आमन्त्रण बोर्ड बन गया है। स्पीकर सर, आप तो स्वयं बाढ़ के भुक्तभोगी रहे हैं। एक तरफ तो बारिश पड़ रही थी, सभी नदियां नालें पानी से भरे हुए चल रहे थे ऐसी हालत में

सरकारी अधिकारियों को चाहिए तो यह था कि पानी के गेटस बन्द करके पानी को रोका जाता लेकिन सरकारी अधिकारियों ने गेटस को खोलकर नदियों में और अधिक पानी छोड़ा जिससे कि बाढ़ ने भयंकर रूप लिया। नहरें बन्द करने की बजाए बाढ़ में एडीशन करने के लिए अधिक पानी उनमें छोड़ा गया। इस प्रकार बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने बाढ़ में एडीशन करने के लिए अधिक पानी उन में छोड़ा गया। इस प्रकार बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने बाढ़ आमन्त्रण बोर्ड का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाउसिज बनाने की बात कही गई। ग्रीन हाउसिज बनाने पर जो पैसा खर्च किया जाना है अगर वह हरियाणा प्रदेश के किसान ओर मजदूर वर्ग के लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाने के किसी काम पर खर्च किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि लोग रोटी तक के लिए तरस रहे हैं इसलिए उनको रोटी देने का प्रयास किया जाना चाहिए था। 4.43 करोड़ रूपए का प्रावधान इस कार्य के लीए रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ग्रीम हाउसिज बनाने की बजाए इस पैसे से गरीब हाउसिज बनाए जाते तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय साथी राम बिलास जी शर्मा से मैं एक बात कहूंगा वे कह रहे थे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर बतियों पर टैक्स में कमी की गई है। लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है उसका उदाहरण भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। धर्म के नाम पर और देवी देवताओं के नाम पर हरियाणा में कितनी लॉटरीज आत बिल रही हैं इसका थोड़ा सा



ब्यौरा में हाउस में रखना चाहूंगा हरी ओम 55 रूपये की लॉटरी है जो कि 10.15 बजे खुलती है, महाबली 22 रूपये की 11.00 बजे, जब विश्णु मार्निंग 11.30 बजे, जय विश्णु आफरटरनून 2.15 बजे, महालक्ष्मी 1.00 बजे, महालक्ष्मी इवनिंग 3.30 बजे महालक्ष्मी गोल्ड 4.15, श्री गणेश 3.00 बजे, हरि ओम, श्री गणेश डबल डिजिट 1.30, हरि ओम डबल डिजिट 12.30 बजे और महालक्ष्मी डबल डिजिट 4.55 बजे कुल 12 लाटरीज हर रोज खुलती हैं। ये सभी लाटरीज देवी देवताओं के नाम पर चला कर उनके नाम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** यह लॉटरीज शुरू किसने की यह भी बता दीजिए?

**श्री रामपाल माजरा:** स्पीकर साहब, चौ. भजन लाल जी के राज में 6 लॉटरीज प्रतिदिन निकलती थीं लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद इन लॉटरियों की संख्या 6 से बढ़ कर 12 हर रोज की हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इस लॉटरी के बारे में मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि इस लॉटरी से हरियाणा प्रदेश की जनता से धोखा किया जाता है। जय दुर्गे के नाम से एक करोड़ रूपये के ईनाम की लॉटरी निकलती है जिसके नम्बर 0000000 से 9999999 तक होते हैं परन्तु वह लॉटरी की टिकटें 56 लाख के लगभग छापते हैं और फस्ट ईनाम की टिकट निकाली ही नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लाटरी खरीदने वालों से धोखा करके उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है।

हरियाणा लॉटरीज की जो टिकट छापी जाती हैं वह भी हरियाणा प्रदेश की प्रैस से न छपवा कर सरकार के किसी मन्जूरे नजर से छपवा ली जाती हैं और यहां तक कि उसक लिए टैण्डर तक भी कॉल नहीं किए जाते हैं। वैसे ये टिकटें गवर्नमेंट प्रैस में छपवाई जानी चाहिए। इस लाटरी की वजह से हरियाणा की जनता का विनाश हो रहा है इसलिए इनकानाम हरियाणा नाशम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में चन्द तथ्य उजागर करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश के इकनामिक सर्वे का जिक्र करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 232 डिस्पैसरीज पिछले काफी समय से चली आ रही हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितने हॉस्पिटल्ज की संख्या थी उतनी ही आज भी है। कहीं पर बिल्डिंग नहीं है तो कहीं पर बिल्डिंग खस्ता हालत में है। कहीं हैल्थ सैन्टर के पास बिल्डिंग नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है। मैं आपसे राजौंद के बारे में जिक्र करूंगा वहां पर जो पोस्टें मंजूर हैं उसमें से वरिष्ठ अधिकारी की एक पोस्ट मंजूर की गई है और वहीं खाली पड़ी है। चिकित्सा अधिकारी की आठ पोस्टें मंजूर हैं और छः खाली पड़ी हैं। खण्ड विस्तार शिक्षक की एक सीट है ओर एक ही खाली पड़ी है, कम्प्यूटर की एक सीट है और एक ही खाली पड़ी है। इसी प्रकार से कहीं पर भी दवाई नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, 3 साल में केवल 20 बैडज बढ़े हैं। यह सब हरियाणा का इकनौमिक सर्वे बता रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की तरक्की तो हरियाणा में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह लिस्ट पढ़ने लगू तो यह इसको सुन नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय,

जींद में नौ वर्षीय उशा बालिका को उठाया गया और उसके ऊपर जुर्म लगाया गया था कि उसने चोरी की है। उसके हाथ बांध कर इतना पीटा गया कि वह चल न सकी। जींद के हास्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन उसकी वहां से छुट्टी करवा दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ उस लड़की को पांच हजार रूपये कम्पनसेशन देने का फैसला दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कैथल के अतवार सिंह को इनके एक डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया कि उसको जला दिया जाए। अगर किसी को जलाया जाए या जलने के लिए मजबूर किया जाए तो एक ही बात है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बीड बडाला गांव के हरि कैलाश पुत्र चमेला राम किसान को का-आपरेटिव डिपार्टमेंट के एल.डी.बी. बैंक के अधिकारियों ने उठाया क्योंकि उससे कर्जा वसूल करना था। अध्यक्ष महोदय, उसको मार कर नहर में फेंक दिया गया। फिर भी ये अपने आपको किसानों की सरकार कहते हैं। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से किसानों के बारे में जिक्र कर देता हूं। हरियाणा प्रदेश में तूड़ी का भाव 130 रूपये प्रति क्विंटल है और यह आप भी जानते हैं, 140 रूपये प्रति क्विंटल लकड़ी बिकती है। खोई ओर बगास चालीस रूपये क्विंटल बिकती है जो पलवल में नैगोसिएशन हुआ है। हरियाणा प्रदेश में शीरा का नैगोसिएशन 230 रूपये पर क्विंटल हुआ है। आज हरियाणा में यह सरकार गन्ने का 62 रूपये पर-क्विंटल के हिसाब के भाव दे रही है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को तीन-तीन साल से पेमेंट नहीं हुई है। आज किसान ट्राली में जब गन्ना भर कर आता है और

कंडे के पास आकर खड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं कि तेरा गन्ने साफ नहीं है और दो क्विंटल गन्ना वहीं पर काट लेते हैं। कहीं पर लोडिंग और अन-लोडिंग के चार्जिज उनके पैसे से डिडक्ट किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गुड़ ओर खांडसारी के लाईसैंस दिए जाते हैं। अब की बार तो किसानों ने लाख लाख रूपये लगाए हैं और अब की बार तो उन्होंने लगाए है लेकिन अगले साल गन्ना कम हुआ तो यह एक प्रस्ताव पास करके भेज देंगे तथा इस प्रकार का हुक्म जारी कर देंगे कि कोई गन्ना पीड़ नहीं सकेगा, कोई क्रैशर नहीं लगेगा। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैंने बातें तो बहुत कहनी थीं और आज आपने मुझे बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे पांच मिनट और बोलने दिया जाए क्योंकि मैं नया मैम्बर भी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज बिजली बोर्ड का बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, एक सगुन है कि सवेरे घर में दूध बिलोया जाना चाहिए, रई और मधानी की आवाज आनी चाहिए और शाम का दीवा जरूर लगना चाहिए। परन्तु इनके राज में ये दोनों बातें दी खत्म हो गई हैं। सवेरे दूध बिलोया नहीं जाता है और शाम को दीया जलता नहीं है। आज इस तरह का असुगन हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज कितनी ही दरखासतें पड़ी हैं मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा। फिर भी किसानों को 6 महीने के अन्दर बिजली बिल भरने की सुविधा दे दी जानी चाहिए और हरियाणा प्रदेश के अन्दर की नहीं मैं आपको अपने हल्के की बात बताऊंगा। ट्रासफार्मर बदलने के लिए जिस प्रकार से पहले पटवारी

और कानूनगों की धड़ी बंधी हुई होती थी अनाज की उसी तरह से आज भी लाईन मैन की धड़ी बंधी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वह छमाही में दाने इक्ठे करते हैं, अनाज इक्ठठा करते हैं और लाईन मैन को दे देते हैं। तब वे जाकर जे.ई. को, फोरमैन को और ऐक्सियन को देते हैं फिर जाकर उसका ट्रांसफार्मर बदलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं आपको सड़कों के बारे में भी बताऊंगा। हरियाणा में सड़कें पहले से ही टूटी हुई हैं और ये कह देते हैं कि पैच वर्क कर दिया है। आज कोई भी पैच वर्क नहीं किया जाता है। खड्डे के अन्दर मिट्टी डाल दी जाती है और जब इनकी तरफ से गर्म हवा आती है तो वह उड़ जाती है। पांच छः दिनों के बाद वे खड्डे ज्यों के ज्यों रह जाते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने पैचिंग का काम कर दिया है। ये बिचुमिन का काम क्यों नहीं करते हैं, ये बिचुमिन का काम करें तो इन्हें पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूंगा। यह कहते हैं कि हम सबको एक नजर से देखते हैं। शर्मा जी ने केवल 22 स्कूल ही अपग्रेड किये हैं क्या इसके अलावा पूरे प्रदेश में और कोई स्कूल दर्जा बढ़ाने के काबिल नहीं था, क्या और कोई स्कूल नोर्म्ज पूरा नहीं करता था? इन्होंने झज्जर के 6 और महेन्द्रगढ़ के 9 स्कूल के दर्जे बढ़ाए हैं। इस प्रकार यह सबको बराबर की नजर से देखते हैं? अध्यक्ष महोदय, इनको पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को एक नजर से देखना चाहिए। जैसा कि मंत्री जी कहते हैं।

**श्री राम बिलास शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं माजरा साहब से कहना चाहता हूँ कि यह तो तीन चार महीने पहले वाली बात है लेकिन अब जब पूरे हरियाणा की लिस्ट इस बारे में आएगी तब हम और आप इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। (विघ्न)

**श्री रामपाल माजरा:** अध्यक्ष महोदय, जब महिलाएं शौचालय के लिए जाती हैं तो सड़कों पर ही बैठकर उनको लैटरिन करनी पड़ती है। जब कोई आदमी उधर आ जाता है तो उनको खड़े होना पड़ता है और बाद में वे फिर बैठ जाती हैं। अतः सरकार को चाहिए कि वह उनकी समस्याओं को देखते हुए कोई न कोई व्यवस्था इस बारे में करे ताकि उनको भी सहूलियत मिल सके। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि यह बजट इस सरकार के कफन में आखिरी कील का काम करेगा। इस बजट में कुछ नहीं है जबकि यह कह रहे हैं कि यह बजट हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है। यह हरियाणा की सरकार जो हविपा और भाजपा गठबन्धन की सरकार है हरियाणा को ग्रहण के रूप में ऐसे लग गई है जैसे सूरज और चांद को ग्रहण लगता है। धन्यवाद।

**श्री बलबीर सिंह (मेहम):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आज बजट पर चर्चा हो रही है। हमारे कई सम्मानित नेता भी इस बारे में बोले। उन्होंने कहा कि इस बजट में ऐसा दर्शाया गया है कि हरियाणा

में अगले साल कोई काम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बजट में तो सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है लेकिन जैसा इन्होंने पहले भी किया है कि जब भी इनका मन होगा ये बाद में टैक्स लगा देंगे क्योंकि यह तो इनके अपने हाथ में है। अध्यक्ष महोदय अगर कोई भी सड़कों के बनाने के बारे में या मुरम्मत करने बारे जिक्र हो तो मंत्री जी खड़े होकर कह देते हैं कि अगर पैसा होगा तब हम उनको बताएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस पैसे होने का समय तो निर्धारित होना चाहिए कि पैसा 6 महीने में, 9 महीने में या एक साल में आए। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा।

**श्री राम बिलास शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, चौ. बलबीर सिंह गवर्नर ऐड्रेस पर बोल रहे हैं या बजट पर।

**श्री धीरपाल सिंह:** सर, बलबीर सिंह बजट पर बोल रहे हैं ओर उन्होंने इस सरकार की मंशा बतायी है कि बजट सेशन के बाद टैक्स फिर लगेंगे।

**श्री अध्यक्ष:** ऐसा है कि आप उन माननीय नये विधायक को हतोत्साहित न करें बल्कि उनका उत्साह बढ़ाएं।

**श्री धीरपाल सिंह:** सर, हम तो उनका उत्साह ही बढ़ा रहे हैं।

**श्री बलवीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा जी बहुत विद्वान आदमी हैं। अभी जो इन्होंने खड़े होकर कहा है मैं उसका इनको जवाब दे देता हूँ। 3-4 महीने पहले झज्जर का चुनाव था तो ये मेहरबान हुए और रोहतक में 7-8 स्कूल अपग्रेड हुए। दस हल्के थे लेकिन इन्होंने सिर्फ एक हल्के में स्कूल अपग्रेड किए तो क्या बाकी के 9 हल्कों के स्कूल क्राइटेरिया पूरा नहीं करते थे। राम बिलास शर्मा जी आपको मैं विद्वान आदमी मानता हूँ कम से कम आप तो हरियाणा को एक नजर से देखे। अध्यक्ष महोदय अब मैं कुछ नहरों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। खाद, बीज और दवाई जमींदार को मिल जाए, बस हमारा तो यही बजट है। मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के समय वायदा किया था कि टेल तक पानी पहुंचाएंगे, हर टेल पर पूरा पानी देंगे लेकिन हमारे रोहतक का पानी काटकर ले गए। मोगे भीड़े कर दिए और पानी भिवानी ले गए। (विघ्न) दलाल साहब, मैं एक बात और कहूँ। झूठी बात तो मैं कहता नहीं। पानी हमारा नहीं काटा गया हो तो जो मर्जी कह दियो मैं सोमवार को आके बता दूँगा कि कितने क्यूसिक पानी काटा है और कितनी तारीख को काटा है।

**श्री अध्यक्ष:** मेरी आप सभी साहिबान से प्रार्थना है कि जब तक बलवीर सिंह जी बोलें, तब तक कोई बीच में न बोले।

**13.00 बजे**



**श्री बलबीर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक भोले बच्चे की इमदाद की। जब पानी काटकर ले गए तो मेहम हल्के के कई लोग कहने लगे कि मोगे भीड़े कर दिए और पानी ले गये तो मैंने कहा कि जब पानी आबै तो एक रापड़ा (कूश) होता है उसने मोगे में मारियो और पानी खोल के ले लियो, जब पुलिस आवैगी तो मन्ने बुला लियो। तीसरा मेरा गन्ने का सवाल है जब से अपना हरियाणा प्रदेश अलग हुआ है उस समय से लेकर आज तक जो भी सरकार आइ हैं किसी सरकार ने गन्ने का इतना भाड़ा किसान पर नहीं डाला जितना आज की हविपा-भाजपा की सरकार ने भाड़ा डाला है। यह किसान के लिए बहुत दुखदायक बात है। (विध्न) पिछली सरकार की भी कहूंगा माड़ी शान्ति करो। अब मैं बिजली के बारे में कहूंगा। चुनाव के समय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि 24 घंटे बिजली दूंगा। मुख्य मंत्री जी, मंत्रीगण और सत्तापक्ष के सम्मानीत सदस्य जब कुर्सी पर बैठते हैं तो यह एक ऐसी कुर्सी है कि इस बैठ कर आंख मिच जाए, आदमी भूल जाए। अगर यही हालत रही तो साल छ महीने में जब मंत्री या विधायक अपने हल्केयां में जाएंगे तो लोग घुसन कोनी देंगे। पिछली सरकार अगर ठीक काम कर देती तो आप ने नहीं आना पड़ता पिछली सरकार का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। बाढ़ राहत के लिए जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया था यह सारा पिछली सरकार के अफसरों, मंत्रियों और उनके चहेते लोगों की जेब में चला गया जबकि मेहम में सबसे ज्यादा बाढ़ थी और आज भी पानी खड़ा हुआ है जबकि मुख्यमंत्री

जी ने कहा था कि 31 दिसम्बर तक पानी निकाल दिया जायेगा और इस सरकार ने तो पैसा जमा ही नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह प्रजातंत्र है जब इलैक्शन का टाईम आता है तो चुने जाने वाले प्रतिनिधि गांव के आम लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं और उनके पैरों में भी पड़ते हैं लेकिन जब चुनकर यहां बैठ जाते हैं तो गांव के लोगों से इनको बास आनी शुरू हो जाती है। यह प्रजातन्त्र के खिलाफ है क्योंकि प्रजातंत्र में सबको बराबर की नजर से देखा जाता है। (घंटी) स्पीकर साहब, घंटी ना बजाई ये मैं तो बोलबाला बैठा था।

**श्री अध्यक्ष:** आप जल्दी खत्म कीजिए।

**श्री बलबीर सिंह:** हरियाणा सरकार के विकलांगों को पेंशन देने की जो बात की है उसमें यह नियम बना रखा है कि विकलांग आदमी हर साल अपना मैडिकल करवायेगा। मैं यहां पर सभी माननीय मंत्रियों से, सभी सदस्यों से और माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विकलांग आदमी के लिए एक परमानेंट नियम बनाया जाये कि जो भी विकलांग है उनका दोबारा मैडिकल नहीं होगा क्योंकि विकलांगों को एक दूसरी जगह डॉक्टरी परीक्षण के लिए जाना होता है उसमें बड़ी असावधानी होती है। अब बात रही बुढ़ापा पेंशन की। बुढ़ापा पेंशन चौ. देवी लाल ने लागू की थी। उस समय चौ. देवी लाल ने जब बुढ़ापा पेंशन की। बुढ़ापा पेंशन चौ. देवी लाल ने लागू की थी। उस समय चौ. देवी लाल ने जब बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी तो कोई

शर्त नहीं थी, न जमीन की और न सर्विस में लड़कों की (घंटी) पांच मिनट और दीजिए। चौ. देवी लाल ने तो मान-सम्मान देने के लिए हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी लेकिन चौ. भजन लाल जी की सरकार ने यह नियम बना दिया कि जिस आदमी के पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिसके दो लड़के सर्विस करते हैं उसकी बुढ़ापा पेंशन काट दो जिसके कारण काफी लोगों की पेंशन कट गई। फिर चुनाव नजदीक आ गए और सदन ने नेता चौ. बंसी लाल जी ने वायदा किया कि 60 साल के हर नागरिक को पेंशन देंगे और वह पेंशन भी लाईन में खड़े होकर के नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि डाक के द्वारा घर भेजी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब महीने पहले यह काम इस सरकार ने शुरू किया। लेकिन सभी गांवों में यह कार्य पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है और सेशन में बैठे हुए यह प्रचार करते हैं कि सब जगहों पर पेंशन बन गई अथवा लागू है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अगर कोई काम करो तो तसल्ली से करो, उससे फायदा होगा। 36 बिराड़रियों के गरीब आदमियों की सेवा करो तो भला होगा। मेरी तो हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी):** अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर चल रही चर्चा में बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार सत्ता में आने के बाद इसका यह पहला बजट है जो कि इस सदन में पेश किया गया। इस बजट को अगर किसान विरोधी,

मजदूर—विरोधी, हरियाणा की समस्त जनता का विरोधी बजट कहा जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** ये कह रहे हैं कि एक 'विरोधी' शब्द और जोड़ दो।

**श्री जय सिंह राणा:** अध्यक्ष महोदय, उसके जो नतीजे हैं उनको जरूर जोड़ेंगे। स्पीकर सर, इस गठबंधन सरकार के बनने से पहले नेताओं ने जनता से जो वायदे किए थे, इस बजट से यह लगता है कि आज वे उस वायदों की पूरी तरह से भूल चुके हैं क्योंकि सरकार ने सबसे पहला वायदा शराबबंदी का किया था लेकिन इस प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाना जा रहा है, जो मैं समझता हूँ, अपराधी किस्म के लोग हैं और पूरी तरह से इस नाजायज धंधे में जुटे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे गांव के पास सांभली गांव में जहरीली शराब जो कि कुछ लोग अपने घर में बनाया करते थे, के पीने से 8 लोगों की मृत्यु है गई, जिसका जिक्र पहले भी इस महान सदन में हो चुका है। उन शराब का धंधा करने वाले लोगों ने जनता के सामने इस बात को कबूल किया कि हम एस.पी. करनाल को इस धंधे को चलाने के लिए 60 हजार रुपये प्रति माह देते हैं। इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परन्तु सरकार ने उस विशय में कोई कार्यवाही नहीं की, तथा कुछ लोगों के खिलाफ ही सिर्फ दिखावे के रूप में कार्रवाई की गई है। लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं

कि इस कार्रवाई से इन लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। स्पीकर साहब, यहीं तक नहीं, आज शराब हरियाणा के हर शहर में हर गांव में हर डेरे में और हर ढाणी में उपलब्ध है। जिसको बंद करने के लिए सरकार ने भरसक प्रयत्न किए लेकिन शराब बंद नहीं हुई। हरियाणा की जनता को इस बात की बड़ी खुशी हुई थी कि इस प्रदेश से एक बहुत बड़ी बुराई का पतन होते जा रहा है। लेकिन शराब के बंद न होने से लोगों को उसका बड़ दुख है। जो भले लोग हैं जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं वे इस बात को महसूस करते हैं कि इस शराबबंदी से कुछ लोगों को शराब बेचने का मौका मिल गया और वे शराब बेचकर बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनको पैसा कमाने का अवसर मिल गया। वे लोग ऐसा करने के सिवाय प्रदेश को परेशानी में डालने के और कुछ नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि शराबबंदी लागू करने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए। शराबबंदी के लिए सरकार गम्भीरता से कदम उठाए और कठोर से कठोर कार्यवाही करे ताकि प्रदेश से यह बहुत हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाए। स्पीकर साहब, आज प्रदेश में अपराधीकरण बढ़ रहा है। मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण शामली गांव दिया था। स्पीकर साहब, शराब बेचने का धंधा करने वाले लोगों का जो आदमी विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ 302 का झूठा मुकदमा दर्ज करा कर उनको जेल में बंद करवा दिया। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी से बात भी की थी और इन्होंने खुद माना है कि उनके खिलाफ 302 का झूठा मुकदमा बना है। इस बारे में गृह मंत्री जी

और पुलिस के सीनियर ओफिसर से फरियाद की गई लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वे आदमी आज भी दफा 302 के तहत जेल में बंद है। यह अच्छी बात नहीं है।

**पशु पालन मंत्री (श्री हरमिन्द्र सिंह):** स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य दफा 302 की बात कर रहे हैं। जब इनका राज था उस वक्त फतेहाबाद और आदमपुर मंडी में जो शराब के ठेके थे उन ठेकों की शराब वहां के हर गांव की करियाने की दुकान पर बिकनी थी। उन दिनों वह शराब कौन बिकवाता था। उन दिनों इनकी पार्टी के लोग शराब की जीपें भर-भर कर गांव गांव में बेचते थे। वह शराबबंदी की बात कर रहे हैं जिनकी जिनकी पार्टी के आदमी के घर से शराब बरामद हुई है। आपने सरकार को शराबबंदी लागू करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलाया है लेकिन आप लोग खुद अपने घरों में शराब रखते हैं। छाज तो बोले छलनी क्या बोलेगी।

**श्री जय सिंह राणा:** स्पीकर साहब, डेरी तथा पशु पालन मंत्री जी जो बात कह रहे हैं मुझे तो पता नहीं इनके फतेहाबाद में पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। इस बारे में ये खुद ही जानते होंगे। स्पीकर साहब, मैं तथ्यों के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं कि आप शराब बंद नहीं कर सके हैं। कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो देश और प्रदेश का हर आदमी उस सरकार से आशाएं रखता है चाहे किसी आदमी ने उस सरकार को अपना वोट दिया है या नहीं दिया है उसके विकास के काम होंगे

लेकिन यह सरकार भेदभाव के आधार पर काम कर रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो उसकी एक परम्परा रही है कि अगर कहीं कोई इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए, जिसमें स्कूली बच्चों की या कई लोगों की जानें चली जाएं तो आर्थिक सहायता उस वक्त की सरकार द्वारा दी जाती रही है। जब महेन्द्रगढ़ के गांव ढोलान में किसी स्कूली बच्चे की मौत हो जाती है तो वहां पर तो सरकार की तरफ से 50 हजार रूपया मृतक के परिवार को दिया जाता है और जब नीलोखेड़ी में निगधू गांव के 17 बच्चों और एक अध्यापक की यानि 18 मौतें हो जाती हैं तो अगर फिर भी यह सरकार उस बारे में कुछ भी न सोचे, यह अच्छी बात नहीं है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वे गरीब किसानों और मजदूर परिवारों के बच्चे थे। ये गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों से यह आशा लगाये बैठे थे कि ये बच्चे बड़े होकर उनके परिवार का पालन-पोषण करेंगे और अपने मां-बाप की मदद करेंगे परन्तु वे उस दुर्घटना के शिकार हो गये। इसके बावजूद भी इस सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि उन परिवारों की हर प्रकार से सहायता की जाये। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब वह टैंकर व बच्चे नहर में गिरे तो प्रशासन ने उनके बचाव के लिए कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण उन बच्चों के घर वाले प्रशासन से खुश नहीं थे। इसके

लिए हाउस की एक कमेटी बनाई जाए जो लोगों से जाकर पूछे कि इस प्रशासन के लोगों का क्या रवैया रहा। मेरा मांग है कि प्रशासन की तरफ से कोई बचाव कार्य न करने के लिए सरकार कार्यवाही करे। प्रशासन के लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही भी न करे और मदद भी न करे, यह अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र के सरझाड़ी गांव में जहां की एक सरपंच दलित महिला है वहां पर 25 एकड़ पंचायत की जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया। उस सरपंच ने और पंचायत ने वहां के एस.डी.एम. और डी.सी. से उन प्रभावशाली लोगों से जमीन का कब्जा छुड़वाने के लिए बार-बार कहा और मिले लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उनको किसी प्रकार की मदद मिली। सरकार से मेरी मांग है कि उस गांव की पंचायत वाली जमीन पर जिन प्रभावशाली लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसको छुड़वाया जाये नहीं तो यह पंचायतों की जमीनों पर कब्जा करने की एक गलत रवायत कायम हो जायेगी और ऐसा होने से पंचायतों को जो आमदनी होती है वह भी समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही और न ही इस बजट में किसी प्रकार की कोई सहायता की जा रही है। जिस प्रकार से यह सरकार कार्य कर रही है उससे लोग समझते हैं कि यह सरकार उनकी कोई मदद नहीं करेगी। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जिले में भादसों में पिकाडली शूगर मिल है। उस शूगर मिल में किसानों को 62 रूपये प्रति



क्विंटल का भाव दिया जा रहा है। कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि किसानों को पूरा रेट दिया जाएगा। उस मिल न आज तक यह वायदा भी नहीं किया कि पहली किश्त कब दी जाएगी और दूसरी किश्त कब दी जाएगी?

**श्री बंसी लाल:** अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर हाउस को गुमराह कर रहे हैं। जिस वक्त बच्चों का टैंकर नदी में गिरा और बच्चों की व अध्यापक की मौत हुई तो हमारे शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा, मेहता जी व एक मंत्री और मौके पर पहुंचे थे। यह गलत बात कह कर हाउस को गुमराह कर रहे हैं कि प्रशासन की तरह से कोई कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह बताना चाहूंगा कि भादसों मिल के बारे में कल परसों ही डी.सी. के सामने बैठक कर मालिकों और किसानों का समझौता हुआ है। किसानों का जितना पैसा बकाया पड़ा हुआ है उसका भुगतान जनवरी या फरवरी तक कर दिया जाएगा। (विघ्न)

**श्री जय सिंह राणा:** स्पीकर सर, जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि निगधू की दुर्घटना के वक्त शशी पाल मेहता और राम बिलास शर्मा जी वहां गये थे, मैं उस बात से इन्कार नहीं करता ये वहां पर गये हैं लेकिन बात तो प्रभावित लोगों को सहायता दिये जाने की है। उन परिवारों की सहायता करना तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इन्सानियत के नाते यह फर्ज भी इनका बनता है कि वे उनकी सहायता करें। अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने की नीयत से मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हाउस में एक आश्वासन चाहता हूँ। (विधन) मुख्यमंत्री जी ने अभी हाउस में बताया है कि मिल के मालिकों और किसानों के बीच डी.सी. की मौजूदगी में समझौता हुआ है। क्योंकि यह फैसला डी.सी० की मौजूदगी में हुआ है इसलिए इस फैसले में सरकार की इन्वाल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से हाउस में एक आश्वासन चाहता हूँ कि पिकाडली मिल, भादसों किसान को गन्ने का निर्धारित रेट देगी। इससे ज्यादा मैं मुख्य मंत्री से और कुछ नहीं चाहता साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी आश्वासन दें कि किसानों को उनका पैसा कब तक मिल जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता तो स्पीकर साहब, हम यह समझेंगे कि यह स्पष्ट है कि ये फ़ैक्टरी के उद्योगपतियों से मिले हुए हैं।

**श्री बंसी लाल:** अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि यह काम तो इनका हुआ करता था, हमारा यह काम नहीं है।

**उद्योग मंत्री (श्री शशि पाल मेहता):** अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने जो यह कहा है कि निगधू दुर्घटना के समय हादसे के स्थान पर उस वक्त कोई नहीं पहुंचा तो मैं उनकी जानकारी के लिए हाउस में यह बताना चाहूंगा कि हादसा 8.50 बजे सुबह के समय हुआ था और हादसे के फौरन बाद एडमिनिस्ट्रेशन 9.15 बजे तक हादसे की जगह पहुंच चुका था और सुहब से लेकर शाम तक जब तक यह सारा काम खत्म नहीं हो

गया अधिकारी वहां पर मौजूद रहे पूरी डैड-बॉडीज मिलने तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें डी.सी., एस.डी.एम., एस.पी. वगैरा सारे अधिकारी हादसे की जगह पर मौजूद थे। जैसे ही इस हादसे के बारे एस.पी. श्री आई.डी. स्वामी को पता चला तो वे भी करीब 9.30 बजे तक वहां पर पहुंच गये थे और शाम तक वहीं रहे। मुझे भी जैसे ही पता चला मैं अगले दिन सुबह वहां पर पहुंचा, राम बिलास शर्मा जी भी पहुंचे और सारा दिन वहां रह कर लोगों की सारी बात को सुना। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक यह बात कही कि मिल वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं अगर मिले हुए होते हैं क्या यमुना नगर मिल एक दिन की स्ट्राईक के बाद अगले दिन चालू हो जाती। भादसों मिल का भी फैसला हो चुका है उनको बढ़ा हुआ रेट मिलेगा। एक दिन वहां स्ट्राईक रही थी दूसरे दिन मिल चालू हो गई थी।

**श्री बंसी लाल:** अध्यक्ष महोदय, वह मिल कांग्रेस के एक एम.पी. की है इन्हें चाहिए कि उसको भी घर बिठाकर समझाएं।

**श्री धीरपाल सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वह मिल किसी कांग्रेस संस्था की हो या न हो लेकिन मुख्यमंत्री जी जी से गुजारिश करता हूं कि किसान किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है। अगर किसान बर्बाद होगा तो उसका दायित्व वर्तमान सरकार पर आएगा।

**श्री बंसी लाल:** किसानों को बर्बाद तो इन्होंने किया है। शूगर के बारे में तो ये किसानों की बात करते हैं और गन्ना मिलों की हड़ताल करवाते हैं, अब ये किसानों की बात करते हैं। किसानों की गाड़ियों और ट्रैक्टर मिलों के आगे खड़ी हुई थी और ये हड़ताल करवा गये। अब ये किसानों के हमदर्द भी बनते हैं। (विधन)

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, उस हड़ताल में बी.जे.पी. का वाईस प्रैजिडेंट शामिल था और इनकी ही पार्टी का पदाधिकारी था जो कि रिकार्ड में भी दर्ज है। हड़ताल तो इन्होंने ही योजना बद्ध तरीके के बरवाई थी।

**श्री बंसी लाल:** अध्यक्ष महोदय, हड़ताल तो इन्होंने करवाई थी और ये खुद वहां पर गये थे। एक-एक मिल में ओम प्रकाश चौटाला खुद हड़ताल करवाने के लिए गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** राणा जी आप बैठ जाएं आपका समय खत्म हो गया है। अब वीरेन्द्र पाल जी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए। आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) Capt. Ajay Singh ji, you please take your seat. Otherwise I will have to name you. (Interruptions). Nothing is to be recorded. (Interruptions). I would request all the members to take their seats. Jai Singh ji, please you also take your seat. Otherwise I will have to name you. Surjewala ji, this is not court and you are not going to plead the case

here. Please take your seat. सुर्जेवाला जी आप हाईकोर्ट के वकील हैं और आपको तो जब स्पीकर साहब खड़े हों तो बैठ जाना चाहिए। (शोर)

**श्री राम बिलास शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, जाम्भा के नजदीक नदी में डूबने से 17 बच्चों की और एक अध्यापक की मृत्यु हो गयी थी। मैं खुद उन सब बच्चों के तथा अध्यापक के घर में गया था। जो वह अध्यापक जैल सिंह था वह एक हरिजन का बेटा था और उसके बाप ने उसको बुगी से मिट्टी डाल डालकर पढ़ाया था। उसने 3 बच्चों की जान बचाई। जब उसने दोबारा से नहर में बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई तो उसके बाद वह वापिस नहीं आया। हमने राष्ट्रीय सरकार को उसका नाम पुरस्कार के लिए भेजा है। इसके अलावा एक विधवा थी और उसके दो बच्चे थे वे दोनों उस हादसे में मारे गये हमने उसको भी आर्थिक सहायता देने की बात कही है। एक सुनील नाम का लड़का जो कि आठवीं में पढ़ता था, जिसने दो बच्चों की जान बचाई उसको भी हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

### **बैठक का समय बढ़ाना**

**कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):** अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के सभी सदस्यों की इस बात के लिए सहमति हो तो मैं

आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

**श्री ओम प्रकाश चौटाला:** अध्यक्ष महोदय, अभी तो बजट पर दो दिन और चर्चा होनी है इसलिए अब समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सभी सदस्यों को अपने-अपने घरों को भी जाना है।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

### **वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)**

**श्री जय सिंह राणा:** स्पीकर सर, जैसा कि राम बिलास जी ने बताया है कि वे उन गांवों में गए थे। मेहता ने भी कहा कि ये भी वहां पर गये थे तथा प्रशासन ने यह किया वह किया। प्रशासन ने वहां पर जो कुछ भी किया, उसके बारे में तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। मैंने तो इनके लिए एक कमेटी नियुक्त करने की बात कही थी। अगर सरकार को मेरी बात मंजूर हो तो वह सभी दलों के मੈंबर्ज की एक कमेटी बना दे। आपको एक या दो परिवारों की आर्थिक सहायता नहीं करनी चाहिए बल्कि उन सभी परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार को अवश्य ही इस बारे में सोचना चाहिए।

**डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत (बेरी):** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि

आपने मुझे पहली बार बोलने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, “निजाम मयखाने में इस कदर बिगड़ेगा साकी, कि शराब उनको मिलती है जिनको पीनी नहीं आती”। अध्यक्ष महोदय, जो समय बोलने के लिए विपक्ष के लोगों को मिलना चाहिए वह सत्ता पक्ष के मंत्रियों को दिया जाता है।

**श्री अध्यक्ष:** आपका मतलब क्या उनसे है जो आपको टाईम देते हैं?

**श्री कर्म सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, यह बौखलाए हुए हैं इसलिए शराब के नाम पर ये बार-बार सदन को गुमराह कर रहे हैं।

**डा. वीरेन्द्र सिंह अहलावत:** हमारे आदरणीय वित्त मंत्री ने जो बजट सदन में पेश किया है वह बहुत ही नीरस बजट है जिसको पढ़ने में और सुनने में किसी की भी रुचि नहीं है। इसमें किसी भी किस्म के विकास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट को सुनते-सुनते हमारे कुछ साथी तो सो तक गये थे। अध्यक्ष महोदय, जब बजट की नीरसता के बारे में उस दिन वित्त मंत्री जी से कहा गया तो उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था और कहा था कि मुझे तो यह पढ़ना ही पड़ेगा। उनको तो मात्र औपचारिकता ही पूरी करनी थी। इसके अलावा इस बजट में सिवाये शब्दों की हेरा फेरी के कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इस बजट में

15 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गयी है। जहां तक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात है वह पिछले साल हरियाणा प्रदेश के अंदर 5.2 प्रतिशत था और अब नवम्बर 1996 में यह 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गया है यानी ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। यह तो मैंने नवम्बर तक का ही बताया है और 31 मार्च, 1997 तक तो यह लगभग 18 प्रतिशत के आसपास तक जरूर पहुंच जाएगा अगर इसी रेट से बढ़ौतरी होती रही। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इस बजट में कुछ नहीं है यह कर रहित बजट नहीं है। कर तो सरकार ने सत्ता संभालते ही और असामयिक ही प्रदेश की जनता पर लाद दिए थे। यही कारण है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 13.4 प्रतिशत हो गया और इसके 31 मार्च तक लगभग दो गुना के करीब हो जाने की संभावना है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह बजट इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं है बल्कि इस प्रदेश की जनता के लिए एक तरह से दमनकारी है और इस तरह का जो दमनकारी बजट पेश किया गया है उसका मैं बहुत ही विरोध करता हूं। इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारी सरकार ने कहा है कि इस बजट के अन्दर क्योंकि पिछले दो सालों से हमारे प्रदेश के अन्दर बाढ़ की समस्या बनी हुई है और उस बाढ़ की समस्या के लिए बजट का प्रावधान किया है लेकिन मेरे हल्के के गोछी ओर शेरिया गांव के बीच आज भी लगभग 300 से 400 एकड़ जमीन के अन्दर पानी खड़ा है व शेरिया और लकड़ियां गांव के बीच भी लगभग 100 एकड़ जमीन



में पानी खड़ा है आज तक इस सरकार के द्वारा उस पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं किया गया। आगे अगर हो जाए तो अलग बात है लेकिन वर्स्ट अफैक्टेड एरिया में जब नजर नहीं पड़ी तो बाकी प्रदेश के लिए इसका क्या प्रावधान होगा? इसके बारे में सरकार ही बता सकती है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने यह स्वीकार किया है कि रोहतक और गुड़गांव जिले के अन्दर छह हजार एकड़ जमीन में आज भी रबी की फसल की बीजाई नहीं हो सकी है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के एक विशेष हिस्से के अंदर फसल की बीजाई न हो और सरकार स्वीकार करे कि बाढ़ के कारण किसान की फसल को क्षति पहुंची है फिर भी उसकी भरपाई के लिए मुआवजा न दे यह उस किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस सरकार को चाहिए कि चौ. देवी लाल जी की तर्ज पर चलते हुए जिस तरह पिछली सरकार के समय में भी बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ आई थी। उन्होंने भी मुआवजा देने का काम किया था और अब तो बहुत थोड़े से एरिया में बाढ़ आई थी इसके लिए तो इन्हें मुआवजा देना ही चाहिए। अब की बार जो बरसात हुई थी वह औसत बरसात से ज्यादा नहीं थी फिर भी कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी खड़ा है और सरकार आज भी उसक लिए कोई कदम नहीं उठा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वे जमीनें अब हमेशा पानी के नीचे रहेंगी। अगले वर्ष फिर बरसाल आ जाएगी और रबी की फसल की बीजाई नहीं हो पाएगी। इसलिए यह परमानेंट काम हो जाएगा, इसलिए सरकार को इस इलाके की ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे

हल्के के दूसरे गांव हैं जैसे बागपुर, वजीरपुर, ढराना, बीसन, मांगावास आदि ऐसे गांव है जो बरसात के दिनों में टापू की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा खातीवास, जहाजगढ, दुबलधन, एम.पी. माजरा आदि ऐसे गांव हैं जिनमें कहीं-कहीं अब भी पानी खड़ा है। सरकार को चाहिए कि इस समय जबकि बरसात के पानी का बीच में कोई व्यवधान नहीं है इस समय ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उस पानी की निकासी हो जाए। इसमें सरकार का पैसा तो लगेगा लेकिन किसान की फसल बर्बाद नहीं होगी। इसके बाद मैं गन्ने के विषय में कहना चाहूंगा। मेरे बेरी हल्के के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि रोहतक की शूगर मिल से जितना गन्ना बौंड हुआ है उससे ज्यादा बीजा गया था और अकेले बेरी हल्के के अन्दर 40-50 क्रशर चल रहे थे जिन पर उचित भाव न मिलने के बावजूद गन्ने का ढेर लगा रहता है यह हमारे हल्के की एक मजबूरी है क्योंकि थोड़ी सी बरसात के बाद पानी भर जाता है और कोई फसल ऐसी नहीं है कि इस पानी को रेजिस्ट कर सके। धान की बीजाई इसलिए नहीं हो पानी क्योंकि पानी नहीं होता। पीछे गन्ने की मिट्टी पलीत की गई। जो लोगों के ईट भट्ठे थे उनके अन्दर गन्ना जलाना पड़ा जिसका भाव 10-15 रूपये प्रति क्विंअल था। मेरे हल्के में जहां इतना गन्ना होता है और लोगों की डिमांड भी आ रही है कम से कम एक शूगर मिल की एकवेलेब्लिटी होनी ही चाहिए। अगर यह सरकार उसके बारे कुछ कदम उठायेगी तो कम से कम अगले सीजन तक काम शुरू किया जा सकता है। रही बात बुढापा पेंशन की। चौ. देवी लाल

की सरकार ने ओल्ड ऐज पेंशन को इसलिए लागू किया था कि चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या और किसी किस्म की पेंशन हो। उसके लिए मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम कंडीशन न की जाए। क्योंकि आज हमारे सदस्य जो एम.एल.ए. हैं जब से एम.एल.ए. नहीं रहते तो उनको भी पेंशन मिलती है, और जो सरकार के अधिकारी या कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनको भी पेंशन मिलती है ऐसा नहीं कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जरूरत नहीं होती। ओल्ड-ऐज पेंशन एक राईट है इसलिए इस पर किसी प्रकार की इकोनोमिक लिमिट फिक्स नहीं करनी चाहिए। इस ओल्ड-ऐज पेंशन को देने के लिए पास बुक बनवाई जाए क्योंकि जो गांवों में पेंशन बांटने वाले आते हैं उन पर सरकार का काफी खर्चा आता है तथा लोगों की भी शिकायतें आती हैं कि समय पर पेंशन नहीं मिलती। पास बुक जारी करने से लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। इसके अवाला मैं शराब बंदी कर बारे में कहना चाहता हूँ। शराब बंदी एक अहम मुद्दा है और इसके बारे में स्वयं सेवी संस्थाओं और प्रदेश के लोगों ने इस बारे कई बार मांग भी की थी। जब शराब बंदी की घोशणा की गई तो हमारी पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर इसके बारे पूरा सहयोग देने की बात कही थी और सभी विपक्ष के साथियों ने भी इसका समर्थन किया था आज सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आती रहती है कि विपक्षी पार्टी के सदस्य हमें शराबबंदी के मामले में सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के साथी ने

विपक्ष के किसी आदमी को पकड़ा हो या किसी के खिलाफ केस दर्ज कराया हो तो किसी एक का नाम लेकर बता दें (विधन) अगर किसी के खिलाफ शिकायत की हो। (विधन)

**श्री जगवीर सिंह मलिक:** गोहाना में चार लड़के शराबबंदी के केस में मैंने पकड़वाये हैं और उनके खिलाफ एफ. आई.आर. मैंने दर्ज करवायी है और एक अखबार में उन लड़कों को चौटाला साहब के साथ फोटो है। (विधन)

**लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव):** अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी शुरू होने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया जबकि हमारी सरकार के किसी विधायक या मंत्री ने किसी न किसी को नहीं पकड़वाया हो। मैंने खुद पटौदी में एक साधू को शराब की तरकरी करते पकड़वाया जोकि इनकी पार्टी का कार्यकर्ता भी था।

**मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा गहलावत):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री ओम प्रकाश चौटाला साहब को बताना चाहती हूँ कि रोहट हल्के में जितनी भी शराब पकड़वाई है, वह मैंने पकड़वाई है। वे शराब के उदाहरण हैं। (विधन) हमारे आदमी तो शराब बेचते ही नहीं हैं। ये इनकी पार्टी के आदमी हैं, जिन से शराब पकड़ी गई है। (शोर)

**डॉ. वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी के बारे में बार-बार कहा गया कि हमने 600 करोड़ रुपये का घाटा उठाकर भी यह

साहसिक कदम उठाया है। यह ठीक है कि शराबबंदी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके लिए हमने भी समर्थन दिया है। लेकिन माननीय डेरी विकास एवं पशुपालन मंत्री जी सदन में बैठे हैं, इन्होंने वक्तव्य दिया है कि शराबबंदी की जिन समाज सेवी संस्थाओं ने मांग की थी, उन समाज सेवी संस्थाओं ने इसमें सहयोग नहीं दिया है और शराबबंदी एक जन-आन्दोलन नहीं बन सकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार यह दावा करती है नहीं थकती है कि हमें 85 प्रतिशत सफलता शराबबंदी में मिली है। इसलिए बिना जन-आन्दोलन के वद बिना जन-सहयोग के यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। (विघ्न) मेरे पास कटिंग है।

**श्री हरमिंदर सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें जो इन समाज सेवी संस्थाओं से उम्मीद थी, उतनी इमदाद हमें नहीं मिली है। जिन्होंने एक्साइडट किया था कि शराबबंदी लागू करो, वे ही बैक-आउट कर गए हैं। वे विपक्ष के आदमी हैं तथा इस कार्य में साथ नहीं दे रहे हैं। हर जिले में इनके कार्यकर्ता ही यह काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पुराने समय से एक ऐसा बीच बोककर रखा है कि उसकी सेल्ज क्रिएट हो चुकी है। इसलिए इसको काबू में रखना भी हम एक बड़ी समस्या समण रहे हैं। (शोर)

**श्री रामबिलास शर्मा:** स्पीकर सर, सरदार हरमिंदर सिंह जी यह इसलिए जानते हैं कि ये चौटाला साहब की संगत में रहे हैं। इसलिए संगत का असर तो रहता ही है। (विघ्न)

**डा. बीरेन्द्र पाल अहलावत:** स्पीकर सर, इन्होंने खुद भी माना है। (विघ्न) इसके बाद सरकार एक ही बात को बार बार दोहराती है कि शराब सभी बुराईयों की जड़ थी। यह बात ठीक है कि इससे नैतिकता का ह्रास होता होगा और सारी बुराईयां शराब से पैदा होती होंगी। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उस सारी बुराईयों को खत्म करने से अगर नैतिकता बढ़ती है तो जो शराबबंदी से 600 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है, वह भी सस्ती बात है। लेकिन 600 करोड़ रुपया दूसरे प्रदेशों को जा रहा है और शराब पहले से ज्यादा बिक रही है। नैतिकता का ह्रास भी बढ़ा है क्योंकि कोई चोरी से शराब निकाल रहा है, कोई चोरी से शराब सप्लाई कर रहा है, कोई चोरी से शराब बेच रहा है तथा अगर कोई शराब के मामले में पकड़ा जाता है, तो कोई उसको छुडवा रहा है और कोई शराब की चोरी का झूठा ईल्जाम लगाकर किसी को जेल में भिजवा रहा है। यह सब सरकार की मानसिकता का उदाहरण है। (घंटी) स्पीकर सर, उनीदा गांव का सुखीराम नाम का 13 वर्ष का लड़का जिसे थानेदार थाने में पकड़कर ले आया, उसके ऊपर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाकर उसको डराकर सारा दिन उससे काम कराया और रात को उसके साथ कुकर्म किया। लेकिन जब उस लड़के ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गुहार की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हल्के के एम.एल.ए. (विघ्न)

**श्री मनीराम गोदारा:** अध्यक्ष महोदय, वह थानेदार गिरफ्तार हो गया है और जो उसके खिलाफ कार्यवाई की जानी जरूरी थी, वह सब हो गई है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** अध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे थानेदार चौटाला साहब के भर्ती किए हुए हैं। (हंसी)

**डा. बीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलने के लिए पांच मिनट ही मिल हैं। मेरे टाइम के बीच में दूसरे सदस्य बोलते रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** ठीक है आप कंकल्यूड कीजिए।

**डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सुखी राम को जिसकी लाईफ पर परमानेंटली एक धब्बा लग गया है जिसको सारी उम्र शर्म से सिर झुका कर जीना पड़ेगा, उसको सरकार की तरफ से कम से कम मुआवजे के दो लाख रुपये दिये जाने चाहिए। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के के अन्दर एक आदमी की कम्प्लेंट पर एक बीरपाल नाम का थानेदार रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया था।

**श्री अध्यक्ष:** वीरेन्द्र पाल जी आप कृपया बैठ जाएं अब सुरजेवाला जी बोलेंगे।

**डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आज पूरे हफ्ते में बोलने का टाईम दिया है और आज भी मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है।

**एक आवाज:** स्पीकर साहब, इनको दो तीन मिनट का टाईम और दे दें।

**डॉ वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बीरपाल नाम के थानेदार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। जब उसको न्यायिक हिरासत में लेने का आर्डर किया गया तो उसको बचाने के लिए आपकी पार्टी के कार्यकर्ता उसको होस्पिटल में लेकर गये ताकि उसको हिरासत में न लिया जाए। जब उसको कैजुअलटी में ले कर गए तो उसने अपनी छाती में दर्द बताया, जब चैक किया गया तो छाती में दर्द नहीं पाया गया फिर उसने अपने पेट में दर्द बताया, चैक करने पर उसके पेट में भी दर्द नहीं पाया गया। उसको कैजुअलटी में दाखिल नहीं किया गया। अगले दिन एक दूसरे डाक्टर के माध्यम से उसको ओ.पी.डी. के माध्यम से वार्ड के अन्दर दाखिल किया गया। कायदे के मुताबिक वह डाक्टर एम.बी. सिवाच की यूनिट में होना चाहिए था लेकिन दूसरे यूनिट में उसको दाखिल किया गया। जब डी.सी. ने उनको कहा कि आपने यह क्या किया तो उस डाक्टर सिवाच से प्रार्थना की कि आप इसको अपने यूनिट में ले लो तो डाक्टर सिवाच ने उसको अपने यूनिट में लेने से मना कर दिया तब उसको जेल जाना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह आपकी



सरकार की मानसिकता है। उस दिन विज साहब ने बताया था कि मानसिकता दो प्रकार की होती है। एक मानसिकता वह होती है कि अपराधी को पकड़ा ही न जाए और दूसरी मानसिकता यह है कि अगर अपराधी को पकड़ा भी जाए तो फिर उसको किसी न किस तरह बचाया जाए। इसके अलावा मैं व्हीट स्कैण्डल के बारे में कहना चाहूंगा। वह व्हीट स्कैण्डल मिस्टर आर.के. रंगा के किया था।

**Mr. Speaker:** Verender Pal Ji, please take your seat.

**डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात कह कर बैठ जाऊंगा। मिस्टर आर.के. रंगा अरंड लीव पर थे और उन्होंने अरंड लीव के फार्म पर एक ऐड्रेस दिया हुआ था जो दिल्ली में एक कांग्रेस के एम.पी. का ऐड्रेस है। फिर भी सरकार उसको पकड़ कर नहीं ला सकी। पता नहीं सरकार की क्या मन्जूरी थी। सरकार उसको पकड़ने में क्यों असमर्थ रही है। (घंटी)

**एक आवाज:** स्पीकर साहब इनको एक मिनट और दे दें।

**Mr. Speaker:** Now, this must be the last sentence.

**डा. वीरेन्द्र पाल अहलावत:** अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट का टाईम दे दें, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक बात मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं

के बारे में माननीय सदस्य रामपाल जी ने भी बताया था कि तीन साल में केवल 20 बैड बढ़ाए गए वह अलग बात है। लेकिन मैं रोहतक अस्पताल की बात कहना चाहूंगा। रोहतक अस्पताल के अन्दर जहां पर चिल्डर्न वार्ड है उसके कोरीडोर के अन्दर टी.बी. वार्ड बनाया हुआ है। जो नवजात शिशू पैदा होते हैं उनके वार्ड के अन्दर टी.बी. का वार्ड होना कितनी गलत बात है। वहां पर चिल्डर्न वार्ड की एक सीनियर लेडी डाक्टर थी उनको टी.बी. हो गई। चिल्ड्रन विभाग के हैड से बार बार अनुरोध किया गया कि उस वार्ड को अलग किया जाए लेकिन अभी तक वह वार्ड अलग नहीं किया गया है। इसके अलावा लार्डु सेविंग ड्रग्स जो कैजुअलटी वार्ड में होती हैं उनका तीन शिफ्टों के अन्दर तीन सी. एम.ओ.के पास एक हजार रूपए की कीमत तक का प्रति दिन कि हिसाब से प्रावधान किया हुआ था, वे सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहां के डायरेक्टर ने एसोसिएशन के नाम पर पांच लाख रूपए इक्ठे किए जिसके कारण उस एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि आप इतने पैसे कहां ले जाएंगे। वहां पर इस किस्म का व्यापार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बेरी और झज्जर के आसपास कम से कम करोड़ों रूपए के सरकारी दरखत काटे जाते हैं और बेचे जाते हैं। वहां पर इस किस्म का माफिया पैदा हो गया है। स्पीकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**बैठक का समय बढ़ाना**

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

**Mr. Speaker:** The time of the sitting is extended by 10 minutes.

### वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): स्पीकर साहब, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आबकारी, नहरी पानी और बिजली, जिनकी चर्चा वित्त मंत्री जी द्वारा की गई है, उन पर कुछ कहने से पहले 3-4 ऐसी मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त में बच्चों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में, हरिजन और बैकवर्ड भाईयों के बारे में जो फिगरज इस बजट में दी गई हैं, वह एक प्रकार से उनका उत्थान किया जाने वाला जो वायदा है, उसका मजाक है। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस का, बजट के पैरा 116 की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस पैरा में वित्त मंत्री जी ने कहा कि 11 लाख 77 हजार बैनिफिशरीज के लिए 1996-97 के दौरान 22.38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 9.54 लाख बच्चे हैं वे 2.23

लाख गर्भवती महिलाएं हैं। स्पीकर साहब, अगर आप इनको प्रति व्यक्ति लगाएं तो प्रति बच्चा और हर गर्भवती महिला पर यह सालाना खर्च है और यह राशि 190 रु. 05 पैसे एक साल में एक की आती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ कि हरियाणा के उन 11 लाख 77 हजार बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ये किस प्रकार से उत्थान करेंगे जिन पर एक साल में 190 रूपये 05 पैसे पर हैड खर्चने का सरकार का प्रावधान है? स्पीकर साहब उन गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ यह एक भद्दा मजाक है। जो फिगर्ज वित्त मंत्री जी ने पढ़ी हैं, यह उन पर आधारित है। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान बजट के पैरा 120 की तरफ दिलाना चाहूंगा जहां हरिजन और पिछले वर्गों के उत्थान की बात सरकार द्वारा की गई है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) इसी प्रकार से सरकार द्वारा यहां पर जो बजट में प्रावधान किया गया है वह दर्शाता है कि सरकार की कोई कमिटेमेंट हरिजन या बैकवर्ड वर्गों के लिए नहीं है। परन्तु यह, उनके साथ एक भद्दा मजाक है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा बजट के पैरा 120 पेज 24 की तरफ जिसमें यह कहा गया है कि

“For the economic upliftment of Scheduled Castes, during 1997-98, Haryana Harijan Kalyan Nigam plans to assist 14500 families with an outlay of Rs. 35-79 crore.”

**14.00 बजे**

डिप्टी स्पीकर साहब, 35.79 करोड़ रुपये हरिजन कल्याण निगम के लिए हैं। जिनसे यह सरकार 14500 हरिजन परिवारों की मदद करेगी। स्पीकर साहब, अगर इसको देखा जाए तो प्रत्येक परिवार के यह 2468 रुपये 27 पैसे हिस्से आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या 2468 रुपये 27 पैसे प्रति परिवार की मदद करके किसी हरिजन परिवार के उत्थान की बात यह कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो मंत्री जी इस बात का विश्वास दिला दे कि इतनी राशि इस समस्या का ठीक समाधान है। क्या इस राशि में कम से कम 100 प्रतिशत राशि की बढ़ौतरी बारे सरकार कोई विचार करेगी?

**श्री कर्ण सिंह दलाल:** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वह गलत है। जहां तक हरियाणा प्रदेश में हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की भलाई का सवाल है, तो जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं कुछ किया। उपाध्यक्ष महोदय, चौ. धीरपाल सिंह जी हाउस में बैठे हुए हैं उन्हें भली प्रकार से इस बात का पता है कि किस प्रकार का कल्याण कांग्रेस के राज में हुआ करता था। हरियाणा के हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का नौकरियों पर जो हक हुआ करता था ये लोग उसको कैसे पूरा किया करते थे, वह भी मैं हाउस में बता देता हूँ। हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की

नौकरियों में बैकलॉग छोड़ कर उनके अगेंस्ट चौ. भजन लाल जी द्वारा हिन्दुस्तान भर से बिश्नोइयों को ला कर लगाया गया था। (विध्न) यह रिकार्ड की बात है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, आज ये ट्रेजरी बेंचिज पर बैठे हुए हैं इसलिए सरकार की तरफ से इन्होंने जवाब देना है। आज चौ. बंसी लाल जी मुख्यमंत्री हैं और सरकार ने जो कुछ बजट में प्रावधान किया है मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। मैं कोई फिगर अपने पास से तो बनाकर नहीं लाया। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं एक अच्छे शिक्षाविद रहे हैं। जहां तक हरिजनों के कल्याण की बात का सम्बन्ध है, यह तो सीधा सा मैथेमैटिक का सवाल है इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है केवल तकसीम करने की बात है, ये करके देख लें। प्रत्येक परिवार के हिस्से में 2468.27 पैसे आते हैं, क्या इतनी राशि से किसी हरिजन परिवार का कल्याण हो सकता है (विध्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** लास्टर ईयर क्या फिगर थी।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का रिकार्ड निकलवा कर देख लें वैसे पिछली सरकार के वक्त में मैं इस सदन का सदस्य नहीं था और आप भी इस सदन के सदस्य नहीं थे। पिछली सरकार के वक्त क्या फिगर थी यह मुझे मालूम नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष:** अब पिछला रिकार्ड ला कर देख लें कि कितना अन्तर है।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए की अगर सरकार ने प्रावधान कम रखा है और उस मद में और अधिक पैसे की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रावधान और अधिक किया जा सकता है। वर्तमान बजट सरकार के आने वाले वर्ष की रूपरेखा का दिशानिर्देश होता है हरियाणा की जनता के लिए नये वर्ष के लिए बनाए गए कार्यक्रम की रूपरेखा है। जनता के कल्याण के लिए अधिक राशि की मांग न की जाए यह तो सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती और न ही राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा हो सकती है।

**श्री उपाध्यक्ष:** जनता को पता लगना चाहिए कि पिछली सरकार के वक्त में कितना प्रावधान था और अब कितना अन्तर उसमें हुआ है यह फिगर भी क्लीयर होनी चाहिए, अब कितना प्रावधान है यह भी पता लगना चाहिए।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, पहले चाहे जो भी फिगर रही हो। आज फिगर 1996-97 की डिस्कस नहीं हो रही है। आज तो वर्ष 1997-98 के बजट पर चर्चा हो रही है आज तो वही फिगर डिस्कस होनी चाहिए जो कि वर्ष 1997-98 के बजट में परपोज किए गए हैं। जो मैं कोट कर रहा हूँ वह बजट के अन्दर लिखा है और उसमें जो परपोज किया है वह

आज की वर्तमान सरकार ने किया है राशि का प्रावधान सरकार ने किया है ।

**श्री जगन नाथ:** हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के बारे में अभी इनकी पार्टी के श्री बीरेन्द्र सिंह थोड़ी देर पहले बोल रहे थे \*\*\*\*\* ।

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, न तो उन्होंने ऐसा कहा है और न ही उनकी ऐसी कोई मन्शा ही थी ।

**श्री जगन नाथ:** इन दोनों के गांव नजदीक ही पड़ते हैं और इन दोनों की मैटेलिटी भी एक जैसी है इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ । (विघ्न)

**श्रीमती करतार देवी:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने भाई जगन नाथ जी से कहना चाहूंगी कि कम से कम वे इस प्रकार की बात खुद तो न कहें । (विघ्न) उन्होंने आपकी बिरादरी शब्द कहे थे । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द कहे हैं उन्हें कार्यवाही से निकाला जाए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है । (विघ्न)

**श्री उपाध्यक्ष:** इन्होंने जो बात कही है उसे रिकार्ड न किया जाए ।

**श्री जगन नाथ:** अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी ने हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का जितना भला किया है वह भी मैं आपको बता देता हूँ । पुलिस की भर्ती में 471 को कोटा



हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों का था, जो कि कम किया गया और उनकी जगह पर कौन-कौन लोग भर्ती किए गए, उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कुछ दिया होगा वे ले लिए। यह रिकार्ड की बात है (विघ्न)

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जगन नाथ जी मुझे से बहुत ही सीनियर हैं तजुर्बे में भी और उम्र में भी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे काफी छोटा हूँ ओर यह उम्मीद करता हूँ कि जब कहीं मुझे से कोई त्रुटि होगी तो वे मेरी सहायता करेंगे। मुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखना है। जो बात मैं कह रहा था उसका उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। सरकार द्वारा अगर हरिजनों अथवा बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं तो उनको बढ़ाने के एिल मैं उनके पक्ष की बात कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम उनका सहयोग मिलना चाहिए था क्योंकि मैं उनके हितों की बात कह रहा हूँ और वे मेरी बात की वकालत करेंगे। पैसों का प्रावधान कम किया गया है तथा 2 हजार 468 रूपये 27 पैसे में किसी हरिजन परिवार का भला नहीं हो सकता है अगर यह बात सत्य है और तथ्यों पर आधारित है तो मैं, अपने सीनियर मंत्री श्री जगन नाथ जी और सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों से तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों से यह उम्मीद करूंगा कि सोचे समझे ढंग से उन 27 प्रतिशत हरियाणा की बिरादरी की जिनको जरूरत है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यह देखा जाए यह नहीं होना चाहिए कि किसी की बात काट कर

एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश की जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको यह कहना चाहता था कि हरियाणा में हरिजन परिवारों की एस्टीमेटिड संख्या 10 लाख से ज्यादा है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने सिर्फ 14 हजार 5 सौ परिवारों के लिए वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है जो बजट वित्त मंत्री जी ने पढ़ा था। उपाध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए और हरियाणा की 27 प्रतिशत हरिजन आबादी के 10 लाख परिवार हों तो यह 1.45 प्रतिशत है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह हरिजन का डेढ़ प्रतिशत आबादी से भी कम है। तो क्या यह तथ्य मेरी बात को नहीं दर्शाता? मैं अपनी और अपने दल की तरफ से सरकार के ध्यान में यह बात लाता हूँ कि सरकार की कमिटीमेंट एस.सी. और बैकवर्ड क्लास को यह बजट नहीं दर्शाता और न ही यह तथ्यों पर आधारित है। स्पीकर साहब, एक और बहुत की महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आप जानते हैं और आप बड़े शिक्षाविद भी हैं, संविधान की धारा 15 और 16 में तीन कैटेगोरिज का संरक्षण क्रियेट किया गया है। वे हैं हरिजन, बैकवर्ड क्लास और नारी। उसमें यह कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों के अपवाद बनाकर इन वर्गों को बैनिफिट दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, 1997-98 का जो प्लान आउट ले है, वह इस बजट के मुताबिक 1575 करोड़ रुपये है। बजट में उसके साथ जो एस्टीमेट्स दिए गए हैं उनमें ये चर्चा की गई है कि 27.22 करोड़ रुपये की राशि हरिजन और बैकवर्ड क्लास की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक

उत्थान के लिए 1997-98 के लिए सरकार मुहैया करवाएगी। यह टोटल प्लान आउट ले की 1.72 प्रतिशत राशि है। एक तथ्य है कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या हरियाणा प्रान्त में लगभग 40 प्रतिशत है। 40 प्रतिशत लोगों के उत्थान के लिए टोटल प्लान आउट ले का 1.72 प्रतिशत यानि कि दो प्रतिशत राशि भी यह सरकार मुहैया नहीं करवा सकी। इस सरकार ने जो कमिटीमेंट हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लिए किया है यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। (घंटी) इसके अलावा इस सरकार ने 1996 से शराब बंदी करके एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

### **बैठक का समय बढ़ाया**

**श्री उपाध्यक्ष:** अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट और बढ़ा दिया जाए।

**आवाजें:** ठीक है जी।

**श्री उपाध्यक्ष:** सदन का समय पांच मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

### **वर्ष 1997-98 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)**

**श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हरियाणा में शराब बंदी करके शराब के ठेकेदारों को बहुत फायदा पहुंचाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना

चाहूंगा। चौ. बंसी लाल जी हविपा और भाजना गठबन्धन की सरकार के लीडर हैं, इन्होंने चुनाव से पहले हरियाणा की जनता से एक वादया किया था कि हम 27 अप्रैल 1996 को सत्ता में आएंगे और जिस दिन सत्ता में आएंगे उन दिन से ही पूर्ण शराब बंदी लागू करेंगे। इन्होंने शराब बन्दी 1 जुलाई 1996 से लागू की और इस तरह का इम्प्रेसन हरियाणा के लोगों को दिया कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में शराबबंदी का प्रावधान नहीं था तथा सरकार ने इनके लिए कुछ नये कानूनी कदम उठाए जिसके बाद ही शराबबंदी लागू की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह है कि शराब के उन ठेकेदारों से मिलकर, शराब के उन माफियाओं को तीन सौ करोड़ रूपये की शराब बेचने या मुनाफा कमाने का मौका इस पीरियड के दौरान इस सरकार ने दिया था। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 उन अमेंडमेंटिड फोरम में इस बात के लिए पूरा पूरा प्रावधान है कि शराबबंदी लागू की जा सके। मैं इस अधिनियम के एक दो प्रोविजन आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब आबकारी अधिनियम की सैक्शन 26 में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पर पाबन्दी लागू करने का सरकार को अख्तियार है। सैक्शन 24, सब कलाज चार में हर प्रकार के इनटोक्सीकैन्ट को बन्द करने का पूरा अख्तियार सरकार को है। सैक्शन 25 में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है। सैक्शन 28 में शराब ओर इनटोक्सीकैन्ट को नहीं बनाने का प्रावधान है। सैक्शन 17 में शराब को हरियाणा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है और न ही हरियाणा में लेकर आया जा सकता

है। Transportation of liquor is prohibited, if that is so, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि एक जुलाई, 1996 से शराबबंदी लागू करने का क्या औचित्य था क्या इसका औचित्य यह नहीं था कि शराब के जो भंडार हरियाणा में शराब के ठेकेदारों ने इकट्ठे कर रखे थे, को किसी भी प्रकार से बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बार बार कही जाती रही है कि हरियाणा में शराब बंदी से मुनाफा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस जिसके खिलाफ मौजूदा सरकार पिछले सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायी थी, ने अलग-अलग फिगर्ज इस बारे में दी हैं कि शराबबंदी के बाद पुलिस द्वारा पकड़े गये अगल अलग केसिज कितने हैं। मैं चंद फिगर्ज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। एक जुलाई, 1996 से 31 जनवरी, 1997 तक यानी सात महीनों में अंग्रेजी शराब आई.एम.एफ.एल. की बोतल को दो लाख 35 हजार पकड़ी गयीं, बीस हजार बीयर की बोतलें पकड़ीं गयीं, तीस हजार किलोग्राम से भी ज्यादा लाहन पकड़ी गयीं, 697 शराब की भट्ठी पकड़ी गयीं। इसी दौरान 31594 व्यक्तियों को पकड़ा गया है जिन पर 29174 मुकदमें दर्ज किए गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई रीजनेबल आदमी इन फिगर्ज को देखकर कह सकता है कि हरियाणा प्रान्त में शराबबंदी लागू है। आज भी हरियाणा प्रान्त में शराब का एक माफिया बनता जा रहा है और हजारों, सैंकड़ों बेरोजगार नौजवानों को क्रिमिनल बना दिया गया है। हरियाणा में तीन ट्रैजेडी नकली और गंदी

शराब पीने से हो चुकी हैं। दो अगस्त, 1996 को बूढाखेड़ा गांव में पचास आदमी शराब पीकर बीमार हो गए और प्रभुवाला उकलाना मंडी गांव में पांच आदमियों की मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार से पीपल गांव था जो कि नरवाना तहसील में पड़ता है, एक व्यक्ति की नाजायज तरीके से शराब पीकर मौत हो गयी। दस दिसम्बर, 1996 को शामली, करनाल में दस आदमी मारे गये और डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी और मेरे दल ने शराबबंदी की स्वागत किया था और कहा था कि असली मायनों में शराबबंदी लागू होनी चाहिए।

**Mr. Deputy Speaker:** Now the House stands adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17<sup>th</sup> March, 1997.

**\*14.15 hrs.**

(The Sabha then \*adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 17<sup>th</sup> March, 1997)